राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 241

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, गुरुवार, 8 फरवरी, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

देश के शैक्षणिक संस्थानों को डोनेशन दें उद्योगपति

>> 2

जागरण विशेष

बायो रिसोर्स सेंटर से श्रीअन्न संग प्राकृतिक कृषि

शिवहर : तीन वर्षों से बिहार में श्रीअन्न संग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के अभियान में जुटे जयकली कुंवर मेमोरियल ट्रस्ट ने कृषि विभाग की देखरेख में नवाचार शुरू किया है। (पेज-7)

संपादकीय

घातक असर वाला इजरायल-हमास संघर्ष : समूचे पश्चिम एशिया में लड़ाई फैलने से ईरान के युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का भी खतरा है। **शिवकांत शर्मा** का आलेख।

विकृत इतिहास लेखन के दुष्परिणाम : इस्लामी हमलावरों के रक्तरंजित इतिहास के बावजूद वामपंथी इतिहासकार हमेशा उनका महिमामंडन ही करते रहे। **हरेंद्र प्रताप** का दृष्टिकोण।

● पेज 8

विमर्श

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का प्रश्न : ईपीएफओ द्वारा दिए जा रहे न्यूनतम पेंशन को एक हजार रुपये से मासिक से बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। लिहाजा इस मामले को विश्लेषित कर रहे हैं, **डा. अश्विनी महाजन**।

प्राथमिकताएं और दाने भुनाने का आग्रह : हिमाचल प्रदेश में विधायक प्राथमिकता बैठक का दो दिवसीय वार्षिक कार्य हाल ही में संपन्न हुआ है। इसमें विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं सीएम को बताते हैं। इसे रेखांकित करती **नवनीत शर्मा** की डायरी। ● पेज-9

विश्वास News

चुनाव पूर्व खरगे के हार मान लेने का दावा फर्जी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज-13

दैनिक जागरण सप्तरंग

तकनीक की दुनिया का

एआइ टूल्स से बढ़ाएं कौशल

वाट्सएप मैसेजिंग को बनाएं सुरक्षित

● पेज-13

कांग्रेस आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग की जन्मजात विरोधी : प्रधानमंत्री

तंज कसा ▶ जिसकी वारंटी खत्म हो गई, वह मोदी की गारंटी पर उठा रहे सवाल

पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस आरक्षण विरोधी रही

नीलू रंजन, नई दिल्ली

- **पिछले 10 साल में ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के उत्थान के लिए किए गए काम गिनाए**
- **चुटकी ली- राजग को 400 सीटें मिलने का कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का 'आशीर्वाद' सिर माथे**

राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रेट्र

...ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा : मोदी ने बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लंबे भाषण पर भी कटाक्ष किया और कांग्रेस नेता पर निशाना साधने के लिए लोकप्रिय बालीवुड गीत 'ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा' की पंक्तियों का इस्तेमाल किया। पीएम बोले- ' खरगे ने राज्यसभा में काफी देर तक बात की और मैं सोच रहा था कि उन्हें इतनी देर तक बोलने का मौका कैसे मिला? फिर मुझे एहसास हुआ कि दो विशेष कमांडर वहां नहीं थे और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। मुझे लगता है कि खरगे ने वह गाना जरूर सुना होगा ' ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा...।'

कांग्रेस पर ये भी कहा

- उसने अपने युवराज को 'स्टार्ट-अप' बनाया लेकिन दुख की बात यह है कि वह 'नान-स्टार्टर' बनकर रह गए हैं
- कांग्रेस का सोच आउटडेटेड हो गया है, उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है।
- आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया। अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता क्यों नहीं बदली? ऐसे सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे।
- भारतीय संस्कारों को मानने वालों को रुढ़िवादी-संकीर्ण सोच का बताया। अपनी परंपरा को गाली देना कहां तक सही है?

मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। जाति जनगणना के वादे के साथ ओबीसी, दलित और आदिवासी को साधने में जुटी कांग्रेस और राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कहा- पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस आरक्षण की विरोधी रही है। उन्होंने नेहरू द्वारा उस समय मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र का हवाला दिया। पत्र में नेहरू ने लिखा था कि- ' मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और नौकरियों में आरक्षण को तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी काम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे।' केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों में ओबीसी, एससी व एसटी की नगण्य भागीदारी के राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इसके मूल में नेहरू का आरक्षण विरोधी सोच था। यदि उस समय इन वर्गों को आरक्षण का लाभ दे दिया जाता तो वे आज नौकरशाही में शीर्ष पदों पर जरूर होते। (**बाबा साहब नहीं होते तो एससी-एसटी को भी आरक्षण नहीं मिलता : पेज-3**)

(**मोदी 3.0 में रखी जाएगी विकसित भारत की मजबूत नींव : पेज-3**)

रालोद अध्यक्ष जयन्त की भी भाजपा के साथ डील पक्की

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली

▶ **लोकसभा की दो और राज्यसभा की मिल सकती है एक सीट**

जयन्त चौधरी को केंद्र सरकार में एक मंत्रिपद का भी मिला है प्रस्ताव

राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की समाजवादी पार्टी (सपा) से दूरियां बढ़ गई हैं। रालोद की नई दोस्ती भाजपा के साथ होने जा रही है। रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात आगे बढ़ चुकी है। शर्तें भी लगभग तय हैं। भाजपा ने रालोद को लोकसभा की दो सीटों के साथ राज्यसभा की एक सीट का प्रस्ताव दिया है। जयन्त लोकसभा की एक अतिरिक्त सीट के लिए अड़े हैं। सूत्रों का दावा है कि एक-दो दिनों में सब फाइनल होने के बाद घोषणा भी हो जाएगी।

लगातार दो लोकसभा चुनावों में शून्य पर आउट रालोद की भाजपा से चार सीटों की अपेक्षा थी, जो भाजपा को मंजूर नहीं है। इसीलिए बात का सिलसिला कुछ लंबा खिंच रहा है, किंतु रालोद से जुड़े सूत्र का कहना है कि आखिरी दौर की बातचीत में दोनों दलों के नेतृत्व सहमति की ओर बढ़ रहे हैं। भाजपा ने रालोद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की ऐसी दो सीटें देने का प्रस्ताव किया है, जो जाट बहुल हैं। बागपत मिलना तय हो गया है। दूसरी सीट बिजनौर या सहारनपुर हो सकती है। तीसरी सीट पर मामला अटका है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की रजामंदी हुई तो तीसरी सीट के रूप में संभल या अमरोहा में से कोई एक हो सकता है। भाजपा ने केंद्र की सत्ता में आने पर रालोद को एक कैबिनेट रैंक का मंत्रिपद भी देने का वादा किया है।

जयन्त ने भाजपा से सहारनपुर, बागपत, बिजनौर व मथुरा की अपेक्षा की थी। दलित-मुस्लिम समीकरण के लिए नगीना, संभल एवं अमरोहा में किसी एक की भी मांग की गई थी। बात आगे बढ़ी। किंतु भाजपा ने इन्कार किया तो जयन्त तीन पर आकर ठहर गए। भाजपा की तरफ से लोकसभा की दो एवं राज्यसभा की एक सीट की पेशकश कर बात को विराम दे दिया गया। एक दौर ऐसा भी आया जब लगा कि बात बिगड़ गई है, किंतु फिर दोनों तरफ के विश्वस्तों को लगाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बहुल दो लोकसभा सीटों के अलावा संभल और अमरोहा में किसी एक के लिए जोर लगा रहे जयन्त का तर्क है कि इन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, जहां रालोद का आधार है। अगर ये सीटें रालोद के हिस्से में आती हैं तो राजग की जीत पक्की हो जाएगी। (**पेज-4 भी देखें**)

पांडवों ने मांगे पांच गांव, हमने तो सिर्फ तीन स्थान : योगी

- **उत्तर प्रदेश के सीएम ने अयोध्या के बाद मथुरा-काशी का एजेंडा रखा सामने**
- **रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कहा, 'हमने वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया'**
- **अखिलेश पर साधा निशाना- 'उनकी पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथारिटी'**

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए पांच गांव मांगे थे, हमने तो सिर्फ तीन स्थानों (अयोध्या, मथुरा, काशी) की बात की। ये तीनों ईश्वर के अवतरण की धरती हैं, लेकिन इसमें भी राजनीतिक तड़के और वोट बैंक की प्रवृत्ति ने विवाद खड़ा कर दिया। योगी ने विधानसभा में बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत अयोध्या के साथ-साथ काशी व मथुरा का भी एजेंडा सामने रखा। योगी ने विपक्ष पर तंज कसा-'तब दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोंक के बराबर जगह नहीं दूंगा तो महाभारत होना ही था। वोट बैंक के लिए हमारी संस्कृति व आस्था को रौंदने वाले आक्रांताओं का महिमामंडन किया गया, जिसे अब देश स्वीकार नहीं करेगा।'

अयोध्या के साथ अन्याय हुआ : राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 110 मिनट के उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में रखा। अयोध्या सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। पांच हजार वर्ष पुरानी बात को याद करें तो भगवान कृष्ण ने केवल पांच ग्राम मांगे थे। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाई...'तो दे दो केवल पांच ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम।'

कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले...

योगी ने कहा, पहली बार देखने को मिला कि लोक आस्था के लिए भी बहुसंख्यक समाज को गिड़गिड़ाना पड़ा, लेकिन अब जब लोगों ने अयोध्या का उत्सव देखा तो नंदी बाबा (काशी) ने कहा कि हम क्यों इंतजार करें। उन्होंने रात में बैरिकेडिंग तुड़वा दी। अब हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। प्रसन्नता है कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया... जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई।' योगी ने कहा कि यह देश रामराज्य की अवधारणा को स्वीकार करेगा, समाजवाद को नहीं...। आज का समाजवाद बहुरूपिये की तरह हो गया है। कभी यह प्रजातांत्रिक, कभी लोकतांत्रिक तो कभी चच्चू (शिवपाल यादव) का प्रगतिशील समाजवाद हो जाता है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश पर प्रहार जारी रखा- 'इनकी पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथारिटी है। इसमें और कोई है या नहीं, मगर चच्चू (शिवपाल यादव) नहीं है। हाल ही में टिकट घोषित किए जिसमें परिवार के तीन सदस्यों के नाम थे, चच्चू का नाम क्यों नहीं था। अगर प्रभु राम को मानते, रामायण या महाभारत से सीखते तो चच्चू का अपमान नहीं करते।'

मुख्यमंत्री ने कहा-'दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को बंधक बनाने की कोशिश की-'उलटे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला...'यही तो हुआ था अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ। ये तीनों विशिष्ट स्थल हैं।'

आबकारी घोटाले में आप को दोहरा झटका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- **ईडी के सामने केजरीवाल के पेश नहीं होने को कोर्ट ने अपराध माना**
- **कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 17 फरवरी को पेश होने का दिया आदेश**

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फाइल

अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। उनके विरुद्ध प्रथमदृष्टया आइपीसी की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के तहत अपराध बनता है। **- दिव्या मल्होत्रा, एडिशनल मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट**

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी को बुधवार को दोहरा झटका लगा। ईडी के लगातार पांच समन के बाद भी पेश नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

एडिशनल मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समन के पालन में ईडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बाध्य थे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। भारतीय दंड संहिता की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के तहत उनके खिलाफ अपराध बनता है।

आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक पांच समन जारी किए थे। हर समन पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल उसके समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था। आरोप लगाया कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना व गिरफ्तार करना है। आखिर ईडी ने चार फरवरी को कोर्ट के समक्ष शिकायत की थी। बुधवार को कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्रथमदृष्टया धारा 174 के तहत अपराध बनता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं।

मानहानि मामले में केजरीवाल को 29 को पेश होने का आदेश पेज>>2

हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोपित को जमानत देने का आधार नहीं है। साथ ही, निचली अदालत को मामले पर तेजी से सुनवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पक्ष बेवजह स्थगन की मांग नहीं करेगा। संजय सिंह ने याचिका में तर्क दिया था कि वह तीन महीने से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ईडी ने दलील दी कि संजय सिंह आबकारी घोटाला से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने व उपयोग में शामिल थे।

पवार गुट हुआ अब राकांपा शरदचंद्र पवार

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) करार देने के बाद अब शरद पवार गुट को भी नया नाम दे दिया है। उसे फिलहाल 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार' के नाम से जाना जाएगा। शरद गुट अब इसी नाम से राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतर सकेगा। (**पेज-4**)

श्रीनगर में आतंकियों ने सिख युवक की गोली मारकर हत्या की

श्रीनगर : आतंकियों ने बुधवार शाम श्रीनगर शहर में एक सिख युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। दोनों पंजाब के अमृतसर के निवासी हैं और श्रीनगर में फेरी लगाकर शाल बेचने का काम करते थे। मौजूदा वर्ष में अन्य राज्य के किसी व्यक्ति की यह पहली टारगेट किलिंग है। (**पेज-6**)

उत्तराखंड ने रचा इतिहास, यूसीसी विधेयक पारित

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- **संविधान निर्माताओं के स्वप्न को धरातल पर उतारने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला प्रदेश**
- **विधेयक पर दो दिन 10 घंटे तक चली चर्चा, कांग्रेस ने आक्रामक विरोध से किया परहेज**

विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा का जवाब देते सीएम पुष्कर सिंह धामी। साभार सूचना विभाग

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। **-पुष्कर सिंह धामी, सीएम उत्तराखंड**

उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को इतिहास रच दिया। दो दिनों में लगभग 10 घंटे चली चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके साथ ही देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। हालांकि गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगाली शासन से लागू है। यह पारित विधेयक राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही कानून बन जाएगा। इसमें सभी धर्म-समुदायों की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति में समान अधिकार देते हुए सशक्त बनाया गया है। बहु विवाह और बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले विपक्षी दलों कांग्रेस व बसपा की ओर से विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत से गिर गया। चर्चा के दौरान सत्तापक्ष भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, लेकिन कांग्रेस ने आक्रामक होने के स्थान पर शांत रहने की रणनीति अपनाई। बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की पहल के कारण तीसरे दशक को महिला सशक्तीकरण के दशक के रूप में याद रखा जाएगा।

समान नागरिकता संहिता के रूप में बन रहा कानून किसी के विरुद्ध नहीं : धामी पेज>>5

बिहार के सीएम नीतीश बोले, अब इधर-उधर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे

नई दिल्ली : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट के बाद बुधवार को कहा, अब इधर-उधर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। राजद-कांग्रेस के महागठबंधन को छोड़कर बिहार में भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की पीएम मोदी एवं भाजपा नेताओं से यह पहली भेंट है। भाजपा के तीनों शीर्ष नेताओं से नीतीश की भेंट ऐसे समय हुई है, जब बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को सरकार को बहुमत साबित करना है। (**पेज-4**)

आरोप खारिज

वित्त मंत्री का दावा, संप्रग कार्यकाल की तुलना में कई गुना अधिक दी करों में हिस्सेदारी और अनुदान, राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया अलगाववादी सोच का आरोप, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

कर्नाटक का कोई बकाया नहीं, सीतारमण ने दिखाया आंकड़ों का आईना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार पर अनुदान और करों की हिस्सेदारी में भेदभाव का जो आरोप कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने लगाया है, उसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज कर दिया। इसे अलगाववादी राजनीतिक सोच से प्रेरित दुष्प्रचार बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार को आंकड़ों का आईना भी दिखाया। संप्रग कार्यकाल से राजग कार्यकाल की तुलना करते हुए उन्होंने दावा किया कि इन 10 वर्षों में कर्नाटक को कई गुना अधिक अनुदान और टैक्स में हिस्सेदारी के रूप में पैसा मिला है। केंद्र पर बकाया होने के आरोप को उन्होंने बिल्कुल झूठ बताया।

नई दिल्ली में कर्नाटक सरकार के प्रदर्शन के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त आयोगों की सिफारिशों और अन्य बिंदुओं पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग के पांच वर्षीय काल (2015-16 से 2019-20) में कर्नाटक को टैक्स में हिस्सेदारी के रूप में 1,51,309 करोड़ रुपये दिए गए। वहीं, वर्तमान 15वें वित्त आयोग के शुरुआती चार वर्षों में 1,29,854 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अंतरिम बजट में 44,485 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस तरह पांच वर्ष में कर्नाटक कुल 1,74,339 करोड़ रुपये प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि यह 14वें वित्त आयोग की तुलना में भी यह अधिक है, जबकि सरकार को कोविड के दौरान राजस्व का नुकसान हुआ। कर्नाटक सरकार के आरोपों का बिंदुवार खंडन करते हुए वित्त मंत्री ने प्रश्न उठाया कि भेदभाव का आरोप लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य सिद्दरमैया सरकार ने क्यों नजरअंदाज कर दिया? उन्होंने दावा किया कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर ही कर्नाटक को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,631 करोड़ रुपये दिए गए। केरल को भी इस मद में अनुदान दिया गया, जबकि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित बिहार को राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिला। ऐसे में राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप पूर्णतः निराधार हैं। इतना ही नहीं, 2014 से पहले रही केंद्र सरकारों के दौरान राज्यों की 81,470 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। कर्नाटक का 1996 से बकाया चल रहा था, उसका भुगतान करते हुए मोदी सरकार ने मार्च, 2022 में 2,671 करोड़ रुपये दिए। तुलनात्मक आंकड़ों के साथ कांग्रेस को आईना दिखाते हुए निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि कर्नाटक को 2004 से 2014 के बीच टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 81,795.19 करोड़ रुपये, अनुदान के रूप में 60,779.84 करोड़ रुपये मिले। वहीं, भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 में 10 जनवरी तक कर हिस्सेदारी के मद में 2,85,452 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में अनुदान के रूप में 2,08,832.02 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

नई दिल्ली में बुधवार को प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

कांग्रेस का आरोप गैरजिम्मेदाराना

भाजपा मुख्यालय में साझा प्रेसवार्ता करते हुए सांसद तेजस्वी सूर्या, प्रताप सिम्हा और उमेश जाधव ने भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के आरोपों को सिरे से नकारा। साथ ही इसे संविधान और राष्ट्र के विरुद्ध गैरजिम्मेदाराना बताया। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं कर पाने की वजह से राज्य सरकार ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रही है।

संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- **फर्जी पहचान पत्र के जरिये गृह मंत्रालय में घुसने की कर रहा था कोशिश**
- **आरोपित अयोध्या का रहने वाला, स्वयं को नीति आयोग में बताया था स्टेनो**

संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद अब नार्थ ब्लाक स्थित गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। सीआइएसएफ ने गत छह फरवरी को फर्जी पहचान पत्र के जरिये गृह मंत्रालय में घुसने की कोशिश करते एक युवक को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपित आदित्य प्रताप सिंह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अयोध्या का निवासी है। उसने गृह मंत्रालय के किसी परिचित के पहचान पत्र का रंगीन फोटो कापी करवा कर उस पर अपना फोटो चिपका कर पहचान पत्र बना लिया था। दोस्तों को दिखाने का लिए उसने फर्जी पहचान पत्र बनवाया था, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि वह गृह मंत्रालय में नौकरी करता है। छह फरवरी को दोपहर दो बजे गृह मंत्रालय में घुसते समय सीआइएसएफ कर्मियों ने उसका पहचान पत्र देखा और संदेह होने पर पकड़ लिया। पुलिस, स्पेशल सेल, आइबी, एनआइए व अन्य एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में उसने स्वयं को नीति आयोग में स्टेनो बताया था, लेकिन यह झूठ निकला। सूत्रों के मुताबिक, अभी तक की पूछताछ में कोई आतंकी एंगल का पता नहीं लगा है। पुलिस को शक है कि संभव है जालसाजी के इरादे से वह अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। वह 12वीं पास है। पुलिस उसके स्वजन से पूछताछ कर रही है। गत वर्ष 13 दिसंबर को दो युवक संसद भवन के अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे।

****

175 रहा बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ)। मध्यम श्रेणी में ही बना रहा प्रदूषण। हालांकि 12 इलाकों का एक्यूआइ 200 से ऊपर यानी 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 फरवरी, 2024

आज का मौसम

आसमान साफ रहेगा।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
8 फरवरी	21.0	07.0
9 फरवरी	23.0	07.0
नोएडा		
8 फरवरी	18.0	07.0
9 फरवरी	19.0	07.0
गुरुग्राम		
8 फरवरी	19.0	06.0
9 फरवरी	20.0	06.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

अमानतुल्लाह ने ईडी मामले में वापस ली याचिका

नई दिल्ली : दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली। आरोप है कि अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था। (जासं)

न्यूजक्लिक के एचआर प्रमुख की जमानत पर निर्णय सुरक्षित

नई दिल्ली: आतंकवादी एवं गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले में आरोपित न्यूजक्लिक के मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सरकारी गवाह बनने के आधार पर चक्रवर्ती ने जमानत की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि अगर चक्रवर्ती को राहत दी जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। (जासं)

मानहानि मामले में केजरीवाल को 29 को पेश होने का आदेश

प्रथम पृष्ठ से आगे

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सात फरवरी को व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने उन्हें 29 फरवरी को अदालत के समक्ष सामने पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला वर्ष 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को केजरीवाल के री-ट्वीट करने से जुड़ा है। इस री-ट्वीट पर केजरीवाल के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पेज 'आई सपोर्ट नरेन्द्र मोदी' के संस्थापक विकास सांकृत्यायन ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने केस रद करने की केजरीवाल की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अपमानजनक सामग्री को री-ट्वीट करना मानहानि के समान है।

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दिए भ्रामक बयान : उपराज्यपाल

कहा, सरकारी वकीलों की ओर से पेश झूठे तथ्य अदालत की अवमानना

कानून और वित्त मंत्री आतिशी ने आबकारी विभाग और सरकारी वकीलों के साथ एक बैठक बुलाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

वीके सक्सेना। फाइल

नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन को लेकर अधिकृत एवं अनधिकृत वार्डों की आधिकारिक सूची तैयार करने के संबंध में दिल्ली सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दिए गए बयानों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रामक और झूठ बताया है। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकारी वकीलों की ओर से पेश किए गए झूठे तथ्य अदालत की अवमानना के बराबर हैं।

उपराज्यपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है कि दिल्ली सरकार के वकील हाई कोर्ट में सितंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक यह कहते रहे कि समिति की रिपोर्ट को मंजूरी से संबंधित फाइल राजनिवास स्तर पर लंबित है। जबकि यह फाइल 16 जनवरी 2024 को पहली बार राजनिवास में आई। इससे पहले 18 अगस्त 2022 को भेजी गई फाइल समिति के गठन की मंजूरी देने के लिए थी, न कि समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देने के लिए थी। इन दोनों फाइलों को राजनिवास भेजे जाने के समय में करीब एक वर्ष पांच महीने का अंतर है। उपराज्यपाल ने हाई कोर्ट की ओर से 12 सितंबर 2022, 10 अगस्त 2023, 18 अगस्त 2023 और चार दिसंबर 2023 को पारित आदेशों का हवाला देते हुए सरकारी वकील अरुण पंवार और संतोष त्रिपाठी के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नाम पर झूठी बातें की गईं, जो अदालत की अवमानना के समान है।

उपराज्यपाल ने कहा कि यह मामला सरकार के उस पहलू को दर्शाता है, जिसमें राज्य सरकार के वकीलों ने उपराज्यपाल और उनके कार्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए हाई कोर्ट के समक्ष झूठे और भ्रामक बयान दिए। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास उपराज्यपाल के संवैधानिक कार्यालय को बदनाम करने के समान है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य सरकार अपने हलफनामे में पूरे तथ्य का खुलासा करे कि फाइल के प्रस्तुतीकरण में देरी के लिए राज्य सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के समक्ष तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने, अदालत की अवमानना करने और उपराज्यपाल के पद की गरिमा को कम करने के लिए सरकारी वकीलों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई लंबित रहने तक इन वकीलों को तत्काल प्रभाव से सरकार की ओर से कोर्ट में उपस्थित होने से रोका जाना चाहिए।

उधर, दिल्ली सरकार में कानून और वित्त मंत्री के रूप में आतिशी ने आबकारी विभाग और संबंधित सरकारी वकीलों के साथ एक बैठक बुलाई है। जिससे यह समझा जा सके कि फाइल की स्थिति के संबंध में हाई कोर्ट में गलत संचार क्यों और कैसे हुआ।

ईडी ने पंचनामे में यह तक नहीं लिखा कि छापेमारी किस मामले में की : आतिशी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, 16 घंटे ईडी विभव और रास सदस्य के आवास पर सिर्फ बैठी रही
- न तलाशी न ही पूछताछ, सिर्फ दो ईमेल अकाउंट के डाटा और तीन फोन लिए

प्रेस को संबोधित करतीं आतिशी। एएनआइ

आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां हुई ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद बुधवार को आप नेता एवं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि 16 घंटे तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव (पीएस) बिभव कुमार, राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता आदि के यहां छापेमारी की गई, लेकिन पंचनामे में ईडी ने यह तक नहीं बताया कि छापेमारी किस मामले में की गई। ईडी की टीम सिर्फ पीएस और राज्यसभा सदस्य के आवास पर बैठी रही, न तलाशी ली न ही कोई पूछताछ की।

आतिशी ने कहा कि ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री के पीएस के दो ईमेल अकाउंट का डाटा डाउनलोड किया और उनके परिवार के सदस्यों के तीन फोन लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने यह ऐतिहासिक पंचनामा बनाया है, जिसमें मामले का जिक्र ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ईडी पंचनामे में सभी बातों का जिक्र करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दर्शाता है कि ये छापेमारी केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए की गई थी। मोदी सरकार विपक्ष और आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर चलवाती है। ईडी का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, जो बयान दे। उन्होंने कहा कि मैं यह दावे के साथ कह रही हूं कि आबकारी नीति मामले में आरोपितों के बयान की सीसीटीवी रिकार्डिंग में आवाज को डिलीट किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो ईडी के अधिकारी सामने आएं और इस बारे में बयान दें।

ईडी के खिलाफ करेंगे कानूनी कार्रवाई : आप ने चुनावी कोष के तौर पर दिल्ली जल बोर्ड के कार्यों की निविदा जारी करने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा है कि आप को बदनाम करने के लिए ईडी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह भी सवाल उठाया कि ईडी आयुष्मान भारत और भारतमाला परियोजना घोटाले की जांच क्यों नहीं कर रही है।

एलएन अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए दी वर्ष 2027 की तिथि

उदय जगताप, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के प्रमुख अस्पतालों में शामिल लोक नायक अस्पताल ने सीटी स्कैन के लिए पहुंचे मरीज को तीन साल बाद की तिथि दी है। मामला पिछले महीने का है। मरीज को मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान से सीटी स्कैन के लिए भेजा गया था। यह हाल तब है, जब हाल ही में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। तीन करोड़ की आबादी पर मात्र छह सीटी स्कैन होने पर हैरानी जताई थी।

दांतों के उपचार के लिए संतोष नाम के मरीज मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान गए थे। उनकी जांच के बाद डाक्टर ने सीटी स्कैन कराने के लिए एलएन अस्पताल भेज दिया। यहां पहुंचने पर मरीज को मार्च 2027 की तिथि दी गई। मरीज की सर्जरी होनी है और उसे जांच के लिए तीन साल का इंतजार करने को कहा गया है। मौलाना आजाद दंत कालेज की रेडियोलाजी विभाग की एक अधिकारी ने कहा कि छोटे एक्स-रे की सुविधा अस्पताल में मौजूद है। रोजाना सैकड़ों एक्स-रे हमारे यहां होते हैं, लेकिन मरीज को ट्यूमर की समस्या थी। इसलिए सीटी स्कैन कराने को कहा गया था। चूंकि हमारे यहां से सभी सीटी स्कैन एलएन अस्पताल में ही होते हैं। इसलिए मरीज को वहां भेजा गया। हर रोज दो हजार से अधिक मरीजों को सीटी स्कैन की जरूरत होती है। इसलिए समस्या बनी हुई है।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी सुविधाएं देगी सरकार : केजरीवाल

- मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में वातानुकूलित इंडोर तरणताल का किया उद्घाटन

सिविल लाइंस स्थित दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में तरणताल के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, खेल मंत्री आतिशी व अन्य। सौजन्य- दिल्ली सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सिविल लाइंस स्थित दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में वातानुकूलित इंडोर तरणताल का उद्घाटन किया। उन्होंने स्कूल का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। केजरीवाल ने कहा कि वह खेलों को बढ़ावा देने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। इस स्कूल में 172 छात्रों को ओलिंपिक में शामिल 10 खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बच्चों से कहा कि देश ने आप की प्रतिभा पर भरोसा किया है। अब आपको पूरी मेहनत व लगन के साथ पदक जीतकर देश का सपना पूरा करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभा गरीबी और पैसे की मोहताज नहीं होती है। गांवों के बच्चों में भी प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल पाता है। यदि उस प्रतिभा को मदद मिल जाए तो हम किसी भी देश को प्रतियोगिता में हरा सकते हैं। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में अभ्यास कर रहे सभी खिलाड़ियों को ओलिंपिक में अधिक से अधिक पदक लाने की तैयारी करनी है।

वर्ष 2024-25 के लिए डीडीए का 8811 करोड़ रुपये का बजट पारित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 8,811 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया। केंद्र सरकार के अनुरूप इसमें वार्षिक आवंटन का 61 प्रतिशत (लगभग) पूंजीगत व्यय शामिल है। इस बार बजट में मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, नागरिक सुविधाएं बेहतर करने, गांवों का भी उन्नयन करने और दिल्ली के सुंदरीकरण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

बोर्ड बैठक में सामने आया कि एलजी और अधिकारियों के नेतृत्व में बेहतर रणनीतियों के कारण, डीडीए की कुल प्राप्तियां पिछले वर्ष के 4392 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 75 प्रतिशत तक की वृद्धि के साथ 7696 करोड़ रुपये हो गईं। अगले वर्ष के अनुमानों में डीडीए ने अपना राजस्व लक्ष्य 9182 करोड़ रुपये आंका है, जो चालू वर्ष से लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

देश के शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए डोनेशन दें उद्योगपति : धनखड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नई दिल्ली में इंद्रप्रस्थ महिला कालेज के 100वें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को लोगो जारी करते बाएं से डा. सुदेश धनखड़, कालेज के चेयरमैन आलोक वी श्रीराम, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कुलपति प्रो. योगेश सिंह। जागरण

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं को देश के उद्योगपति मोटा डोनेशन देते हैं। भारत से पांच करोड़ डालर का डोनेशन दिया जाता है। वक्त आ गया है कि यह डोनेशन भारत के शैक्षणिक संस्थानों को दिया जाए। खासकर लड़कियों को शिक्षित करने में इसे खर्च किया जाए।

उपराष्ट्रपति धनखड़ बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के इंद्रप्रस्थ महिला कालेज के 100वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे विदेश में डोनेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सीएसआर फंड के लिए यह होना चाहिए, जिससे हमारे शैक्षणिक संस्थानों का और विकास हो सके। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा क्रांति है। गणतंत्र दिवस पर सेना से लेकर एयर फोर्स व पुलिस तक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ। अब उनके और सशक्त बनने का समय है। देश को वर्ष 2047 में विकसित बनना है तो यह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ही संभव होगा।

उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे नवाचार का जो विचार सोचें, उसे क्रियान्वित भी करें। असफलता का डर उनके अंदर नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल आ चुका है। जरूरी है कि उसके अनुरूप भागीदारी भी बढ़े। देश को आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ना होगा। खिलौने, चाकलेट, पतंग, फर्नीचर जैसी वस्तुएं बाहर से आना उचित नहीं लगता। सबका निर्माण हमारे यहां ही होना चाहिए।

बता दें कि इंद्रप्रस्थ महिला कालेज की शुरुआत 1904 में किनारी बाजार, चांदनी चौक की गली अनार में 'इंद्रप्रस्थ पुत्री पाठशाला' के रूप में हुई थी। कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला महिला कालेज है। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कालेज की वर्षों की गौरवशाली यात्रा को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में चार हजार से अधिक छात्राओं ने भाग लिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने की मेट्रो से यात्रा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- यात्रा के लिए एनसीएमसी रुपे का किया इस्तेमाल
- अमृत उद्यान के लिए शटल बस सेवा की भी शुरुआत की

केंद्रीय सचिवालय मेट्रोस्टेशन से नेहरू प्लेस तक बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मेट्रो में सफर किया इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सफर कर रहे स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। सौजन्य-राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार दोपहर मेट्रो ट्रेन से यात्रा की। वह केंद्रीय सचिवालय से वायलेट लाइन (कश्मीरी गेट-राजा नाहर सिंह कारिडोर) मेट्रो में चढ़ीं और नेहरू प्लेस स्टेशन तक गईं। वहां से मेट्रो से ही वापस केंद्रीय सचिवालय लौटीं। रास्ते में उन्होंने मेट्रो में सफर कर रहे स्कूली बच्चों से संवाद किया। राष्ट्रपति ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर चार से अमृत उद्यान के लिए शटल बस सेवा की शुरुआत की। सुबह साढ़े नौ से शाम पांच बजे तक प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल पर बस सेवा उपलब्ध होगी।

द्रौपदी मुर्मु दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मेट्रो में यात्रा की थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक डा. विकास कुमार इस यात्रा में राष्ट्रपति के साथ थे।

उन्होंने राष्ट्रपति को डीएमआरसी के कामकाज और चल रही निर्माण परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने यात्रा के लिए नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) रुपे का उपयोग किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कई बार मेट्रो में यात्राएं की हैं। उन्होंने खासतौर पर कई मौकों पर विदेशी मेहमानों के साथ भी मेट्रो में यात्राएं की हैं।

लोकसभा में 'साथ', लेकिन नगर निगम में छिटक रहे हाथ

निहाल सिंह, नई दिल्ली

- आम चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चल रही मंत्रणा
- निगम में भाजपा के साथ कांग्रेस पार्षदों की मुखरता सत्तारूढ़ आप को कर रही परेशान

सिविक सेंटर में नगर निगम सदन की बैठक में बजट पर चर्चा के दौरान मंगलवार को महापौर डा शैली ओबेराय से बहस करते कांग्रेसी निगम पार्षद। जागरण

लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) में मंत्रणा जारी है। चंडीगढ़ महापौर चुनाव में दोनों साथ भी आए, लेकिन एमसीडी में भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी की मुखरता सत्तारूढ़ आप को अधिक परेशानी में डाल रही है। स्थिति यह कि यहां हाथ उसके काबू में ही नहीं आ पा रहा है। बल्कि, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद बावजूद कांग्रेस पार्टी के पार्षदों की सक्रियता से सत्तारूढ़ आप के हौसले पस्त हो रहे हैं। यह स्थिति नई नहीं है, बल्कि बीते कुछ माह से कांग्रेसी पार्षद सत्तारूढ़ दल को असहज किए हुए हैं। वहीं, गठबंधन की आस में आप के पार्षद फिलवक्त कांग्रेस पार्टी पर सीधी टिप्पणी से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन, यह उदारता भी कांग्रेस पार्षदों को नरम नहीं कर पा रही है। स्थिति यह कि बजट सत्र में कांग्रेस दल की नेता नाजिया दानिश ने सफाई से लेकर सड़कों व स्कूलों की स्थिति में सुधार की मांग समेत अन्य मुद्दों पर सत्तारूढ़ दल की जमकर घेराबंदी की। वहीं, मंगलवार को निगम सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद आरिबा खान और महापौर डा. शैली ओबेराय में तीखी बहस हुई।

आरिबा खान ने बजट नियमानुसार पेश न कराने तथा स्थायी समिति का गठन न होने पर आप सरकार का विरोध किया। इतना ही नहीं, बिना स्थायी समिति के बजट पेश करने को गैरकानूनी करार दिया। इस बीच, महापौर ने जब आरिबा खान को सदन की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी और तय समय से ज्यादा बोलने पर कांग्रेस पार्षदों को बोलने का समय अब न देने की बात कही तो कांग्रेस के पार्षद महापौर के आसन के पास पहुंच गए और विरोध करने लगे।

इस बीच कांग्रेसी पार्षदों के इस रवैये पर सत्तारूढ़ दल के कुछ पार्षदों ने टिप्पणी की, लेकिन अधिकतर इससे बचते नजर आए। वहीं, इस मामले में आप नेता व एमसीडी में नेता सदन मुकेश गोयल का कहना है कि यह तो कांग्रेस को देखना है कि वह गठबंधन धर्म निभाए। हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। कांग्रेस दल की नेता नाजिया दानिश से पक्ष मांगा गया, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आया।

भाजपा देती है पर्दे के पीछे से साथ: कांग्रेस और आप में गठबंधन को परवान न चढ़ने देने के लिए कांग्रेसी पार्षदों के विरोध में भाजपा पार्षद शांति ओढ़ ले रहे हैं। इससे आप की असहजता और बढ़ रही है। कांग्रेस दल की नेता नाजिया दानिश ने जब बजट पर भाषण दिया तो भाजपा पार्षद शांत रहे। जबकि, मंगलवार को महापौर और कांग्रेसी पार्षदों में नोकझोंक के बीच जब मामले से आगे बढ़ने के लिए महापौर ने भाजपा पार्षद योगेश वर्मा को बोलने का मौका और माइक दिया तो वह तब तक शांत रहे जब तक कांग्रेस पार्टी के पार्षद अपनी बात पूरी तरह से रख नहीं पाए।

एमसीडी में भाजपा और आप दोनों के लिए कांग्रेस महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पास स्थायी समिति की सत्ता की चाबी है। मध्य जोन की वार्ड कमेटी से एक सदस्य स्थायी समिति के लिए चुना जाना है।

संरक्षण जरूरी

पेंटिंग पर खर्च हुई है करीब सात करोड़ की राशि, यहां 98 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया गया आर्टवर्क

डेढ़ साल में ही बदसूरत हो गई विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग

वी के शुक्ला, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में शुरू की गई सुरंग सड़क में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी वाल पेंटिंग या दीवार पर बनी पेंटिंग खराब हो गई है। उकेरे गए चित्रों के बीच-बीच कई जगह दीवार काली हो चुकी है, पानी के रिसाव ने दीवार पर बनी पेंटिंग को बदसूरत बना दिया है। प्रगति मैदान में दुनिया में सबसे बड़े आउटडोर पब्लिक आर्ट वर्क के तौर पर गिनीज रिकार्ड्स में नाम दर्ज कराने की तैयारी की जा रही थी, जो आगे नहीं बढ़ सकी है। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पेंटिंग के रखरखाव का काम पांच साल तक निर्माणकर्ता कंपनी एलएंडटी (लार्सन एंड टूब्रो) के पास है। उन्होंने बताया कि पेंटिंग को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है।

दुनिया में सबसे बड़े आउटडोर पब्लिक आर्ट वर्क के तौर पर अभी दक्षिण कोरिया की इंचियान के नाम यह रिकार्ड है। जहां 23,688 वर्ग मीटर के क्षेत्र में पेंटिंग बनाई गई है, जबकि प्रगति मैदान की नीचे बनी सुरंग का काम पूरा होने के बाद यहां 98 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र में आर्टवर्क बनाया गया है। सुरंग सड़क से प्रगति मैदान के अंदर जाने और वापस आने वाले लूप में इसी माह पेंटिंग का काम पूरा हुआ है। पेंटिंग में स्टील की चादरों पर कटिंग कर काम किया गया है।

प्रगति मैदान सुरंग सड़क में हो रहे पानी के रिसाव से खराब हो रही पेंटिंग व दिवारें। जागरण

पेंटिंग पर आया है करीब सात करोड़ खर्च

पेंटिंग को लेकर सुरंग को छह हिस्सों में विभाजित किया गया है। हर एक हिस्सा भारत के अलग-अलग मौसम को दर्शाता है। जहां मौसम के हिसाब से सूरज और चांद के महत्व को दर्शाया गया है। यह आर्ट वर्क भारत की छह मौसमों में जिंदगी पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के साथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सभी त्योहारों की झलक देखने को मिलती है। इस सुरंग की कुल लंबाई 1.3 किमी है। आइटीपीओ द्वारा फंडेड इस सुरंग सड़क परियोजना पर करीब 777 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पेंटिंग पर करीब सात करोड़ रुपये का खर्च आया है।

गंदी हो रही पेंटिंग देख बुरा लगता है : हिम चटर्जी

इस पेंटिंग को शिमला यूनिवर्सिटी के आर्ट के पूर्व प्रोफेसर हिम चटर्जी के निर्देशन में बनाया गया है। वह कहते हैं कि पेंटिंग के मुख्य भाग को पाउडर कोटेड स्टील की चादर पर बनाया गया है, जो जल्द खराब न होने वाली पेंटिंग है। यह पेंटिंग दीवार से करीब तीन से चार इंच उभरी हुई है, इसमें कुछ नुकसान नहीं है। मगर दीवार पर हाथ से की गई पेंटिंग पानी के रिसाव के कारण कुछ स्थानों पर खराब हुई है। पेंटिंग अच्छी नहीं दिखती है तो गुजरने वालों को भी बुरा लगता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर से कांग्रेस ने किया 'किनारा'

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

जगदीश टाइटलर।

लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार रात घोषित हुई प्रदेश कांग्रेस की चार अहम समितियां

इसे कांग्रेस की राजनीतिक समझ कहें या दूरदर्शिता...लेकिन पहली बार वह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर से 'किनारा' करती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ना तो उन्हें किसी समिति में शामिल किया गया है, न प्रचार अभियान से ही जोड़ा जा रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी इस बार व्यर्थ के विवादों से बचना चाह रही है।

गौरतलब है कि मंगलवार देर रात अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआइसीसी) ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस की एक साथ चार महत्वपूर्ण समितियों की घोषणा की। चुनाव समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, घोषणा पत्र समिति और अनुशासन समिति।

इन समितियों में छोटे-बड़े तमाम नेता शामिल कर लिए गए, मगर जगदीश टाइटलर को किसी भी में नहीं रखा गया। पार्टी के एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने बताया कि टाइटलर को जब-जब किसी समिति में रखा गया, सिखों का विरोध शुरू हो गया। इसीलिए इस बार उन्हें समितियों से दूर ही रखा गया है, ताकि व्यर्थ का विवाद न उठे। सूत्र बताते हैं कि इसकी एक वजह आप और कांग्रेस में होने वाला गठबंधन भी हो सकता है, क्योंकि आप भी टाइटलर का विरोध करती रही है।

****

10 वर्षों में 1,700 प्रतिशत बढ़ी मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग। यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा में दी। इस अवधि में मोबाइल निर्यात में 5,600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उत्तर-दक्षिण का विवाद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण : मोदी

पीएम बोले ▸ राज्यों के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव

हिंदुस्तान के किसी कोने में दर्द हो, पीड़ा सबको होनी चाहिए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में बुधवार को बोलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक सरकार द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत का विवाद खड़ा करने को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया। उन्होंने देश को एकांगी भाव से देखने की जरूरत बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी भाग में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि राज्यों के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है। देश का एक भी कोना विकास से वंचित रह जाए तो देश विकसित नहीं हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में साफ किया कि राष्ट्र उनके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक शरीर की तरह है। जैसे पैर में कांटा चुभने पर हाथ उसे निकालने में लग जाता है, उसी तरह से राष्ट्र के विकास के लिए भी सभी को मिलकर काम करना होगा। उत्तर-दक्षिण विवाद को देश को तोड़ने के लिए नया नैरेटिव बताते हुए उन्होंने कहा कि एक पार्टी की ओर से ऐसे विचार का आना दुखद है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया समेत तमाम मंत्रियों के धरने पर बैठने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जब पूरी सरकार मैदान में उतरकर ऐसी भाषा गढ़ रही हो तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मोदी ने कहा कि हमारा टैक्स, हमारी मनी की भाषा देश के भविष्य के लिए बड़ा खतरा पैदा करने वाली है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के बीच बंटवारे के नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा कि झारखंड का एक आदिवासी युवक यदि ओलंपिक में पदक जीतता है तो पूरे देश को गर्व होता है। इसी तरह से कोरोना काल में किसी राज्य के किसी शहर में निर्मित वैक्सीन ने सभी भारतीयों की जान बचाने का काम किया मगर उस शहर या राज्य ने वैक्सीन पर पहला दावा नहीं किया। कोरोना काल में ही पूर्वी राज्यों में उत्पादित होने वाली आक्सीजन ने पूरे भारत में लाखों जीवन बचाने का काम किया। इसी तरह से हिमालय के राज्य अपनी यहां से निकलने वाली नदियों के पानी और कोयला उत्पादक राज्य कोयले को सिर्फ अपने लिए उपयोग का दावा नहीं करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा- 'देश को तोड़ने के लिए नया-नया नैरेटिव ढूंढना बंद कर दीजिए।'

मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि राज्यों की जरूरतों को वे अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए राज्यों के बीच उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना काल में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें कीं और पूरा देश एकजुट होकर सदी के सबसे बड़े संकट का सामना कर पाया। इसी तरह से जी-20 को सिर्फ दिल्ली तक सीमित रखने के बजाय सभी राज्यों में 200 बैठकें आयोजित की गईं। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को भी वे किसी न किसी राज्य में जरूर ले जाते हैं ताकि दुनिया भारत से सभी राज्यों से परिचित हो सके और पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हो सकें।

कांग्रेस को बताया अंग्रेजों का पिछलग्गू : प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को अप्रासंगिक और अंग्रेजों का पिछलग्गू करार दिया। कहा- उसने न तो अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलने की कोशिश की और न ही अंग्रेजों की नीतियों पर चलने की आदत छोड़ी। इसी कारण कांग्रेस बजट भी शाम पांच बजे पेश करती रही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के वहां 10 बजे शुरू होने का समय होता था। यहां तक कि सेना में भी अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक चलते रहे और युद्ध में मारे जाने वाले जवानों के सम्मान के लिए वार मेमोरियल भी नहीं बनाया गया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के जमाने के राजपथ को भी कर्तव्यपथ बनाने की कोशिश नहीं की।

मोदी 3.0 में रखी जाएगी विकसित भारत की मजबूत नींव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं को भी सामने रख दिया। उनके अनुसार तीसरे कार्यकाल में मौजूदा गरीब कल्याण योजनाओं को जारी रखने के साथ ही विकसित भारत की मजबूत नींव रखने का भी काम होगा। कहा कि विकसित भारत उनके लिए सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि वे इसी भावना के साथ चलते हैं।

प्रधानमंत्री के अनुसार तीसरे कार्यकाल में हर घर में नल से जल, गरीबों को पक्का घर देने, बुलेट ट्रेन चलाने का काम पूरा करने के साथ ही अधिकतम घरों में सोलर पैनल लगाने और पाइप गैस कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। इस दौरान दुनिया भारत की युवा शक्ति का दम देखेगी। बड़ी संख्या में स्टार्टअप और यूनिकार्न बनने के साथ ही रिकार्ड संख्या में पेटेंट फाइल होंगे। खेल में भारत का झंडा और ऊंचा होगा।

मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत एक शक्ति के रूप में सामने आएगा और हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, एथनाल ऊर्जा पर विदेशी निर्भरता को कम करेगा, डिजिटल इकोनमी में भारत का डंका बजेगा। स्पेस के क्षेत्र में भारत दुनिया को अचंभित करेगा तो इलेक्ट्रोनिक्स बाजार में नया सामर्थ्य भी दिखेगा। इस दौरान देश की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी

संसद प्रश्नोत्तर

आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू होगी जीपीएस आधारित टोल प्रणाली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ मार्च के पहले सप्ताह में लागू हो सकती है आदर्श आचार संहिता

▸ फास्टैग से प्रतिदिन हो रही 170 से 200 करोड़ की टोल वसूली

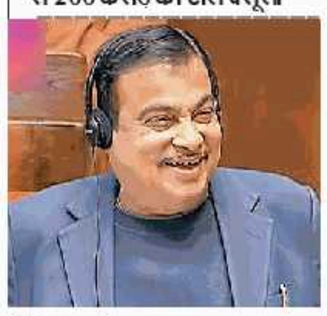
नितिन गडकरी। एएनआइ

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व देश में सेटेलाइट आधारित टोल प्रणाली शुरू हो जाएगी। माना जा रहा कि आगामी लोकसभा चुनाव आचार संहिता मार्च के पहले सप्ताह में लागू हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हम संसद को आश्वस्त करना चाहते हैं कि टोल प्रणाली को लेकर दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक सेटेलाइट आधारित प्रणाली जल्द शुरू की जाएगी। टोल नाके हटा दिए जाएंगे। इससे लोगों को रुकने की जरूरत नहीं होगी और नंबर प्लेट की फोटो से टोल वसूली होगी। यह प्रणाली हाईवे अथवा एक्सप्रेसवे का प्रयोग किए जाने वाले समय के आधार पर शुल्क वसूलेगी। यह शुल्क वाहन चालक के बैंक अकाउंट से स्वतः कट जाएगा। इस दौरान गडकरी ने फास्टैग से वसूली का आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि फास्टैग से 49 हजार करोड़ रुपये से अधिक टोल वसूली हो चुकी है। प्रतिदिन का संग्रह 170 से 200 करोड़ के बीच का है। उन्होंने यह भी बताया कि संप्रग सरकार में शहर से एकदम सटे इलाकों में टोल प्लाजा बना दिए गए और इससे हजारों लोग प्रभावित हैं। ठेकेदारों द्वारा हर्जाना मांगे जाने के कारण हम इन टोल को नहीं हटा पा रहे हैं। गडकरी ने कहा कि ऐसे मामलों में हम केवल ठेके की अवधि समाप्त होने का इंतजार कर सकते हैं।

अगले माह हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना का शिलान्यास

एक अन्य सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि धर्म स्थलों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के क्रम में हेमकुंड साहिब पर रोपवे परियोजना का अगले माह शिलान्यास होने की उम्मीद है। उन्होंने हेमकुंड साहिब तक बेहतर सड़क की मांग के संदर्भ में कहा कि यहां सड़क से बेहतर रोपवे का विकल्प है। अगले साल इस परियोजना का काम पूरा किया जा सकता है।

सिलक्यारा-बारकोट सुरंग का कोई हिस्सा 2019 में नहीं धंसा

गडकरी ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि सिलक्यारा-बारकोट सुरंग के गत वर्ष ढहे हिस्से में 2019 में कोई दरार नहीं थी और न यह हिस्सा ढहा था। गत 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने से 41 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को गत 28 नवंबर को निकाला जा सका था। वह सुरंग के ढहे हिस्से में 2019 में दरार अथवा ढहने के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बीआरओ, रेलवे मंत्रालय, सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय व प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल कर विशेषज्ञ समिति सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच के लिए गठित की जा चुकी है।

वंदे भारत ट्रेनों की गति 160 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने पर काम शुरू : वैष्णव

नई दिल्ली, प्रेट्र : वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 82 कर दी गई है। अब नई दिल्ली-मुंबई व नई दिल्ली-हावड़ा रूट पर इन ट्रेनों की गति 160 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में 10 सांसदों द्वारा किए गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। वंदे भारत की राज्यवार औसत आय कहा कि राज्य वार राजस्व सृजन का रखरखाव नहीं किया जाता है।

आनलाइन दर्ज कराई जा सकती है सरकारी विभागों से संबंधी शिकायत

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोई भी नागरिक केंद्रीय सरकार विभाग, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित शिकायत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर दर्ज करा सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के 1.3 लाख शिकायत अधिकारी इस प्रणाली से जुड़े हैं।

बाबा साहब नहीं होते तो शायद एससी, एसटी को भी आरक्षण नहीं मिलता

प्रथम पृष्ठ से आगे

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे प्रधानमंत्री ने आशंका जताई कि यदि बाबा साहब आंबेडकर नहीं होते, तो शायद एससी और एसटी को भी आरक्षण नहीं मिलता।

नारे लगाते कांग्रेस सदस्यों के विरोध के बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से जाति जनगणना और ओबीसी, एससी, एसटी को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग महज दिखावा है। कांग्रेस के लिए नेहरू का कथन पत्थर की लकीर है। उनकी दलित विरोधी मानसिकता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि आंबेडकर को भारत रत्न देने के बजाय अपने परिवारजनों को वे भारत रत्न देते रहे। उन्होंने पिछले दिनों ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख और गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा के पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें संविधान निर्माण में बाबा साहब आंबेडकर के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश की गई थी। मोदी ने कहा कि उन्होंने दलित नेता और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी को जबरन उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया था, जिसके वीडियो भी उपलब्ध हैं।

परोक्ष तौर पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस नेता की खुद की गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस को ओबीसी, एससी व एसटी का जन्मजात विरोधी बताते हुए प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में उनके उत्थान के लिए उठाए गए कदमों को गिनाया। कहा- केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों में इसी वर्ग के लोग सर्वाधिक हैं, जिन्हें पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन से धुएं से मुक्ति मिली है, मुफ्त में राशन मिल रहा है और आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में इलाज भी हो रहा है। कांग्रेस नेताओं पर भ्रामक आंकड़ों के सहारे देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि एससी, एसटी स्कालरशिप में 10 सालों में बढ़ोतरी हुई है। शिक्षण संस्थानों में नामांकन बढ़ा है और ड्रापआउट तेजी से कम हुआ है।

लोकसभा ने अंतरिम बजट को दी मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ वित्त मंत्री ने कहा, बेरोजगारी और महंगाई दोनों में कमी आई

▸ कार्य बल में लगातार बढ़ती जा रही महिलाओं की भागीदारी

निर्मला सीतारमण। एएनआइ

लोकसभा ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट (लेखानुदान) को बुधवार को पारित कर दिया। अंतरिम बजट पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई दर में कमी आ रही है। सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में किसी भी कल्याणकारी योजना के मद में कोई कटौती नहीं की है। सरकार की वित्तीय मजबूती की वजह से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रखा गया है, जबकि पहले यह लक्ष्य 5.2 प्रतिशत था। वहीं देर रात लोकसभा से वित्त विधेयक 2024 भी ध्वनि मत से पारित हो गया।

बेरोजगारी और कार्य बल को लेकर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर छह प्रतिशत थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई। 2017-18 में यूथ वर्क फोर्स 38.2 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 44.5 प्रतिशत हो गया। यानी इसमें 6.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। असंगठित सेक्टर के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है और इस पोर्टल पर अब तक 29 करोड़ श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें 53 प्रतिशत महिलाएं हैं।

सीतारमण ने महंगाई पर विपक्ष के सवालों के जवाब में कहा कि वर्ष 2022 के अप्रैल-दिसंबर में औसत महंगाई दर 6.8 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2023 की समान अवधि में 5.5 प्रतिशत रही। सरकार की तरफ से महंगाई कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सस्ते दाम पर भारत आटा, भारत दाल, भारत चावल व प्याज की बिक्री की जा रही है। इसका नतीजा है कि खुदरा महंगाई में कमी आई है। उन्होंने बताया कि 27.50 रुपये की दर से अब तक 2.37 लाख टन आटे की बिक्री हो चुकी है। वहीं 25 रुपये की दर से 3.96 लाख टन प्याज बेचे गए हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के साथ बहुआयामी गरीबी से जुड़े सभी मदों में चालू वित्त वर्ष की तुलना में अधिक आवंटन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विपक्ष के सदस्य ने पीएम पोषण में कम आवंटन की बात की थी, लेकिन असल में आगामी वित्त वर्ष में पीएम पोषण के मद में 12,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। चालू वित्त वर्ष में इस मद में 11,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। कुछ सांसदों ने स्कूल के मद में आवंटन को लेकर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के तहत स्कूल के मद में 68,000 करोड़ रुपये आवंटित है, जबकि आगामी वित्त वर्ष में इस मद में 72,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

राहुल गांधी ने कुत्तों के लिए बने बिस्किट आदमी को दिए : निशिकांत दुबे

▸ कांग्रेस नेता के कुत्ते वाले वायरल वीडियो पर भाजपा का निशाना

▸ कटाक्ष पर लोकसभा में विपक्षी दलों ने किया शोरगुल

निशिकांत दुबे। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद दावा किया कि कांग्रेस नेता ने कुत्तों के लिए बने बिस्किट झारखंड के लोगों को दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विगत मंगलवार को अपनी सफाई में कहा था कि एक कुत्ते के उनके हाथ से बिस्किट नहीं खाने पर वह कुत्ते के मालिक को उसे खिलाने के लिए दिया था। लोकसभा में बजट सत्र में चर्चा के दौरान भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड में हमारे गांव में लोग इतने गरीब हैं कि अगर वह अपने परिवार का पेट भर पाते हैं तो उनके लिए इतना ही काफी है। वह कुत्तों को नहीं खिलाते हैं। राहुल गांधी ने एक कुत्ते का बिस्किट एक आदमी को दिया।

निशिकांत दुबे के इस बयान पर विपक्षी दलों की बेंचों से शोरगुल शुरू हो गया। यहां तक कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने प्वाइंट आफ आर्डर का मुद्दा भी उठाया। दुबे उस वीडियो का हवाला दे रहे थे जिसमें राहुल गांधी को झारखंड की यात्रा के दौरान एक कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए देखा गया था। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किए जाने पर भी निशाना साधते हुए कहा, 'इस देश में कुत्तों का बहुत महत्व है। मैंने एक फिल्म देखी थी, 'तेरी मेहरबानियां' जिसमें एक कुत्ते ने अपने मालिक के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन यहां उसका एक दूसरा पहलू है। पिद्दी के कारण हिमंत बिस्वा सरमा को (कांग्रेस से) जाना पड़ा, हेनरी के कारण एक महिला सांसद को (संसद से) जाना पड़ा और अब नूरी के प्रभाव में आकर वह कुत्ते के बिस्किट एक आदमी को दे रहे हैं।'

भाजपा के आरोप से परेशान राहुल गांधी मंगलवार को कह कह चुके हैं कि इस पार्टी को कुत्तों से क्या परेशानी है। उल्लेखनीय है कि विगत 4 फरवरी को झारखंड के धनबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस वीडियो को शूट किया गया था।

कामकाज के आधार पर जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना व्यावहारिक नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने संसद की एक समिति से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु उनके कामकाज के आधार पर बढ़ाना व्यावहारिक होने की संभावना नहीं है। इससे संसद के अधिकारों में और कटौती होगी तथा इसके परिणामस्वरूप अनुचित पक्षपात भी हो सकता है।

विधि एवं कार्मिक मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने पिछले साल अगस्त में 'न्यायिक प्रक्रियाएं और उनके सुधार' विषय पर अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के न्यायाधीशों का कार्यकाल मौजूदा सेवानिवृत्ति आयु से बढ़ाने के लिए कामकाज के आधार पर मूल्यांकन की सिफारिश की थी। संवैधानिक प्रविधानों के अनुसार, इस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, वहीं 25 हाई कोर्टों के जज 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, इसके लिए कलेजियम द्वारा मूल्यांकन की एक प्रणाली बनाई जा सकती है।

गांधी परिवार ने अमेठी की 48 साल अनदेखी की : स्मृति इरानी

▸ कहा-गांधी परिवार को चुनौती देने वालों ने झेली कांग्रेस की असहिष्णुता

▸ राजमोहन को नकली गांधी बोल पत्थर मारे, शरद यादव को कहा-गाय चराएं

स्मृति इरानी। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 48 सालों तक उत्तर प्रदेश की अमेठी विकास से वंचित रही जबकि लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार के लोग करते रहे थे।

लोकसभा में बजट सत्र के दौरान हुई चर्चा में स्मृति इरानी ने बुधवार को कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही इस संसदीय क्षेत्र का विकास होना शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री इरानी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में अमेठी से राहुल गांधी को हराया था।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि अमेठी में गांधी परिवार को चुनौती देने वालों के प्रति कांग्रेस की असहिष्णुता इतनी अधिक थी कि यहां महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को भी 1989 में लोकसभा चुनाव लड़ने पर अपमानित कर पत्थरों से मारा गया था। इरानी ने कहा कि राजमोहन गांधी ने गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें गांधी परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए नकली गांधी बुलाया गया था। मेनका गांधी और शरद यादव को भी अपमानित किया गया था। शरद यादव से कहा गया कि वह जाकर गाय चराएं। उन्होंने कांग्रेस का फटकारते हुए 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि सुलतानपुर जिले में आने वाली अमेठी सीट में 62 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं थी और 83 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री को निर्देश, न करें वादी के जाति-धर्म का उल्लेख

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री अधिकारियों से बुधवार को कहा कि वे अदालत के हालिया आदेश का अनुपालन करें जिसमें कहा गया था कि वादियों की जाति या धर्म के उल्लेख का चलन बंद किया जाना चाहिए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने 10 जनवरी को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री और अन्य सभी अदालतों को निर्देश दिया था कि वे अदालती मामलों में वादियों की जाति या धर्म के उल्लेख का चलन तत्काल बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा कि रजिस्ट्री के सभी संबंधित अधिकारी अदालती निर्देशों का अनुपालन करें, लिहाजा अब से इस अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं में पक्षकारों के ब्योरे (मेमो) में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) जैसी बार संस्थाओं को भी निर्देशों का संज्ञान लेने को कहा।

आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी है, अनगिनत झूठ के सहारे यूपीए सरकार पर लगाए गए आरोप

प्रधानमंत्री मोदी के पास अपना बताने को कुछ नहीं : खरगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में बोलते मल्लिकार्जुन खरगे। प्रेट्र

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तथ्यों से छेड़छाड़ कर यूपीए सरकार पर अनर्गल टीका-टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बेरोजगारी से लेकर आर्थिक विकास दर और महंगाई से लेकर आयात-निर्यात संतुलन जैसे हर मोर्चे पर भाजपा सरकार कमजोर साबित हुई है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब के दौरान पीएम की ओर से किए बेहद तीखे हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम ने अनगिनत झूठ के सहारे यूपीए और कांग्रेस को कोसा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी को इसका जवाब देना चाहिए कि यूपीए सरकार के समय बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत थी लेकिन उनके कार्यकाल में यह 45 वर्षों में सबसे ज्यादा क्यों है। यूपीए के 10 वर्षों में दौरान जीडीपी विकास दर औसतन 8.13 रही तो उनके शासन में केवल 5.6 प्रतिशत क्यों। खरगे ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की मानें तो 2011 में ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमने 10 साल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन, पीएम इधर-उधर के भाषणों को कांट-छांट कर भ्रम और झूठ फैला रहें हैं। सच्चाई है कि डिजिटल इंडिया की तरक्की की बुनियाद यूपीए ने आधार और डीबीटी के जरिये रखी थी। देश की 65 करोड़ की आबादी को 2014 तक आधार दिया जा चुका था। डीबीटी-पहल से सीधे सब्सिडी देने का काम शुरू हो गया था। स्वाभिमान योजना के तहत गरीबों के 33 करोड़ बैंक खाते हम खोल चुके थे।

खरगे ने कहा कि पीएम मोदी 10 सालों से शासन में हैं, लेकिन अपनी बात करने की बजाय केवल कांग्रेस को कोसते रहे और महंगाई, रोजगार, आर्थिक समानता की कोई बात नहीं की। असल वजह यह है कि इस सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। एनडीए का मतलब ही नो डाटा एवलेबल सरकार है। जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ, रोजगार, स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डाटा नहीं और सरकार सारे आंकड़े छिपा कर झूठ फैलाती है। खरगे ने पीएम की गारंटी पर सियासी तंज कसते हुए कहा कि झूठ फैलाना ही 'मोदी की गारंटी' है।

मोदी सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए खरगे ने कहा कि सरकारी कंपनियों को लेकर वह 'बेचो और लूटो' की नीति अपना रही है। अप्रैल 2022 तक 147 सार्वजनिक उपक्रमों को पूरा या आधा बेच दिया गया। सरकारी नौकरियों की भर्ती ठप है और सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसमें एससी-एसटी और ओबीसी के सबसे अधिक पद रिक्त हैं।

अपने भाषण के हटाए गए हिस्सों को बहाल करने का किया आग्रह

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को सभापति जगदीप धनखड़ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उनके भाषण के हटाए गए हिस्सों को बहाल करने का आग्रह किया। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए खरगे ने कहा कि उनके दो फरवरी के भाषण से दो पेज हटा दिए गए हैं, जिससे उनकी द्वारा कही गई बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे, उन्हें रिकार्ड से हटा दिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और न ही किसी नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाने के खिलाफ अपने तर्क के समर्थन में कई नियमों का हवाला दिया। खरगे ने इस मामले पर सभापति को एक लिखित नोट भी दिया है। धनखड़ ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे।

कह कर रहेंगे

माधव जोशी

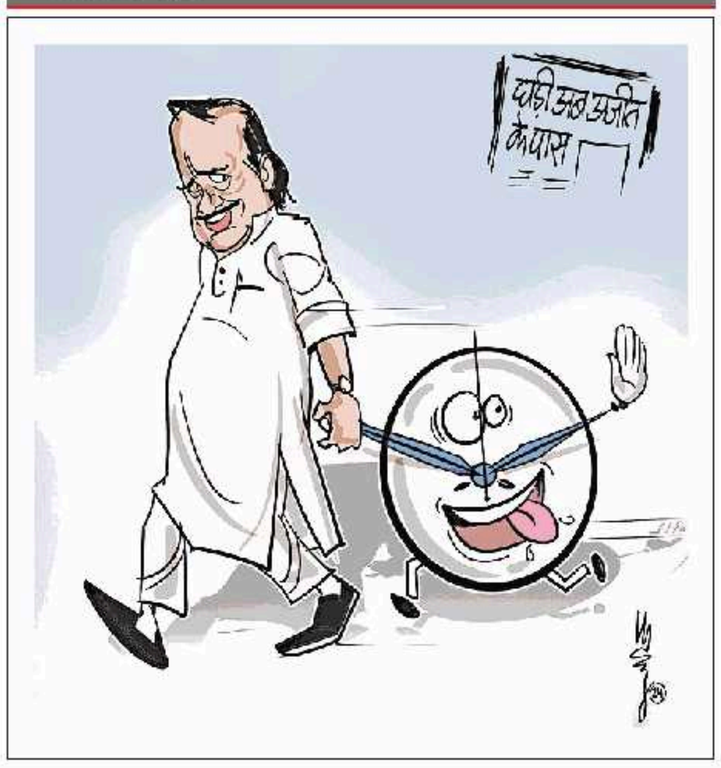

****

6 सीटों के लिए बिहार में दलों के अंदर शुरू हुई प्रत्याशियों की स्क्रूटनी राज्यसभा के लिए। सामाजिक समीकरण और नेतृत्व की कसौटी वाले चेहरों पर मंथन कर रहीं पार्टियां

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 फरवरी, 2024

अब इधर-उधर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे : नीतीश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम मोदी और शाह-नड्डा से मिलने के बाद बोले मुख्यमंत्री
- जदयू ने भाजपा नेताओं से मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट
- कहा हम 1995 से अटलजी के समय से ही साथ थे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। प्रेट्र

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बुधवार को कहा कि अब इधर-उधर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। राजद-कांग्रेस के महागठबंधन को छोड़कर बिहार में भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी एवं भाजपा नेताओं से यह पहली मुलाकात है। भाजपा के तीनों शीर्ष नेताओं से नीतीश की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को नई सरकार को बहुमत साबित करना है। दो दिन पहले नीतीश के सहयोगी बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी।

प्रधानमंत्री के साथ नीतीश की मुलाकात करीब आधे घंटे की रही। उसके बाद उन्होंने बारी-बारी से शाह एवं नड्डा से भेंट की। जदयू के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा के साथ बाहर निकले नीतीश के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हो गई। इसके पहले जब एक साथ थे तो बातचीत हुई थी। एक सवाल के जवाब में नीतीश ने कहा कि हम लोग 1995 से अटलजी के समय से ही साथ थे। बीच में दो बार इधर-उधर जरूर हो गए थे, अब फिर साथ आ गए हैं। अब कहीं नहीं जाएंगे। सीट बंटवारे के फार्मूले पर नीतीश ने कहा कि अभी इसका कोई तुक नहीं है। आज की मुलाकात में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। सीट बंटवारे पर बात होगी, लेकिन अभी नहीं। उन लोगों को सब पता है इसलिए अभी बात करने की जरूरत नहीं है।

तीनों शीर्ष नेताओं से बातचीत के बारे में नीतीश ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि उनके एजेंडे में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, राज्यसभा चुनाव एवं बहुप्रतीक्षित विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जे पर विमर्श शामिल है। बिहार में राजग के घटक दलों के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। साथ ही बिहार से राज्यसभा की छह सीटें भी रिक्त होने जा रही हैं, जिनमें जदयू एवं राजद की दो-दो और कांग्रेस एवं भाजपा की एक-एक सीट है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। इस दौरान उन्होंने बिहार राजग में सीटों के बंटवारे पर बातचीत की संभावनाओं से इन्कार किया, लेकिन लोकसभा चुनाव करीब होने के चलते माना जा रहा है कि बिहार के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। जदयू से जुड़े सूत्र ने बताया कि विशेष राज्य का दर्जा भी नीतीश के एजेंडे में प्रमुख है, लेकिन सारा ध्यान अभी बिहार विधानमंडल के बजट सत्र पर है। नीतीश की मोदी से मुलाकात पिछले वर्ष सितंबर में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में हुई थी। नीतीश तब राजद एवं कांग्रेस के साथ थे।

पवार गुट अब हुआ राकांपा शरदचंद्र पवार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) करार देने के बाद अब शरद पवार गुट को भी नया नाम दे दिया है। उसे फिलहाल 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार' के नाम से जाना जाएगा। शरद गुट अब इसी नाम से राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतर सकेगा। आयोग ने हालांकि उन्हें अभी कोई चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया है, लेकिन शरद गुट ने इसके लिए दो विकल्प प्रस्तावित किए हैं, इनमें एक उगता सूरज और दूसरा बरगद का पेड़ बताया जा रहा है।

चुनाव आयोग के निर्देश पर शरद गुट ने बुधवार को तय समय-सीमा के भीतर अपनी पार्टी के लिए तीन नामों का विकल्प मुहैया कराया था। इसमें पहला नाम- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, दूसरा- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदराव पवार और तीसरा- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद पवार दिया था। आयोग ने फिलहाल के लिए पहले नाम के विकल्प को स्वीकृति दे दी है।

आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े विवादों पर छह महीने से ज्यादा समय तक सुनवाई करने के बाद अजीत पवार गुट को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मान्यता दी थी। साथ ही उन्हें ही पार्टी का चुनाव चिह्न घड़ी भी आवंटित कर दिया था। इससे पहले आयोग ने इस मामले में दोनों पक्षों को दस बार सुना।

शरद गुट जाएगा सुप्रीम कोर्ट, अजीत गुट ने दाखिल की कैविएट

नागपुर में बुधवार को असली एनसीपी घोषित होने और चुनाव चिह्न मिलने पर मिठाई खिलाकर जश्न मनाते राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गुट के कार्यकर्ता। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : राकांपा-शरदचंद्र पवार ने बुधवार को कहा कि वह चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पार्टी प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि आयोग का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है जो विवाद की स्थिति में राजनीतिक पार्टी को उसके विधायक दल के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। वहीं, राकांपा के अजीत पवार गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर मांग की कि अगर शरद पवार गुट चुनाव आयोग के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देता है तो उनके गुट का पक्ष भी सुना जाए। अजीत गुट ने कैविएट यह सुनिश्चित करने के लिए दाखिल की है कि शीर्ष अदालत कोई एकतरफा आदेश न जारी कर दे।

तमिलनाडु भाजपा में शामिल हुए 15 पूर्व विधायक व पूर्व सांसद

चुनावी साथ ▸ भाजपा में आए 15 नेता अन्नाद्रमुक व एक द्रमुक से हैं

अन्नाद्रमुक ने बंद किए भाजपा के लिए अपने दरवाजे

चेन्नई, आइएएनएस : लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भाजपा ने बड़ी सेंध लगा ली है। अन्नाद्रमुक पार्टी के 15 पूर्व विधायकों और द्रमुक के पूर्व सांसद को भाजपा में शामिल कर लिया गया है। इससे नाराज होकर कभी जे. जयललिता की पार्टी रही अन्नाद्रमुक ने भाजपा के लिए अपने दरवाजे बंद करने का एलान कर दिया है।

दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बुधवार को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तमिलनाडु से भाजपा के 16 नए सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एल.मुरुगन और तमिलनाडु इकाई के भाजपा अध्यक्ष के.अन्नामलाई भी मौजूद रहे। द्रमुक से आए पूर्व सांसद डी.कुलनताई वेलु भाजपा में शामिल हो गए हैं। वह कुड्डालोर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और द्रमुक में जिला स्तर के प्रभारी समेत विभिन्न पदों पर रहे हैं।

चंद्रशेखर ने कहा कि तमिलनाडु के पूर्व विधायकों और एक पूर्व सांसद ने भाजपा में शामिल होकर दक्षिणी राज्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का परिचय दिया है। यहां पहले परंपरागत रूप से भाजपा की पकड़ नहीं रही है। हर कोई पिछले दस सालों में देश में हुए नए बदलावों का हिस्सा बनना चाहता है। वहीं, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के.अन्नामलाई ने पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सभी नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे।

बुधवार को तमिल अखबार में प्रकाशित इंटरव्यू में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि अन्नाद्रमुक से गठबंधन के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हुए हैं। इस इंटरव्यू के संदर्भ में तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने बताया कि अमित शाह ने अन्नाद्रमुक का स्पष्ट नाम लेकर या उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। बल्कि दूसरी ओर उन्होंने सभी दलों को आमंत्रित किया जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व मंजूर है। हालांकि तमिलनाडु के विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने अन्नामलाई के बयान पर आरोप लगाया कि भाजपा ने द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई और दिवंगत नेता जे जयललिता के भरोसे को धोखा दिया है। अन्नाद्रमुक शासन में मंत्री रहे जयकुमार ने कहा कि इस पार्टी का प्रस्ताव है कि अन्नाद्रमुक अब भाजपा से कोई गठबंधन नहीं करेगा। भाजपा चाहे तो अपना दरवाजा खुला रखे, लेकिन अन्नाद्रमुक ने भाजपा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं।

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्ना मलाई की उपस्थिति में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआइएडीएमके) के पूर्व नेता ने बुधवार को भाजपा के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। चुनाव से पहले भाजपा की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। एएनआइ

'मिशन-400' पर तेज हुई रफ्तार

जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए आइएनडीआइए के रूप में 28 दलों ने कदम तो बढ़ाया, लेकिन सीटों के बंटवारे पर छाई रही कलह-मनमुटाव की धुंध ने इनमें से कुछ की राहें बदल दीं तो कुछ दल हाथ झटककर अलग खड़े हो गए। वहीं, दूसरी ओर मोदी की गारंटी पर लोगों के विश्वास और हर चुनाव में भाजपा के स्ट्राइक रेट के रिकार्ड ने राजग के विस्तार का नया द्वार खोल दिया। यही कारण है कि साथ आ चुके और आने वाले दल अब सीटों की संख्या पर भी समझौता करने को तैयार हैं। जदयू पहले ही साथ आ चुका है। उत्तर प्रदेश में रालोद और आंध्र प्रदेश में टीडीपी भी राजग का कुनबा बढ़ाने के लिए द्वार पर खड़ी है।

केंद्र की सत्ता में तीसरी बार वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को भाजपा 370 पार और राजग 400 पार का उद्घोष कर पार्टी संगठन को न सिर्फ बड़ा लक्ष्य सौंप दिया, बल्कि रणनीति को नई धार भी दे दी। अब जिस तेजी से देश के विभिन्न राज्यों में समीकरण बदल रहे हैं, वे बताते हैं कि भाजपा के रणनीतिकारों ने 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में राजग की जीत के आंकड़े को 400 पार ले जाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। इसके लिए राज्यों में जातीय-क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु का बुधवार को दिल्ली आगमन प्रस्तावित था। दरअसल, आंध्र में 25 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में वाइएसआर कांग्रेस को 22 तो टीडीपी को तीन पर जीत मिली, जबकि भाजपा के हाथ कुछ नहीं आया था। अब भाजपा यहां टीडीपी के साथ लोकसभा व राज्य की 175 विधानसभा सीटों पर समझौते के लिए बातचीत कर रही है। वहीं, 28 सीटों वाले कर्नाटक में फिर बड़ी जीत सुनिश्चित करने की मंशा से जेडीएस का साथ भाजपा को मिल चुका है। तो तमिलनाडु की 39 सीटों का गणित साधने के लिए एआइडीएमके के 15 पूर्व विधायकों और एक पूर्व सांसद को पार्टी में शामिल कराते हुए भाजपा अन्य छोटे दलों को साधने की जुगत में है।

जबलपुर के महापौर सहित 50 से अधिक कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल

राज्य ब्यूरो, भोपाल: मध्य प्रदेश में जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजसेवी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सभी ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि भाजपा का परिवार बड़ा हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए 'वेटिंग' चल रही है।

डूबते जहाज से सब भाग जाते हैं : प्रमोद कृष्णम

जागरण संवाददाता, मेरठ : कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि डूबते जहाज पर कोई नहीं रहना चाहता, सब भाग जाते हैं। यह बात उन्होंने पत्रकारों के रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी के राजग में शामिल होने की संभावना के सवाल पर कही। उनके पाला बदलने से किसे नुकसान होगा? इस पर बोले, यह सोचिए कि फायदा किसे होगा। बुधवार देर शाम मेरठ स्थित संघ कार्यालय शंकर आश्रम पहुंचे प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यहां उन्होंने अपने आत्मीय बंधुओं को कल्किधाम के शिलान्यास में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।

प्रमोद कृष्णम।

आइएनडीआइए को उन्होंने समाप्त प्रायः बताया। ममता बनर्जी के बयानों के बाद यह और स्पष्ट हो गया है। सपा के लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने पर कहा कि अखिलेश भी चाहते हैं कि भाजपा एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीते।

उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता को लेकर उठाए गए कदम पर कहा कि यह देशहित में है, इसका स्वागत करते हैं। इससे पहले खरखौदा में एमएस हैरिटेज स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पुराणों में लिखा है कि कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में संभल की धरती पर आएंगे।

केजरीवाल की महारैली को देख कांग्रेस ने कन्वेंशन को शक्ति प्रदर्शन में बदला

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

- 11 फरवरी को खरगे समराला में तो केजरीवाल खडूर साहिब में ठोकेंगे ताल
- कार्यक्रम में लाने के लिए 44 हजार लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है

अरविंद केजरीवाल।

मल्लिकार्जुन खरगे।

पंजाब की राजनीति में 11 फरवरी का दिन राजनीतिक रूप से रोचक रहने वाला है। इस दिन दो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। आप सुप्रीमो व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महारैली को देख कांग्रेस ने अपनी कन्वेंशन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में बदल दिया है।

कांग्रेस ने समराला में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उपस्थिति में होने वाली पहली कन्वेंशन में प्रदेश से लेकर मंडल कमेटी सदस्यों को बुलाने का निर्णय किया था, लेकिन आप की महारैली को देख अब पार्टी शक्ति प्रदर्शन के मूड में आ गई है। कांग्रेस ने कन्वेंशन के लिए प्रदेश से लेकर मंडल कमेटी तक के 38,667 कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार भी की थी लेकिन अब इस नीति में बदलाव किया जा रहा है।

कांग्रेस ने अब समराला के आसपास के जिलों लुधियाना, जालंधर, मोगा आदि से ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कन्वेंशन स्थल पर लाने का फैसला किया है। इसके लिए 44 हजार लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। कन्वेंशन में 50 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं को समराला लाने की तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने यह रणनीति 11 फरवरी को ही केजरीवाल द्वारा खडूर साहिब में रखी गई महारैली को देखते हुए अपनाई है। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि रैली में उपस्थित भीड़ से 2024 के लोकसभा चुनाव की राह निकलेगी। अहम बात यह है कि आइएनडीआइए घटक दल कांग्रेस और आप के बीच पंजाब में गठबंधन की संभावना खत्म होती नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस शुरू से ही गठबंधन का विरोध कर रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री व पंजाब में आप के प्रदेश प्रधान भगवंत मान ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद दोनों ही पार्टियां पंजाब में एक-दूसरे के खिलाफ उतर आई हैं। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान भारत भूषण आशु का कहना है कि हमारा पूरा फोकस कन्वेंशन पर है। कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह पाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पंजाब कांग्रेस में अभी फूट पड़ी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू सहित अन्य कई नेता भी प्रदेश प्रभारी का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है।

सीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कर्नाटक के भाजपा नेता गिरफ्तार

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में बुधवार को भाजपा विधायकों को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के नेतृत्व में भाजपा विधायकों और नेताओं ने विधान सौध (कर्नाटक का राज्य विधानमंडल और सचिवालय परिसर) के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर मार्च किया। उस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। भाजपा ने वित्तीय न्याय की लड़ाई के लिए सिद्दरमैया के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल द्वारा बुधवार को दिल्ली में आयोजित धरने का विरोध करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए भाजपाइयों ने सूखा प्रभावित किसानों को राहत और दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने में विफल रहने के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा करते हुए नारेबाजी की।

मोदी के बयान को हथियार बना राहुल ने भाजपा-बीजद पर बोला हमला

जागरण संवाददाता, राउरकेला

- राउरकेला में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल बोले-भाजपा-बीजद में पार्टनरशिप
- ओडिशा के 30 लाख युवा रोजगार के लिए भटक रहे, मित्र नीति के तहत राज्य को लूट रहे हैं 30 अरबपति

ओडिशा के राउरकेला में बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वेद व्यास मंदिर में पूजा-अर्चना की। प्रेट्र

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को ओडिशा के राउरकेला में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को हथियार बनाकर भाजपा और बीजू जनता दल पर हमला बोला। पिछले दिनों ओडिशा दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपना मित्र बताया था। इसी बयान को लपकते हुए राहुल गांधी ने राउरकेला के पानपोष स्थित गांधी चौक पर जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा-राज्य में नवीन पटनायक और नरेन्द्र मोदी की पार्टरनशिप की सरकार चल रही है। दोनों मिले हुए हैं। एक साथ काम करते हैं। यह संसद में भी देखने को मिलता है। जब भी भाजपा को संसद में मदद की जरूरत होती है, बीजद मदद करता है। ओडिशा की जनता के लिए अकेले कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है।

राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह हर प्रदेश की बीमारी है। ओडिशा के 30 लाख से अधिक युवा नौकरी के लिए अन्य राज्यों में भटक रहे हैं। मोदी मित्र नवीन पटनायक के संरक्षण में बाहर से आए 30 अरबपति उद्योगपति ओडिशा के संसाधनों को लूट रहे हैं। रेल, सेल, पोर्ट, एयरपोर्ट समेत कांग्रेस द्वारा बनाए गए देश के बड़े-बड़े पीएसयू आज मोदी की 'मित्र नीति' के तहत बेचे जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है जीएसटी में सुधार कर छोटे उद्योगों के लिए एक नया आर्थिक माडल तैयार करना, निजीकरण को रोकना, पीएसयू को फिर से जीवित करना और खाली पड़े सरकारी पदों को भरना। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा-भाजपा देश भर में नफरत फैला रही है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। उनके साथ राज्य प्रभारी डा. अजय कुमार व प्रदेश अध्यक्ष शरत पटनायक थे।

तोल-मोल

नेशनल कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर बोले- सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक गठबंधन के बीच कोई चर्चा नहीं हुई, कहा- चर्चा के लिए तैयार, पर जम्मू, ऊधमपुर व लद्दाख सीट पर होगा विचार विमर्श

नेकां आइएनडीआइए से उन सीटों पर बात करेगी जो भाजपा के पास

राज्य ब्यूरो, जम्मू

नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) जम्मू कश्मीर में उन लोकसभा सीटों पर समझौता करने के कतई मूड में नहीं है, जिन्हें उसने वर्ष 2019 के चुनाव में जीता था। नेकां उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाले आइएनडीआइए से लोकसभा की सिर्फ उन सीटों पर ही बात होगी जो भाजपा के पास हैं। इनमें जम्मू कश्मीर की दो और लद्दाख की एक सीट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक आइएनडीआइए के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि, कांग्रेस बातचीत के लिए तैयार है और हमसे बात करना चाहती है। आने वाले दिनों में आपस में विचार-विमर्श होगा विशेषकर जम्मू, ऊधमपुर और लद्दाख की संसदीय सीटों के लिए जो भाजपा के पास हैं।

जम्मू में पार्टी मुख्यालय शेर-ए-कश्मीर भवन में पत्रकारों से बातचीत में उमर ने कहा कि वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस ने श्रीनगर, बारामुला और अनंतनाग लोकसभा सीट जीती थी। उस समय महबूबा मुफ्ती भी गठबंधन का हिस्सा थीं। जम्मू, ऊधमपुर, लद्दाख सीट पर भी हमने पहले चुनाव लड़ा था। हमने एक बार जम्मू की सीट और एक से अधिक बार लद्दाख की सीट जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे और फार्मूला पर विचार विमर्श करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भाजपा के हैं वह कांग्रेस के पास आए। उन्होंने कहा कि नेकां ने जो सीटें 2019 में जीती थीं, वह आइएनडीआइए का ही हिस्सा था। गठबंधन के बीच कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई उन सीटों पर है, जो भाजपा के पास हैं इसलिए जम्मू कश्मीर में आइएनडीआइए के पास तीन सीटें हैं। हम सिर्फ उन तीन सीटों पर बात करेंगे जो भाजपा के पास है।

उमर अब्दुल्ला। फाइल

2019 में नेकां ने जो सीटें जीती थीं, वह आइएनडीआइए का ही हिस्सा था, गठबंधन के बीच कोई लड़ाई नहीं

हालात सुधरने के दावों पर भी सवाल

जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने के भाजपा के दावों पर नेकां उपाध्यक्ष ने राजौरी और पुंछ की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि मैंने इन दो जिलों में हुए ऐसे आतंकी हमले इससे पहले कभी नहीं देखे। हमारे कई जवान बलिदान हुए हैं। पिछले दो वर्षों में कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है और सरकार कह रही है कि आतंक पर अंकुश लगाया है।

भाजपा के 370 प्लस के लक्ष्य पर कसा तंज

जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने की संभावना के सवाल पर उमर ने कहा कि भाजपा के पास हिम्मत नहीं है कि यहां विधानसभा के चुनाव करवाए। भाजपा लोगों का सामना नहीं कर सकती। भाजपा ने अनुच्छेद 370 को हटाया, विधानसभा का परिसीमन किया, सभी कानूनों में बदलाव किया, राम मंदिर बनाया। भाजपा के 370 प्लस सीटों के लक्ष्य पर उमर ने तंज कसा कि यह सिर्फ नंबर है, लेकिन यह हैरानी है कि 10 साल के शासन के बाद उन्होंने (भाजपा) यह लक्ष्य 500 सीटों से अधिक क्यों नहीं रखा।

मप्र से लोस प्रत्याशियों की सूची में नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल भी

राज्य ब्यूरो, भोपाल

- भाजपा चुनाव समिति की बैठक में छह संसदीय सीटों के दावेदारों पर चर्चा

मध्य प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा की जिन छह संसदीय सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई, उनमें उन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों के नाम भी शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। जबलपुर से राकेश सिंह, दमोह से प्रहलाद पटेल, सीधी से रीति पाठक, ग्वालियर-चंबल संभाग से नरेंद्र सिंह तोमर व विष्णुदत्त शर्मा के नाम भी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई। कहा गया कि कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा का परचम फहराने के लिए चौहान को प्रत्याशी बनाया जाए। बता दें कि विधानसभा चुनावों में पार्टी ने तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत सात सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें एक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते व एक सांसद गणेश सिंह चुनाव हार गए थे। सरकार बनने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अब इन्हें फिर लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। बता दें कि प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 भाजपा के पास हैं। एक मात्र छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस नेता कमल नाथ के पुत्र नकुल नाथ सांसद हैं। छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है।

****

12 फरवरी को ज्ञानवापी में अतिरिक्त सर्वे की मांग पर सुनवाई होगी। 1991 में पं. सोमनाथ व्यास व अन्य की ओर से दाखिल मुकदमे में वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी में अतिरिक्त एएसआइ सर्वे कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।

कनिंघम की गवाही, ईदगाह में 'केशवराय'

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामला

विनीत मिश्र, मथुरा

- आर्केलाजिकल सर्वे आफ इंडिया पुस्तक में मिलता है उल्लेख
- 1862-65 के बीच हुए पहले सर्वे को दिया पुस्तक का रूप
- एएसआइ के संस्थापक और पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम

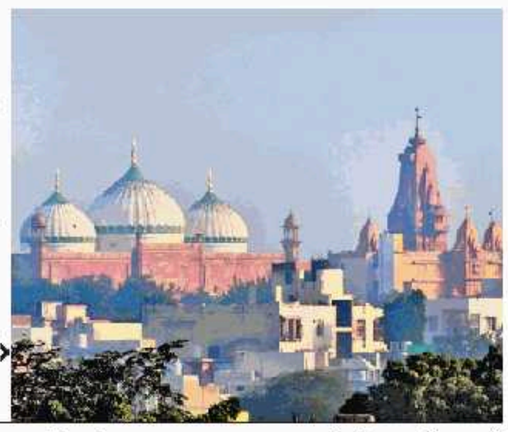

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह। जागरण आर्काइव

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में एएसआइ के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के निष्कर्ष को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने ही 1862 से 1865 के बीच शाही मस्जिद ईदगाह का पहला सर्वे किया था। यहां एक खंभे पर उन्हें केशवराय लिखा मिला। इस सर्वे का विस्तृत विवरण 'आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया' पुस्तक में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में इस पुस्तक को प्रस्तुत किया जाएगा। हिंदू पक्ष का मानना है कि ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमीशन सर्वे कराने की उनकी मांग के पक्ष में यह बड़ा साक्ष्य होगा।

बता दें, ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप के इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। बाद में वह भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल व इतिहास के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। कनिंघम ने 1862-65 में पूरे देश में कई स्थानों का सर्वे किया था। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह भी शामिल थी। पुस्तक में शाही मस्जिद ईदगाह का उस समय का हाथ से बनाया गया एक नक्शा भी मिलता है। इसमें मस्जिद की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ ही पूरे परिसर की नापजोख अलग से दी गई है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान का वाद न्यायालय में लड़ रहे अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, पुस्तक में कनिंघम ने लिखा है कि ईदगाह में एक खंभे पर संवत् 1713 फाल्गुन लिखा है। एक अन्य खंभे पर केशवराय लिखा है। कुछ चिह्न भी मिले हैं, जो हिंदू मंदिर में होते हैं। महेंद्र प्रताप का कहना है कि ईदगाह के सर्वे को कोर्ट कमीशन नियुक्ति किए जाने की मांग को इस तथ्य से बल मिलेगा। कोर्ट कमीशन सर्वे में यहां की नापजोख होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री आदि के वाद पर शाही मस्जिद ईदगाह का कोर्ट कमीशन सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस आदेश पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ऐसे में यह पुस्तक महत्वपूर्ण साक्ष्य बनेगी। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में एक और वादी मैनपुरी निवासी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह बताते हैं कि ये साक्ष्य ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। अजय प्रताप सिंह ने एएसआइ द्वारा आरटीआइ से मिला जवाब भी प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया है कि शाही मस्जिद ईदगाह को ठाकुर केशवदेव मंदिर तोड़कर बनाया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष के नहीं, श्रीराम के बुलावे पर जाएंगे अयोध्या : अखिलेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी सरकार के सभी मंत्रियों, विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के 11 फरवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर राजनीतिक दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस संबंध में जब सदन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अखिलेश यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपके बुलावे पर नहीं, भगवान राम के बुलावे पर अयोध्या जाएंगे।'

बुधवार को विधान भवन में मीडिया की ओर से इस बारे में पूछने पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा के साथ अयोध्या जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें (विधानसभा सदस्यों को) 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी आमंत्रित नहीं किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आमंत्रित किया गया था। हम नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से अयोध्या दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए कहेंगे।

यूक्रेन युद्ध से व्यथित रूस की इन्गा ने काशी में ली तांत्रिक दीक्षा

- जन्मदिन पर बदला गोत्र, अब कहलाएंगी इन्गानंदमई मां, शांति के लिए माता सिद्धिदात्री से प्रार्थना करेंगी

वाराणसी : शिवाला स्थित वाग्योग-चेतना पीठम् में तांत्रिक दीक्षा लेतीं मास्को की इन्गा बारादोश। जागरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी

रूस की इन्गा बारादोश ने बुधवार को काशी में माता सिद्धिदात्री की तांत्रिक दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा लेने के बाद इन्गा बारादोश ने कश्यप गोत्र स्वीकार करते हुए अपना नाम इन्गानंदमई मां रख लिया। उन्होंने कहा कि दीक्षा लेने के बाद शांति महसूस कर रही हूं। रूस-यूक्रेन युद्ध से व्यथित हूं और शांति के लिए माता सिद्धिदात्री से प्रार्थना करूंगी।

मास्को की इन्गा बारादोश का बुधवार को जन्मदिन भी था। इस अवसर पर ब्रह्मलीन पद्मश्री व महामहोपाध्याय प्रो. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी उर्फ वागीश शास्त्री के चरणों में नमन करने की इच्छा लेकर काशी आई थीं। शिवाला स्थित वाग्योग-चेतना पीठम् में वागीश शास्त्री के पुत्र व पीठम् के अध्यक्ष पं. आशापति शास्त्री ने उन्हें दीक्षा मंत्र दिया। पं शास्त्री के आचार्यत्व में पं सत्यम शास्त्री, पंडित शिवप्रसाद शास्त्री व गंगा प्रसाद शास्त्री ने विधि विधान से दीक्षा दी। इन्गा ने जनवरी 2012 में गुरुदेव वागीश शास्त्री के सान्निध्य में कुंडलिनी ध्यान का अध्ययन किया था।

'व्यासजी तलगृह में 1993 से पूर्व किसका कब्जा, यह साफ हो जाए तो फैसला'

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दूसरे दिन भी ढाई घंटे तक चली बहस, आदेश को सही-गलत बताने के पक्ष में रखे तर्क

मस्जिद पक्ष को आदेश की प्रति 24 घंटे में दाखिल करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तलगृह पर 1993 से पहले किसका कब्जा था, यह तथ्य अहम हो चला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि 1993 से पहले किसका कब्जा था, यह साफ हो जाए तो फैसला हो जाएगा। कोर्ट में बुधवार को ढाई घंटे तक चली बहस के बाद भी पूजा संबंधी जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई अधूरी रही। अब 12 फरवरी को सुबह 10 बजे से सुनवाई होगी। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी (मस्जिद पक्ष) के अधिवक्ता ने बताया कि जिला जज के आदेश की प्रमाणित प्रति मिल गई है। कोर्ट ने इसे 24 घंटे में दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई शुरू होते ही मंदिर पक्ष से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये अधिवक्ता हरिशंकर जैन व कोर्ट में उपस्थित विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा।

उन्होंने जिला जज के आदेश को सही बताया। कहा, वादी का व्यासजी के तलगृह में भौतिक कब्जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों व वादी की तरफ से 28 नवंबर, 2014 को ताला खोलकर तलगृह से जितेंद्र नाथ व्यास की मौजूदगी में सामान निकाला गया। पांच नवंबर, 2016 को रामचरितमानस पाठ का सामान रखा गया। एक चाबी व्यास व दूसरी प्रशासन के पास रहती थी। हालांकि यह बात ट्रायल कोर्ट की पत्रावली पर नहीं है। रामायण पाठ किया गया था।

मंदिर पक्ष का दावा

मंदिर पक्ष का कहना था कि सीआरपीसी की धारा 151 व धारा 152 को एक साथ देखा जाएगा, इसमें कोर्ट को अंतर्निहित शक्ति है। धारा 152 में आदेश देते समय कुछ छूट गया है तो अदालत स्वयं प्रेरणा से या अर्जी दाखिल होने पर आदेश कर सकती है। वादी अधिवक्ता द्वारा ध्यान खींचने पर जिला जज की अदालत ने छूटे आदेश को 31 जनवरी को पारित किया। यह आदेश दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया। विपक्षी ने कोई आपत्ति नहीं की। तलगृह में 68 साल से रामायण पाठ हो रहा था। 1993 में बैरिकेडिंग के बाद रोक दिया गया। फिर भी वादी का कब्जा रहा है। जैन ने कहा, जिला अदालत का आदेश विधि सम्मत है।

विष्णु शंकर जैन।

मस्जिद पक्ष ने दिया तर्क

मस्जिद पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी व पुनीत गुप्ता ने जिला जज के आदेश को अधिकार क्षेत्र के बाहर का बताया। कहा, जिला जज ने विधि प्रक्रिया के खिलाफ आदेश दिया है, इसे रद किया जाए। नकवी ने कहा, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट कानून केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी में जिलाधिकारी पदेन सदस्य हैं। उन्हें रिसीवर नियुक्त कर विरोधाभासी कार्य का आदेश दिया गया है। यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है। जिला जज ने 31 जनवरी का आदेश स्वयं नहीं दिया है और ऐसा आदेश जारी करने के लिए उनके समक्ष कोई अर्जी नहीं दी गई। जिला जज ने पूजा अधिकार देकर आधा वाद स्वीकार कर लिया है, इसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है। आदेश पारित करते समय धारा 152 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

एसएफए नकवी।

भूल सुधार या छूटी मांग पर आदेश देने का अधिकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट। फाइल

कोर्ट ने कहा, धारा 151 व धारा 152 एक साथ देखी जाएगी। इसमें भूल सुधार या छूटी मांग पर अदालत को आदेश देने का अधिकार है। वह स्वयं या अर्जी पर दे सकती है। नकवी ने दीन मोहम्मद केस व काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट एक्ट केस का हवाला देते हुए कहा कि जिला जज ने 17 जनवरी का आदेश देकर प्रांगन्याय (रेसजुडीकेटा) का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र से 1993 में बैरिकेडिंग लगाने संबंधी आदेश के बाबत जानकारी मांगी।

अयोध्या के लिए 150 पर्यटक गाइडों की टीम तैयार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अयोध्या के लिए पर्यटक गाइडों की टीम तैयार हो गई है। पर्यटन विभाग द्वारा जल्द ही प्रमाण पत्र जारी करके इन्हें अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही है। मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान (एमकेआइटीएम) द्वारा इनका प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। अयोध्या के लिए प्रशिक्षित किए गए गाइडों में अयोध्या सहित दूसरे जिलों के 150 युवाओं को शामिल किया गया है। इन्हें अयोध्या और आसपास के पर्यटक स्थलों के इतिहास सहित अन्य जानकारी दी गई है। अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद इस वर्ष से पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि होना तय है। इसी के मद्देनजर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक गाइडों की टीम तैयार की गई हैं। अयोध्या भ्रमण करवाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए गाइडों को हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं की भी जानकारी दी गई है।

सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने रामलला को किया नमन

सूरीनाम से आए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे वहां की नेशनल असंबेली के स्पीकर मरीनस बेई (मध्य में) को राममंदिर की अनुकृति भेंट करते एडीएम सिटी सलिल कुमार पटेल (मध्य में दाएं) एवं एसडीएम सदर राजकुमार पांडेय (दाएं से चौथे): जागरण

जासं, अयोध्या

अयोध्या में नवनिर्मित और भव्य मंदिर में विराजे रामलला को देश ही नहीं दुनिया भी शिरोधार्य कर रही है। मंगलवार को अरुणाचल सरकार के नतमस्तक होने के बाद बुधवार को सूरीनाम देश का प्रतिनिधिमंडल रामलला के दरबार में नतमस्तक हुआ। सूरीनाम की नेशनल असेंबली के स्पीकर मरीनस बेई के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल में नेशनल असेंबली के सदस्य रबींद्र परमेसर, आसीस कुमार जादेन, महिंदर कुमार जोगी, राय मोहन, निशा झाकरी एवं रेशमा मांगरे सहित स्पीकर के सलाहकार रविन सोइराजबली, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्टीवन ईश्वरदत्त शामिल रहे। सूरीनाम के प्रतिनिधियों ने रामलला और बजरंगबली के दर्शन-पूजन के बाद रामनगरी में आगमन को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और याद दिलाया कि हमारे पूर्वज डेढ़ सौ साल पहले रामनगरी के आसपास सहित पूर्वांचल की ही भूमि से सूरीनाम गए थे। प्रतिनिधिमंडल भारत के लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला के आमंत्रण पर चार फरवरी से ही भारत की यात्रा पर है और दिल्ली, आगरा, लखनऊ होते हुए बुधवार को रामनगरी पहुंचा।

मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों के लिए शुरू होगी हेलीकाप्टर सेवा

राज्य ब्यूरो, भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार से शुरू हुए बजट सत्र में राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार का रोडमैप बताया। इसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश के तीर्थ स्थलों के लिए सरकार हेलीकाप्टर सेवा शुरू करेगी। इंदौर से उज्जैन व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जबलपुर से चित्रकूट, ग्वालियर से ओरछा और पीतांबरा पीठ के लिए हवाई यात्रा की सुविधा शुरू की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि यह नए भारत, विश्व मित्र भारत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण और हर क्षेत्र में अग्रणी मध्य प्रदेश को गढ़ने का समय है। सरकार प्रदेश के चौतरफा विकास और जन कल्याण की नीतियां बना रही है और निर्णय भी ले रही है। संकल्प-पत्र के क्रियान्वयन पर काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पर्यटन स्थालों के लिए मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा योजना के साथ एयर एंबुलेंस सेवा प्रारंभ होगी।

हिंदू पक्ष के दावों के आगे धराशायी हुए मुस्लिम पक्ष के तर्क

जागरण संवाददाता, बागपत

53 साल आठ महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हिंदू पक्ष ने अदालत में महाभारतकालीन लाक्षागृह को लेकर बड़ी जीत हासिल कर ली। 1970 में वाद दायर होने के बाद से ही हिंदू पक्ष ने अदालत में ठोस साक्ष्य पेश किए, जबकि मुस्लिम पक्ष अपने दावों पर खरा नहीं उतर सका। उसने जो साक्ष्य पेश किए, उनके बारे में भी पुख्ता जानकारी अदालत को नहीं दे सका।

मुस्लिम पक्ष न तो यह बता सका कि जब प्राचीन टीले पर मानव की अस्थियां मिली तो उनकी कार्बन डेटिंग क्यों नहीं कराई गई? न ही टीले के कोने-कोने में कब्रें होने का पुख्ता सबूत दे सका। दूसरी तरफ, हिंदू पक्ष ने न केवल कमीशन की रिपोर्ट पेश की, बल्कि सरधना तहसील और एएसआइ की साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। बता दें, पांच फरवरी को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने प्राचीन टीले पर फैसला सुनाया, जिसमें उसे महाभारतकालीन लाक्षागृह ही माना।

- दावों पर अदालत में खरा नहीं उतर सका मुस्लिम पक्ष

इन साक्ष्यों से हिंदू पक्ष को मिली जीत

- तत्कालीन संयुक्त प्रदेश सरकार की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 25 नवंबर 1920 व 27 दिसंबर 1920 के अनुसार प्राचीन पुरातत्व संरक्षण अधिनियम 1904 के अनुसार मेरठ से 19 मील उत्तर-पश्चिम में स्थित टीले को लाखामंडप प्राचीन पुरातत्व के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद एसडीओ सरधना के आदेश पर चार मार्च 1965 में विवादित भूमि को लाखा मंडप दर्ज किया।
- अदालत में कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें संपूर्ण टीला प्राचीन व टूटे हुए मिट्टी के पात्रों के अवशेष, विशेष प्रकार की मिट्टी से बने होने बताए गए। इन्हीं आधार पर प्राचीन टीले को लाखा मंडप कहा गया था। टीले को महाभारतकालीन प्राचीन अवशेष भी बताया गया था। रिपोर्ट में दीवार का भी उल्लेख था। कमीशन रिपोर्ट को विशेष साक्ष्य माना गया।

यहां पड़ गया कमजोर

- कमीशन की रिपोर्ट में टीले की सतह विशेष प्रकृति के मिट्टी के पात्र व बहुत प्राचीन कंक्रीट की ईंट से बनी होना बताया व टूटे हुए मिट्टी के मटके में मानव अस्थि प्राप्त होना बताया, लेकिन वादी मुकीम खां ने अस्थियों की न तो कार्बन डेटिंग कराई और न ही वैज्ञानिक विधि से अस्थियों की आयु पता लगाने का प्रयास किया।
- मुस्लिम पक्ष ने विवादित जगह पर 600 साल पुराना मकदूम शाह विलायत का मजार होना, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना व उसका मुतवल्ली होना बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा धारा-30, अधिनियम, 1960 में संरक्षित पंजिका क्यों नहीं प्रस्तुत की और न ही यह स्पष्ट किया कि 1920 में जारी अधिसूचना के विरुद्ध क्या आपत्ति की?
- गवाह मजहर अहमद ने अपनी गवाही में विवादित जमीन के कोने-कोने में कब्रें होने का बयान दिया है, जो कि पत्रावली पर लगी आयुक्त की आख्या व मानचित्र के अनुसार सही नहीं प्रतीत होता है।

अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद की पहली ईंट मक्का-मदीना से पवित्र होकर पहुंची मुंबई

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- इसे मक्का स्थित झरना जम-जम के जल और मदीना में इत्र से धोने के लिए भेजा गया था

अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद की नींव के लिए पहली ईंट मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा के बाद बुधवार को मुंबई पहुंची। यह ईंट मुंबई में पकाई गई थी। इसे मक्का स्थित झरना जम-जम के जल और मदीना में इत्र से धोने के लिए भेजा गया था। यह ईंट मध्य अप्रैल के आसपास अयोध्या के धन्नीपुर गांव में पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में नामित नई मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद तक पहुंचने वाली है। यह ईंट मुंबई की काली मिट्टी से बनाई गई है, जिसे कुरान के शिलालेखों से सजाया गया है और पांच मुसलमानों द्वारा की गई पवित्र तीर्थयात्रा के बाद एक समारोह में लाई गई गई। **मस्जिद का निर्माण संभवत:** रमजान और ईद-उल-फितर के बाद शुरू होगा। ईंट की शुभ यात्रा इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्य और मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला विकास समिति के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख के घर से शुरू होगी। हाजी अराफात शेख का कहना है कि नई मस्जिद और उसके निकट बनने वाला अस्पताल भारत में प्रार्थना और उपचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है जो इस्लाम के पांच सिद्धांतों के आधार पर बनाई जाएगी, जिसके लिए पांच प्रतीकात्मक मीनारें बनाई जाएंगी, जो 11 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दिखाई देंगी।

अराफात शेख ने बताया कि मुंबई से अयोध्या तक इस पवित्र ईंट की यात्रा की शुरुआत एक भव्य जुलूस के रूप में शुरू होगी। यह जुलूस मुंबई में कुर्ला उपनगर से शुरू होकर मुलुंड तक निकाला जाएगा। फिर यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक जाएगा। रास्ते में हर 300 किलोमीटर पर प्रार्थनाओं और लोगों के सम्मान के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

वित्तीय हिस्सेदारी का आरोप लगा केंद्र के खिलाफ मुखर हो रहे विपक्षी राज्य

नई दिल्ली में बुधवार को जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एवं अन्य। प्रेट्र

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- सिद्दरमैया के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने किया विरोध-प्रदर्शन
- आज केरल के सीएम विजयन अपने दल-बल संग केंद्र पर डालेंगे दबाव

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य केंद्रीय करों में वाजिब वित्तीय हिस्सेदारी को मुद्दा बना रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की अगुआई में राजधानी दिल्ली में बुधवार को राज्य की पूरी सरकार के साथ कांग्रेस विधायकों-सांसदों ने वाजिब हिस्सेदारी की मांग करते हुए केंद्र सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर इस मुद्दे को गरम कर दिया। कर्नाटक की ओर से उठाई गई आवाज के सुर अभी धीमे भी नहीं पड़े कि केरल की वाममोर्चा गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपने लाव-लश्कर के साथ राज्य का हिस्सा देने का दबाव बनाने के लिए राजधानी पहुंच चुके हैं। विजयन की अगुआई में केरल सरकार के मंत्री और उनके सांसद-विधायक गुरुवार को दिल्ली में अपनी हिस्सेदारी देने की आवाज उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी राज्यों का हिस्सा नहीं देने का सवाल उठाते हुए पिछले काफी समय से केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं।

संसद के पिछले सत्र में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने दिल्ली पहुंचकर मनरेगा के अटके पैसे समेत वित्तीय सहायता रोकने को लेकर केंद्र के विरुद्ध आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया था। मगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक की सिद्दरमैया सरकार द्वारा राज्य को अपेक्षित वित्तीय हिस्सेदारी नहीं देने के सवाल पर बुधवार को किए गए विरोध प्रदर्शन ने इस विवाद का आयाम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने केंद्रीय करों में वाजिब हिस्सा नहीं मिलने और कई केंद्रीय अनुदानों में कटौती की बात उठाते हुए कहा कि बीते छह वर्षों के दौरान कर्नाटक को इसकी वजह से 1.87 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। केरल सरकार की ओर से राज्य के हक की लड़ाई के लिए गुरुवार को किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री विजयन ने भी आरोप लगाया कि हमारे संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों को कमजोर करने के प्रयास हो रहे हैं जिसके विरुद्ध खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करने का समय आ गया है। विजयन ने उत्तर-दक्षिण विवाद को भी हवा देने की कोशिश की और कहा कि केंद्र सरकार दक्षिणी राज्य केरल को उसके इतिहास के सबसे खराब वित्तीय संकट की ओर धकेल रही है।

द्रमुक शासित तमिलनाडु भी केंद्र पर वित्तीय अनदेखी को लेकर सवाल दागता रहा है। स्टालिन ने केंद्र पर संविधान के अनुच्छेद-293 के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके राज्यों के उधार लेने के विकल्पों में भी रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया।

समान नागरिक संहिता को लेकर राजस्थान में भी कसरत शुरू

जागरण संवाददाता, जयपुर

- उत्तराखंड के विधेयक का अध्ययन करने के बाद ड्राफ्ट तैयार करने पर विचार कर रही सरकार

भजन लाल शर्मा। फाइल

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में कसरत शुरू कर दी है। सरकार उत्तराखंड के विधेयक का अध्ययन करने के बाद ड्राफ्ट तैयार करने पर विचार कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मंत्रियों व अधिकारियों की कमेटी गठित की जाएगी। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के विधेयक का अध्ययन करने के लिए शिक्षामंत्री मदन दिलावर और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी। दिलावर और प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड के विधेयक का अध्ययन करने के बाद उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। दिलावर ने कहा कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इससे संबंधित ड्राफ्ट पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

प्रदेश के गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारी विवाह और लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर कठोर प्रविधान के पक्ष में हैं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि प्रत्येक विवाह का पंजिकरण संबंधित अधिकारी के समक्ष होना आवश्यक हो। साथ ही लिव-इन में रहने वालों के लिए पंजिकरण अनिवार्य किया जाए, चाहे वे प्रदेश के बाहर के ही मूल निवासी क्यों न हों। उनके अभिभावकों को भी सूचित किया जाना चाहिए।

समान नागरिकता संहिता के रूप में बन रहा कानून किसी के विरुद्ध नहीं : धामी

प्रथम पृष्ठ से आगे

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ने इस समानता के कानून को लागू करने की प्रेरणा दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान नागरिकता संहिता के रूप में बन रहा कानून किसी के विरुद्ध नहीं है। महिलाओं को कुरीतियों और रुढिवादी प्रथा से दूर करते हुए सर्वांगीण उन्नति में इससे सहायता मिलेगी।

भगवान श्रीराम पर टिप्पणी से गर्माया सदन: समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन तब गर्मा गया, जब कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कहा, 'भगवान राम सांवले थे, लेकिन उन्हें काला कर दिया गया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई।

समान नागरिक संहिता के मुख्य प्रविधान

- विवाह का पंजीकरण अनिवार्य। पंजीकरण न होने पर सरकारी सुविधाओं से होना पड़ सकता है वंचित।
- पति-पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित।
- सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित।
- वैवाहिक दंपती में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे पक्ष की सहमति के अपना मत परिवर्तन करता है तो दूसरे पक्ष को उससे तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा।
- पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक का बच्चा माता के पास रहेगा।
- सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार।
- सभी धर्म-समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटे-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार।
- मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत पर रोक।
- संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं, नाजायज बच्चों को भी उस दंपती की जैविक संतान माना गया है।
- लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी।
- लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चे को युगल की जायज संतान माना जाएगा और उसको जैविक संतान के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

****

4 दिवसीय सम्मेलन में तीन दिन मौजूद रहेंगे संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत मुरैना में हो रहे आरएसएस के प्रांतीय सम्मेलन में। मुरैना के पास सुंदरपुर में कार्यक्रम स्थल तैयार किया गया है, जिसे अयोध्याधाम नाम दिया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 फरवरी, 2024

हेमंत ने किया सत्ता का घोर दुरुपयोग

दलील ▶ रिमांड याचिका में ईडी ने लगाए गंभीर आरोप, वाट्सएप चैट में धन उगाही की बातें

कहा- ईडी ने जांच शुरू की तो प्रशासन ने शुरू कर दी जमीन वापसी की प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, रांची

जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पांच दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने उन्हें फिर पांच दिनों के रिमांड पर लिया है। बुधवार को पीएमएलए कोर्ट में दाखिल रिमांड याचिका में ईडी ने हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का आरोप है कि हेमंत ने न सिर्फ दस्तावेज में हेरफेर कर गलत तरीके से रांची में 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया, बल्कि सत्ता का घोर दुरुपयोग कर मनमाने तरीके से ट्रांसफर-पोस्टिंग कर भारी धन की उगाही की।

ईडी ने दावा किया है कि कुछ वाट्सएप चैट में इस बात के संकेत मिले हैं कि हेमंत सोरेन कुछ अधिकारियों से हर माह अवैध धन की वसूली करते थे। चैट का विवरण 503 पन्नों में दर्ज है। ईडी ने हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच हुए कुछ वाट्सएप चैट भी प्रस्तुत किए, जिनमें ट्रांसफर-पोस्टिंग के एवज में लेनदेन का उल्लेख है। हेमंत की पेशी के दौरान सिविल कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुट गए थे। उन्होंने हेमंत के समर्थन में नारे लगाए, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई।

रांची सिविल कोर्ट परिसर में पेशी के लिए ले जाए जाते झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (बीच में), साथ में सुरक्षा में तैनात जवान तथा अन्य लोग। जागरण

ईडी ने अदालत को बताया है कि हेमंत सोरेन ने पावर का गलत इस्तेमाल किया और इस केस से संबंधित साक्ष्य को नष्ट करने की भी कोशिश की। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में आठ अगस्त, 2023 को पहला समन किया गया था और उन्हें 14 अगस्त को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 16 अगस्त को रांची के बड़गाई अंचल के सीओ (अंचलाधिकारी) को राज कुमार पाहन ने एक आवेदन दिया कि जमीन उनके कब्जे में है, लेकिन कुछ लोगों ने अवैध तरीके से उक्त जमीन की जमाबंदी (दाखिल-खारिज) करा ली है। इसके बाद जांच व कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई और अंतिम रूप से 29 जनवरी, 2024 को एसएआर (स्पेशल एरिया रेवेन्यू) कोर्ट ने अंतिम रूप से राजकुमार पाहन को उक्त जमीन का मालिकाना हक दे दिया। उस वक्त ईडी की दिल्ली में छापेमारी चल रही थी। ईडी ने इस पूरी प्रकिया पर सवाल उठाए हैं।

हेमंत के आवास में मिली थी भानु प्रताप प्रसाद की चार्जशीट : बड़गाईं की उक्त विवादित जमीन से संबंधित मामले में 12 जून 2023 को भानु प्रताप प्रसाद के विरुद्ध ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी। दाखिल चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से मिले थे। ईडी ने कहा कि यह साबित करता है कि सोरेन उक्त जमीन से संबंधित अनुसंधान से अवगत थे।

हेमंत बोले-मुझे अंधेरे बेसमेंट में रखा है, वाट्सएप चैट से कोई संबंध नहीं

पेशी के दौरान हेमंत सोरेन ने कोर्ट को बताया कि रिमांड पर पूछताछ के दौरान उन्हें ईडी के अधिकारी एक बेसमेंट में रखते हैं, जहां कोई खिड़की नहीं है। रोशनदान अथवा पाइप के सहारे आक्सीजन दिया जा रहा है। उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कहा कि ईडी की पूछताछ के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री को अच्छी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। जिस केस में उन्हें रिमांड पर लिया गया है, उस केस में ईडी अभी तक कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई है। ईडी जिस चैट का जिक्र कर रही है वह 2020 का है। इस मामले से इस चैट का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा जमीन से संबंधित मामले में ईडी पूर्व में ही सीएम से लगातार आठ घंटे पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में अब रिमांड पर देने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

विवाह की वर्षगांठ पर कल्पना ने लिखा, मैं उनके संघर्ष की शक्ति बनूंगी

राज्य ब्यूरो, रांची

▶ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का भावुक पोस्ट, एक्स पर लिखा, हेमंत ने झुकना नहीं किया स्वीकार

कल्पना सोरेन शादी की 18वीं वर्षगांठ पर पति व झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मिलने बुधवार को रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय पहुंचीं। वह करीब 15 मिनट तक पति के पास रहीं। कल्पना ने इस मौके पर हेमंत सोरेन के फेसबुक वाल और एक्स हैंडल पर भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है, 'झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंतजी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, लेकिन हेमंत सोरेन परिवार के बीच नहीं हैं। बच्चों के साथ नहीं हैं। विश्वास है कि वह इस षड्यंत्र को हरा विजेता बनकर हम सभी के साथ शीघ्र होंगे। मैं एक वीर झारखंडी योद्धा की जीवन साथी हूं। आज के दिन मैं भावुक नहीं होऊंगी। हेमंतजी की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी।'

हेमंत की आइडी से पोस्ट किए गए इस संदेश के नीचे कल्पना सोरेन ने अपना पूरा नाम कल्पना मुर्मू सोरेन लिखा है। एक अन्य पोस्ट में कल्पना सोरेन ने लिखा है कि जब तक झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेनजी केंद्र सरकार और भाजपा के षड्यंत्र को परास्त कर हम सब के बीच नहीं आ जाते, तब तक उनका यह एकाउंट, मेरे, यानी उनकी जीवनसाथी कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा चलाया जाएगा।

16 को होगा चम्पाई मंत्रिमंडल का विस्तार, कांग्रेस में कलह

झारखंड के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। बुधवार को इसकी तिथि पुनर्निर्धारित की गई। दिन में राज्यपाल की तरफ से आठ फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार की स्वीकृति दी गई थी। इस बीच मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए जहां लाबिंग तेज हो गई है, वहीं झामुमो और कांग्रेस के रणनीतिकार नाम फाइनल करने में लगे हुए हैं। मंत्री बनने के लिए कांग्रेस में ज्यादा किचकिच है। झामुमो में ज्यादा खींचतान नहीं है। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई दुमका के विधायक बसंत सोरेन या भाभी जामा की विधायक सीता सोरेन में से एक के लिए जगह तय है। इसके अलावा संताल परगना क्षेत्र से आने वाले वरीय विधायकों को जगह देने पर विचार चल रहा है। इस बात पर भी दबाव दिया जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में शामिल रहे मंत्रियों को बदला जाए। अगर यह कारगर हुआ तो तीन नए चेहरे दिखेंगे।

तमिलनाडु में तमिल बोर्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू

चेन्नई, प्रेट्र: तमिलनाडु सरकार ने राज्यभर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और उपक्रमों के बोर्डों पर तमिल में प्रमुखता से नाम लिखवाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस अभियान को अप्रैल के अंत तक पूरा करने की व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की गई है।

इस मुद्दे पर बुधवार को हुई दूसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मंत्री एमपी स्वामीनाथन ने की जिसमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और श्रम कल्याण व कौशल विकास मंत्री सीवी गणेशन भी शामिल हुए। उन्होंने इस दिशा में दिशानिर्देश दिए कि प्रदेश में तमिल बोर्ड लगाने के अभियान को ढाई महीने में पूरा कर लिया जाए। स्वामीनाथन ने कहा कि इस विषय में तमिलनाडु वानिगर संगम के नेतृत्व में ट्रेडरों के साथ हुई पहली बैठक कामयाब रही थी। यह दूसरी बैठक है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इरोड में कुछ व्यापारियों ने दो फरवरी को अपने बोर्ड बदलकर तमिल भाषा में लिखे बोर्ड लगा भी लिए हैं। यह स्वागतयोग्य कदम है और इसी सफलता को हम पूरे प्रदेश में दोहराना चाहते हैं। उन्होंने संवाददाताओं को राज्य सरकार के एक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि सरकारी विभागों, फाइलों और इमारतों पर कुछ भी लिखने के लिए केवल तमिल भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होने व्यापारियों से अपील की है कि वह बिना किसी सरकारी आदेश के तमिल नामों के बोर्ड लगाने शुरू कर दें।

श्रीनगर में आतंकियों ने सिख युवक की गोली मारकर हत्या की

जागरण संवाददाता, श्रीनगर

▶ हमले में घायल युवक की हालत गंभीर, दोनों अमृतसर के रहने वाले

▶ मौजूदा वर्ष में अन्य राज्य के किसी व्यक्ति की यह पहली टारगेट किलिंग

आतंकियों ने बुधवार शाम एक कायराना हरकत करते हुए श्रीनगर शहर में एक सिख युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। दोनों पंजाब के अमृतसर के निवासी थे और श्रीनगर में फेरी लगाकर शाल बेचने का काम करते थे। मौजूदा वर्ष में अन्य राज्य के किसी व्यक्ति की यह पहली टारगेट किलिंग है। हमले के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। हमले के पीछे लश्कर के मुखौटा आतंकी संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का हाथ माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, 31 वर्षीय अमृतपाल सिंह व 25 वर्षीय रोहित दिन में फेरी लगाने के बाद शाम करीब सात बजे श्रीनगर के हब्बाकदल क्षेत्र के शाला कदल मोहल्ले में लौटे। दोनों ने यहीं पर किराये पर कमरा ले रखा था। जैसे ही वे मोहल्ले में पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों ने उन पर एके राइफल से करीब से गोलियां दागीं। अमृतपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित के पेट में गोलियां लगीं। दोनों को मृत समझकर आतंकी भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनकर क्षेत्र में तैनात पुलिस व सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एसएमएचएस अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने अमृतपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया और रोहित का इलाज चल रहा है।

श्रीनगर में बुधवार को आतंकियों द्वारा सिख युवक की हत्या के बाद मुस्तैद सुरक्षाकर्मी। जागरण

कश्मीर के आइजीपी वीके विरदी व सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। बता दें कि पिछले वर्ष भी आतंकियों ने शोपियां और अनंतनाग में अन्य राज्यों के कामगारों पर कई हमले किए थे।

पिछले वर्ष टारगेट हमले की प्रमुख घटनाएं

30 मई : अनंतनाग में सर्कस में काम करने वाले ऊधमपुर के एक कर्मी की गोली मारकर हत्या।

13 जुलाई : शोपियां जिले में आतंकियों के हमले में तीन मजदूर घायल हुए।

31 अक्टूबर : पुलवामा में बिहार के ईंट भट्ठा मजदूर मुकेश कुमार की हत्या।

उत्तराखंड के पूर्व मंत्री व करीबियों के ठिकानों पर ईडी के छापे

जागरण संवाददाता, देहरादून

▶ हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ कटान से जुड़ा है मामला

▶ मुख्य वन संरक्षक पटनायक के आवास से एक करोड़ से अधिक नकदी मिली, नोटों की गिनती जारी

उत्तराखंड में भाजपा की पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर कार्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में पेड़ कटान, अवैध निर्माण और जमीन धोखाधड़ी के मामले में विजिलेंस और सीबीआइ के बाद अब ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। ईडी की टीम ने बुधवार को रावत व उनसे जुड़े उत्तराखंड, चंडीगढ़ व दिल्ली एनसीआर में 16 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इस दौरान वरिष्ठ आइएफएस अधिकारी व वन मुख्यालय से संबद्ध सुशांत पटनायक व पाखरो रेंज में पेड़ कटान के आरोपित सेवानिवृत्त प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) किशन चंद के आवास पर भी छापे मारे गए। पटनायक के देहरादून स्थित आवास पर ईडी को भारी मात्रा में कैश मिला, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। पकड़ी गई धनराशि एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ईडी की 16 टीमों ने बुधवार सुबह रावत के देहरादून में डिफेंस कालोनी स्थित आवास, उनके बेटे के सहसपुर के शंकरपुर स्थित दून इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज समेत उनसे जुड़े करीबी अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों के 16 ठिकानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई रावत के निजी सचिव रहे वीरेंद्र कंडारी के दून स्थित आवास, उनके करीबी नरेंद्र वालिया के ऋषिकेश में गंगानगर स्थित अपार्टमेंट, हरिद्वार रोड पर छिद्दरवाला स्थित लक्ष्मी राणा के अमरावती पेट्रोल पंप, हरिद्वार में पूर्व डीएफओ के किशन चंद के नंद विकास स्थित आवास, काशीपुर में भाजपा के जिला मंत्री अमित सिंह के आलू फार्म स्थित आवास पर की गई। साथ ही हरक सिंह रावत के श्रीनगर गढ़वाल में श्रीकोट स्थित गहड़ के पैतृक आवास और उनके करीबियों के चंडीगढ़ व दिल्ली-एनसीआर पर भी ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की।

देहरादून स्थित डिफेंस कालोनी स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर छापेमारी के दौरान तैनात दिल्ली पुलिस के जवान। जागरण

रावत से चल रही पूछताछ, दस्तावेज जब्त : ईडी की छापेमारी के दौरान हरक सिंह रावत देहरादून की डिफेंस कालोनी स्थित आवास पर ही थे। ईडी की टीम ने उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। देर रात तक चली पूछताछ में ईडी ने उनसे कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रकरण और शंकरपुर में जमीन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गहन पूछताछ की। इस दौरान सामने आया कि दोनों ही मामले में बड़े पैमाने पर धन की उगाही की गई है, जो सीधे रूप में मनी लांड्रिंग के दायरे में आता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक शंकरपुर में की जमीन पर दून इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस स्थापित किया गया है और पैसों को रेगुलेट करने के लिए श्रीमती पूर्णा देवी ट्रस्ट बनाया गया है। देर रात तक ईडी की टीम पूर्व मंत्री रावत से पूछताछ कर रही थी। वहीं, छापेमारी के दौरान ईडी टीम ने विभिन्न ठिकानों से बड़ी संख्या में दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। उनकी जांच भी शुरू कर दी गई है।

जस्टिस अंजारिया को कर्नाटक हाई कोर्ट का सीजे बनाने की सिफारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने बुधवार को गुजरात हाई कोर्ट के जज एनवी अंजारिया को कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश (सीजे) बनाने की सिफारिश की। कलेजियम ने कहा कि 24 फरवरी को जस्टिस पीएस दिनेश कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा।

सीजेआइ के अलावा कलेजियम के अन्य सदस्यों में जस्टिस संजीव खन्ना और बीआर गवई भी शामिल हैं। कलेजियम ने कहा कि जिस तारीख को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के कारण पद छोड़ेंगे, उस दिन से जस्टिस अंजारिया की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रभावी होगी। जस्टिस अंजारिया को 21 नवंबर, 2011 को गुजरात हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। तब से वह वहीं कार्यरत हैं। जज के रूप में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने सिविल, संवैधानिक मामलों, कंपनी कानून, श्रम और सेवा मामलों में गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की।

पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी लुईस खुर्शीद के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट

जागरण संवाददाता, बरेली

▶ दिव्यांगजन के लिए उपकरण वितरण में फर्जीवाड़े का आरोप

▶ कई समन जारी होने के बाद भी कोर्ट में नहीं हुई थीं पेश

फर्जीवाड़े की आरोपित पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद समेत दो आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कई समन जारी होने के बाद भी दोनों आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हुए। जमानत भी नहीं कराई। इसके बाद बुधवार को स्पेशल कोर्ट (एमपी एमएलए) ने आदेश जारी किया। प्रकरण की सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

2017 में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ था। उस समय भोजीपुरा थाने में प्राथमिकी पंजीकृत हुई थी। इसमें डाक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट (फर्रुखाबाद) की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद व संस्था के सचिव मोहम्मद अतहर फारूकी को नामजद कराया गया था। पुलिस के अनुसार 2009-10 में संस्था ने 17 जनपदों में कैंप लगाकर दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग बांटे। विकासखंड भोजीपुरा में फर्जी मोहर, हस्ताक्षर कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। शासन ने भी मामले की जांच कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। उसके बाद कई बार समन जारी हुए। विशेष लोक अभियोजक अचिंत्य द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपित लुईस खुर्शीद निवासी गुलमोहर एवेन्यू जामिया नगर (नई दिल्ली) व अतहर फारूकी निवासी सुखदेव विहार (नई दिल्ली) का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

लुईस खुर्शीद। फाइल

शार्ट वीडियो बनाने के दौरान ट्रेन से कटकर दो दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता, पश्चिम चंपारण : बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बुधवार सुबह शार्ट वीडियो बनाने के दौरान सत्याग्रह एक्सप्रेस से कटकर दो दोस्तों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि सूरज व कन्हैया बेतिया से सुगौली की ओर जा रही मालगाड़ी का शार्ट वीडियो बना रहे थे। दोनों बगल के जिस ट्रैक पर खड़े थे, उसी पर रक्सौल से दिल्ली जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस आ गई। हेडफोन लगाने के कारण पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज नहीं सुन सके और इसकी चपेट में आने से कट गए। दोनों के शव क्षत-विक्षत हो गए।

घटना के बाद स्वजन मौके पर पहुंचे और रेल पुलिस की कार्रवाई के डर से शव के कुछ हिस्से उठाकर घर ले गए। शेष भाग बोरी में रखकर खेत में छिपा दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार्रवाई के डर से दोनों किशोरों के स्वजन घर से फरार हैं। बताया गया कि सूरज और कन्हैया कुमार अक्सर शार्ट वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट करते थे।

प्राचीन ज्ञान के जरिये समाधान सिखाएगा वनस्थली विद्यापीठ

▶ विश्वविद्यालय में की जाएगी 'चेतन नेतृत्व केंद्र' की स्थापना

▶ पंचतंत्र, गीता और रामायण से प्रेरित समाधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : राजस्थान के अग्रणी विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ ने एक 'चेतन नेतृत्व केंद्र' स्थापित करने का फैसला किया है। यहां भारत के प्राचीन ज्ञान और साहित्य जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, गीता और रामायण से प्रेरित समाधान तलाशने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि नेतृत्व केंद्र की स्थापना 'बोधशाला' के सहयोग से की जा रही है। 'बोधशाला' प्राचीन भारतीय ज्ञान की चेतना और धर्म के एकीकरण के माध्यम से शिक्षा में क्रांति लाने के लिए समर्पित संस्था है। यह केंद्र जागरूक नेतृत्व, प्रबंधन में लोकाचार, संस्कृति, स्व-प्रबंधन, उद्यमिता, कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में अनुसंधान भी किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि यह केंद्र कारपोरेट, नौकरशाही और शैक्षणिक क्षेत्रों की अग्रणी हस्तियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा।

'गुजरात के स्कूलों में गीता पढ़ाने के लिए कदम उठाएं'

गांधीनगर, प्रेट्र : गुजरात विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य की भाजपा सरकार से स्कूलों में गीता पढ़ाने के शिक्षा विभाग के हालिया फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। जहां आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस सदस्यों ने शुरू में अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन बाद में मतदान के दौरान समर्थन किया। इसके बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। राज्य शिक्षा विभाग ने पिछले साल दिसंबर में घोषणा की थी कि 'श्रीमद्भगवद्गीता' में निहित सिद्धांतों और मूल्यों को स्कूलों में कक्षा छह से 12 तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा।

विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. आरएन सिंह से मांगी रंगदारी

जागरण संवाददाता, पटना : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान रहे पद्मश्री डा. आरएन सिंह को बुधवार को दो बार फोन कर एक कुख्यात के बेटे ने रंगदारी मांगी और धमकी दी। इसके साथ ही वह बिहार में पटना के कंकड़बाग स्थित उनके आवास के बाहर पहुंच गया।

डा. आरएन सिंह की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। सिटी एसपी पूर्वी भरत सोनी ने बताया कि धमकी देने और रंगदारी मांगने की बात सामने आई है। आरोपित की पहचान भी हो चुकी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा फोन शातिर बिंदु सिंह के बेटे के नाम पर किया गया था। बिंदु सिंह की मौत हो चुकी है। पुलिस आरोपित का नाम उजागर नहीं कर रही है।

मूल रूप से सहरसा निवासी अस्थि शल्य चिकित्सक डा. आरएन सिंह पटना के कंकड़बाग स्थित पीसी कालोनी में रहते हैं।

तनाव की आशंका

लोकसभा में पहाड़ी जनजातियों व अन्य को एसटी के दर्जे का बिल पारित होन से तनाव की आशंका, राजौरी-पुंछ में ऐहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, विजय या विरोध रैली निकालने की अनुमति नहीं

अब पहाड़ी बनाम गुज्जर-बक्करवाल विवाद उठाने का प्रयास

जागरण संवाददाता, जम्मू

लोकसभा में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जनजातियों व अन्य को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने संबंधी विधेयक पारित होने व गुज्जर-बक्करवाल समुदाय के आरक्षण कोटे में कोई कटौती न करने के बावजूद जम्मू संभाग के कई जिलों में तनाव की आशंका देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजौरी और पुंछ में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने के साथ कोई भी विजय या विरोध रैली निकालने की अनुमति नहीं है। जम्मू में धारा 144 लागू करने के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर विधेयक को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बीच, नेशनल कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला में आरोप लगाया कि उन्हें आने-जाने से रोका गया।

पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दर्जे के मुद्दे पर बुधवार सुबह राजौरी और पुंछ में इंटरनेट मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की गई तो प्रशासन सतर्क हो गया। दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद करने के साथ ही बाजारों, चौराहों में पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया है। जम्मू में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधेयक के पारित होने के बाद कुछ लोग धर्म, जाति के आधार पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।

यह था दोनों समुदाय में विरोध का कारण : पहाड़ी नेता अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। वे कई बार दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले। वहीं, गुज्जर-बक्करवाल समुदाय के लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से उनको मिल रहे आरक्षण के कोटे में कटौती की जाएगी।

अमित शाह ने किया था वादा : वर्ष 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एक जनसभा में कहा था कि पहाड़ियों को उनका हक मलेगा, लेकिन साफ किया था कि किसी अन्य का हक काटकर उन्हें नहीं दिया जाएगा। अब हुआ भी वैसा ही। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह चुके हैं कि गुज्जर बक्करवाल का हक भी कायम रहेगा।

पहाड़ी नेता खुश, गुज्जर-बक्करवाल बोले- कोर्ट जाएंगे : पहाड़ी नेता इकबाल मलिक ने खुशी जताते हुए कहा कि अब हमें इस बिल के राज्यसभा में पारित होने का इंतजार है। एक अन्य नेता विक्रांत शर्मा ने कहा कि हम 35 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। वहीं, गुज्जर-बकरवाल लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही जम्मू-कश्मीर गुज्जर यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन शाह मोहम्मद चौधरी ने कहा कि हम सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे और न्यायालय जाएंगे।

राजौरी में तैनात सुरक्षा बल के जवान। जागरण

पहाड़ियों को हक मिले, लेकिन दूसरे के अधिकार छीन कर नहीं : उमर

नेकां उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी पार्टी पहाड़ी भाषाई लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के हक में है, लेकिन गुज्जर-बक्करवाल के अधिकारों को छीन कर नहीं। हमारी पार्टी के सांसद हसनैन मसूदी ने लोकसभा में यह मुद्दा इसलिए उठाया था, क्योंकि बिल में स्पष्ट नहीं है। उमर ने आरोप लगाया कि उनके आवास के दरवाजों को पुलिस ने बंद कर दिया और उन्हें पार्टी मुख्यालय तक एस्काट करते हुए अपराधी की तरह ले जाया गया। उन्हें राजौरी जिला के सुंदरबनी जाने से भी रोका गया।

मुंबई में 30 करोड़ रुपये के हीरों के साथ दलाल लापता

▶ कई फर्मों से एकत्रित की थी हीरों की खेप, व्यापारियों को सता रही ठगी की आशंका

मुंबई, मिड-डे : मुंबई के कई हीरा व्यापारियों से तकरीबन 30 करोड़ रुपये के हीरे लेकर एक दलाल लापता हो गया है। हीरा व्यापारी खुद के साथ ठगी होने की आशंका से सहमे हुए हैं। पीड़ितों में दिल्ली के व्यापारी भी शामिल हैं। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

मुंबई के हीरा इंडस्ट्री के सूत्रों की मानें तो दो दशक से व्यवसाय कर रहा जुहू निवासी मेहुल जवेरी प्रसिद्ध हीरा दलाल है। मेहुल के पिता के भी दलाल होने के कारण अधिकांश हीरा व्यापारी उसके परिवार से अच्छी तरह परिचित हैं। एक ज्वेलर ने बताया कि गत 24 जनवरी को जवेरी मेरी दुकान पर आया और कहा कि उसे कुछ हीरों की जरूरत है और वह उसे ग्राहकों को बेच देगा। वह मुझसे 56 लाख रुपये के हीरे ले गया और इसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। एक अन्य हीरा व्यापारी ने बताया कि ने मुझसे संपर्क किया था और कहा था कि वह कुछ ग्राहकों को मेरे हीरे दिखाएगा। इस पर मैंने उसे 12 लाख रुपये के हीरे दिए। पीड़ित हीरा व्यापारियों में दिल्ली के व्यापारी भी शामिल हैं। बीकेसी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक रघुनाथ कदम ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जवेरी ने बहाने से कई फर्मों से हीरे की कई खेप एकत्र की थीं। वह शहर भर के कई ज्वेलर्स के पास गया और अपने ग्राहकों को बेचने के बहाने हीरे लिए। हीरे लेने के बाद वह संपर्क में नहीं रहता था और कभी हीरे नहीं लौटाता था।

****

1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा मुक्त आवाजाही व्यवस्था के तहत संचालित होती है। यह भारत-म्यांमार सीमा के पास रहने वाले लोगों को बिना वीजा या किसी दस्तावेज के एक-दूसरे के क्षेत्रों में 16 किलोमीटर तक आने-जाने की अनुमति देती है।

न्यूज गैलरी

श्रील प्रभुपाद के जयंती समारोह को आज संबोधित करेंगे पीएम

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम कार्यक्रम को दोपहर तकरीबन साढ़े बारह बजे संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आध्यात्मिक गुरु के सम्मान में स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। आचार्य श्रील प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे, जिन्होंने वैष्णव मत के मूलभूत सिद्धांतों के संरक्षण और प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। (प्रेट्र)

तमिलनाडु में इमारत का एक हिस्सा ढहने से छह की मौत

चेन्नई: ऊटी के निकट लवडेल में इमारत का ढहे हिस्से के मलबे में दबने से छह महिला मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान शकीला, संगीता, भाग्या, उमा, मुथुलक्ष्मी और राधा के रूप में की गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख व घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता देने का आदेश दिया है। (एएनआइ)

नांदेड़ में दो हजार लोग हुए फूड प्वाइजनिंग के शिकार

छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने के बाद दो हजार लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। लोहा तहसील के अंतर्गत कोशतवाड़ी गांव में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ नजदीकी गांवों सवरगांव, पोशतवाड़ी, रिसनगांव और मस्की गांव के लोगों ने खाना खाया। बुधवार तड़के लोगों ने उल्टी और दस्त होने की शिकायत की। शुरुआत में 150 और बाद में तकरीबन 870 और पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रभावित गांवों में जांच के लिए पांच टीमों को तैनात किया गया है। (प्रेट्र)

असम विधानसभा में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून पर प्रस्ताव पारित

गुवाहाटी: असम विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें संसद को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। पर्यावरण व वन मंत्री चंद्र मोहन पटोवारी ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कुछ मुद्दों में संशोधन की मांग की। विपक्ष के सुझावों को शामिल करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को ध्वनि मत पर रखा और प्रस्ताव पारित हो गया। (प्रेट्र)

हरदा में चारों ओर दिखा तबाही का दृश्य

पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट ▸ 50 से अधिक घरों को नुकसान, बचाव अभियान संपन्न

कलेक्टर-एपी हटाए गए, कारखाना निरीक्षक निलंबित

नईदुनिया, हरदा

मध्य प्रदेश में हरदा जिले के बैरागढ़ गांव में मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के दूसरे दिन बुधवार स्थिति पर काबू पा लिया गया। दोपहर तक राहत एवं बचाव कार्य खत्म हो गया था। इस बीच घटनास्थल के आसपास तबाही के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले दिखे। आसपास के 50 से अधिक घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। विस्फोट से उड़े कंक्रीट के टुकड़ों व मलबे से समीप के खेतों में खड़ी फसल भी तबाह हो गई है। शासन ने औद्योगिक स्थापना एवं सुरक्षा विभाग सागर संभाग के कारखाना निरीक्षक व सहायक संचालक नवीन कुमार बरवा को निलंबित कर दिया है। साथ ही कलेक्टर ऋषि गर्ग व पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार कंचन को हटा दिया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के घटनास्थल के हवाई दौरे के बाद कलेक्टर व एसपी को हटाने का आदेश जारी हुआ।

बता दें कि फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग भड़क गई थी। इस दुर्घटना में प्रशासन ने अभी तक 11 लोगों की मृत्यु की बात कही है। सभी के शव दफना दिए गए हैं। मरने वालों में हिंदू मजदूर भी शामिल थे, जिनके शव बुरी तरह से जले मिले। ग्रामीणों का कहना है कि चार लोग लापता भी हैं। हादसे में करीब 200 लोग घायल हुए थे, जिनका उपचार हरदा, नर्मदापुरम, भोपाल व इंदौर के अस्पतालों में चल रहा है। ज्यादातर मरीजों को मलबे के टुकड़े लगने से गंभीर चोट आई है। जलने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके पूर्व ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के घटनास्थल तक न आने पर नाराजगी जताते हुए खंडवा-नर्मदापुरम राज्य राजमार्ग जाम लगाया था।

मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद बुधवार को घटनास्थल का निरीक्षण करते सीएम मोहन यादव। एएनआइ

11 लोगों की चली गई जान, करीब 200 लोग हुए हैं घायल

50 से अधिक घरों व समीप के क्षेत्र की फसल को हुआ नुकसान

सिंगाड पर लिया गया फैक्ट्री मालिक: मंगलवार देर शाम गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल व प्रबंधक रफीक खान को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया। यहां से राजेश और रफीक जेल भेज दिए गए, जबकि सोमेश को पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर लिया है।

दूसरी फैक्ट्री से पटाखे लूट ले गए ग्रामीण: बैरागढ़ में हुए भीषण हादसे के बाद भी पुलिस एवं प्रशासन का रवैया सुस्त बना रहा। विस्फोट स्थल से मात्र डेढ़ किलोमीटर दूर रहटाखुर्द स्थित राजेश अग्रवाल की दूसरी पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण करने भी कोई नहीं पहुंचा। यहां से ग्रामीण पटाखा लूट ले गए।

कांग्रेस ने लगाए साक्ष्य मिटाने के आरोप: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में मामले की जांच करने पहुंचे कांग्रेस के दल ने घटना के लिए शासन-प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। जीतू पटवारी ने सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने, मुआवजा राशि कम देने सहित घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कराए बिना भारी मशीनों से समतलीकरण कर साक्ष्य मिटाने के आरोप लगाए हैं।

सत्ता-प्रशासन के गठजोड़ से मामूली पटाखा कारोबारी बना बारूद माफिया

नईदुनिया, हरदा

हरदा जिला मुख्यालय से सटे रिहायशी इलाके में संचालित पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को हुए भीषण विस्फोट के बाद लोग गुस्से में हैं। इस पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल उर्फ राजू के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले मामूली पटाखा कारोबारी रहे राजेश ने सत्ता-प्रशासन के गठजोड़ से पटाखा कारोबार का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसकी काली कमाई का अंदाजा 2023 में जीएसटी के छापों से लगाया जा सकता है, जिसमें उसने कच्ची पर्चियों से हुए कारोबार में कर चोरी सामने आने पर 53 लाख रुपये जमा किए थे।

लोगों का आरोप है कि पटाखों के अवैध कारोबार को स्थानीय नेताओं व अधिकारियों का खुला संरक्षण प्राप्त था। आप नेता आनंद जाट ने बताया इन फैक्ट्रियों में पूर्व में भी धमाके हुए, जिनमें जनहानि होने के बावजूद अधिकारियों ने खतरे के अंदेशे को नजरंदाज किया। आप नेता आनंद जाट ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में पटाखा निर्माण के लिए कथित तौर पर पीले पाउडर यानी टीएनटी (ट्रिनिट्रोटोलुइन) का उपयोग किया जाता था, जिसका स्टाक भी इसी फैक्ट्री में होता था। टीएनटी का उपयोग युद्धक बम सहित बड़े औद्योगिक विस्फोटक में ही होता है, लेकिन पटाखों में लगने वाले बारूद की लागत घटाकर इनको तीव्र विस्फोट करने वाला बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा था। कुछ साल पहले इसकी शिकायत भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने इस तथ्य तक को गंभीरता से नहीं लिया।

उमा भारती ने आतंकियों का हाथ होने की जताई आशंका: पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरदा सिमी का गढ़ रहा है। जबलपुर में अल्प प्रवास के दौरान उन्होंने आशंका जताई है कि हो सकता है, इस घटना के पीछे आतंकियों का हाथ हो। उन्होंने कहा कि हरदा में हुई घटना की सरकार गंभीरता से जांच करवा रही है।

▸ पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ आक्रोश

फैक्ट्री मालिक सोमेश अग्रवाल (बाएं) तथा राजेश उर्फ राजू अग्रवाल (दाएं) को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रेट्र

एनजीटी के एकतरफा आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

▸ कहा, न्याय के उत्साह में एनजीटी को सावधानी से चलना चाहिए

▸ दो आदेशों को रद करते हुए फिर से न्यायाधिकरण के पास भेजा

नई दिल्ली, आइएएनएस: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने और करोड़ों रुपये का हर्जाना लगाने की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हरित न्यायाधिकरण को न्याय के उत्साह में सावधानी से चलना चाहिए। एकपक्षीय आदेशों का चलन और करोड़ों रुपये का हर्जाना लगाना पर्यावरण संरक्षण के व्यापक मिशन के लिए प्रतिकूल साबित हुआ है।

शीर्ष अदालत ने कहा, यह अफसोस की बात है कि एनजीटी द्वारा बार-बार एकपक्षीय निर्णय लेना, पूर्वव्यापी समीक्षा सुनवाई करना और नियमित रूप से इसे खारिज करना एक चलन बन गया है। एनजीटी के लिए प्रक्रियात्मक ईमानदारी की नए सिरे से भावना पैदा करना जरूरी है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कार्यों में न्याय और उचित प्रक्रिया के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन दिखाई दे। ऐसा करने से ही वह पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट एनजीटी द्वारा पारित दो फैसलों के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई कर रहा था। एक मामले में न्यायाधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेकर एकपक्षीय आदेश देते हुए मुआवजा चुकाने को कहा था।

दूसरे मामले में अपीलकर्ता की ओर से दायर समीक्षा याचिका को एनजीटी ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने दोनों आदेशों को रद कर दिया और मामले को फिर से हरित न्यायाधिकरण के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनजीटी सभी प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी करे और उनका पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित करे।

नक्सलियों से मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी बलिदान

जागरण संवाददाता, चतरा

▸ अफीम की खेती नष्ट कर लौट रहे थे पुलिस के जवान, तीन घायल

▸ चतरा जिले में पुलिस को घेरकर उग्रवादियों ने किया अंधाधुंध फायरिंग

झारखंड में अपने अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए अफीम की खेती करवा रहे तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के उग्रवादियों ने दुस्साहस का परिचय दिया है। चतरा में बुधवार को उग्रवादियों ने अफीम की खेती नष्ट कर लौट रहे पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में दो जवान बलिदान हो गए। बलिदान जवान सिकंदर सिंह बिहार के गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के रसकपुरा गांव तथा सुकुर राम झारखंड के रहने वाले थे। तीन जवान घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर है।

गंहरतरी गांव में पोस्ता की खेती नष्ट करने के लिए पुलिस बल और वन कर्मियों की टीम गई हुई थी। अभियान में सदर व वशिष्ठ नगर थाना पुलिस शामिल थी। खेती को नष्ट करके वापस लौटने के क्रम में गमहारतरी के पास पहले से घात लगाए उग्रवादियों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया। जब तक जिला बल के जवान समझ पाते, तब तक उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिसमें पांच जवान जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इसी क्रम सिकंदर सिंह और सुकुर राम बलिदान हो गए। इलाके में टीएसपीसी के उग्रवादी अफीम की खेती करवाते हैं। पुलिस द्वारा खेती को नष्ट करने के लिए चलाए जाने वाले अभियान से उग्रवादी नाराज थे। इसी कारण उग्रवादियों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि उग्रवादियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवान को इलाज के लिए चतरा के सरकारी अस्पताल लाया गया। प्रेट्र

दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में आठ लाख रुपये का इनामी नक्सली ढेर

नईदुनिया, दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों ने आठ लाख रुपये के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है। गोंदपल्ली, परलागट्टा, बड़ेपल्ली गांवों के बीच जंगल में सुरक्षा बल की टीम पर नक्सलियों के द्वारा फायरिंग के बाद जवानों ने पलटवार किया था। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया, कई घंटे चली मुठभेड़ के बाद जवानों ने घटनास्थल से चन्द्रणा उर्फ सत्यम नामक नक्सली का शव जब्त किया।

कवर्धा में मुठभेड़: कवर्धा के माराडबरा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मंगलवार को मुठभेड़ हो गई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। एक अन्य घटनाक्रम में कांकेर जिले के अंतागढ़ में नवागांव क्षेत्र में नक्सलियों के प्रचार वाले बैनर-पोस्टर लगाते छह को गिरफ्तार किया गया है।

नारायणपुर में तीन गिरफ्तार: नारायणपुर के बेड़ामामेटा के जंगल में पांच फरवरी को पुलिस पार्टी पर फायरिंग के मामले में जवानों ने बेड़ामामेटा निवासी नाग रानू पोड़ियाम, सुधराम मंडावी और विजय पोडियाम को गिरफ्तार किया है।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा, केरल वित्तीय रूप से अस्वस्थ राज्यों में से एक

नई दिल्ली, एएनआइ: केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केरल की वित्तीय एवं कर्ज की स्थिति पर वित्त आयोगों (12वें, 14वें व 15वें) के साथ-साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। यह वित्तीय रूप से सबसे अस्वस्थ राज्यों में से एक है क्योंकि इसके वित्तीय ढांचे में कई खामियां पाई गई हैं।

केरल की कर्ज लेने की सीमा तय करने के मुद्दे पर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नोट में कहा कि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर राज्य अनुत्पादक खर्चों या खराब लक्ष्य वाली सब्सिडियों के लिए बिना सोचे-समझे कर्ज लेता है तो बाजार से निजी उधारी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा, 'राज्यों के कर्ज देश की क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा राज्य द्वारा कर्ज की अदायगी में चूक से प्रतिष्ठा संबंधी समस्याएं पैदा होंगी' वेंकटरमणी ने कहा कि अनियंत्रित उधारी से निजी उद्योगों की कर्ज लेने की लागत में वृद्धि होगी और बाजार में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन व आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले का मैतेयी ने किया स्वागत, कुकी ने विरोध

▸ कोकोमी ने कहा-बाड़ लगाने का काम 30-40 साल पहले किया गया होता तो आज ये हालात न होते

इंफाल, प्रेट्र: भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का मणिपुर के मैतेयी समुदाय ने स्वागत किया है, जबकि नगा और कुकी समुदायों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें यह स्वीकार्य नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीमाओं को अभेद्य बनाने के प्रति कटिबद्ध है। पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया गया है। बेहतर निगरानी के लिए सीमा पर एक पेट्रोलिंग ट्रैक (गश्ती ट्रैक) भी बनाया जाएगा।

केंद्र के इस कदम को म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) खत्म करने का संकेत माना जा रहा है। मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड व अरुणाचल प्रदेश तक फैली 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा एफएमआर के तहत संचालित होती है। यह भारत-म्यांमार सीमा के पास रहने वाले लोगों को बिना वीजा या किसी दस्तावेज के एक-दूसरे के क्षेत्रों में 16 किलोमीटर आने-जाने की अनुमति देती है। मणिपुर की म्यांमार के साथ कम से कम 398 किमी लंबी सीमा लगती है, जिसमें से 10 किलोमीटर पर बाड़ लगा दी गई है। वैसे भी म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेयी समुदाय की लगातार मांग रही है। वे आरोप लगाते रहे हैं कि आदिवासी आतंकवादी अक्सर खुली सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। यही नहीं, इस रास्ते से भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी भी की जा रही है। घाटी स्थित नागरिक संगठनों की संयुक्त समन्वय समिति (कोकोमी) ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही आगाह किया कि इस प्रक्रिया के दौरान राज्य के किसी भी भूमि क्षेत्र से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कोकोमी प्रवक्ता एम धनंजय ने कहा कि अगर सीमा पर बाड़ लगाने का काम 30-40 साल पहले किया गया होता तो हमें हिंसा का ये वर्तमान दौर न देखना पड़ता। उधर, राज्य में नगा-कुकी समुदाय ने केंद्र के इस कदम पर एतराज जताया है। यूनाइटेड नगा काउंसिल के अध्यक्ष एनजी लोरहो ने कहा कि हम सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को रद करने के खिलाफ हैं। हमें यह स्वीकार्य नहीं है। जहां तक म्यांमार से मणिपुर में नशीली दवाओं की तस्करी और घुसपैठ का सवाल है तो इससे निपटने के लिए अन्य वैकल्पिक साधन खोजने चाहिए।

अरुणाचल के सीएम ने केंद्र के फैसले की सराहना की

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस कदम से सीमा पार से अराजक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगेगी। अरुणाचल प्रदेश की 520 किमी लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। खांडू ने एक्स कहा, हमारी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए सही दिशा में यह बड़ा कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का आभार।

बंगाल में अब लाइब्रेरी में नियुक्तियों में धांधली का आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: भाजपा ने ममता सरकार पर अब नया आरोप लगाया है। भाजपा सांसद जोतिर्मय सिंह महतो ने लाइब्रेरी में हुई नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महतो का आरोप है कि पुरुलिया लाइब्रेरी में गलत तरीके से 29 लोगों को नौकरी दी गई है।

सांसद का आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी मिली है, उनमें भर्ती बोर्ड के सदस्य का पुत्र भी शामिल है। साथ ही एक शख्स ऐसा भी है, जिसे पैसे के बदले स्कूल में नौकरी मिली थी। कोर्ट के आदेश पर उसकी नौकरी चली गई थी। अब उस व्यक्ति को फिर से सरकारी नौकरी मिल गई है। महतो ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें सीबीआइ जांच की मांग की गई है। हालांकि, कोर्ट द्वारा इस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है या नहीं, यह कुछ दिनों में पता चलेगा। बता दें कि शिक्षक भर्ती, नगर पालिका नियुक्ति और राशन घोटाले में तृणमूल के कई नेता, मंत्री व विधायक जेल में हैं।

ईडी पर हमले की जांच को एसआइटी के गठन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में हुआ था हमला

बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और केंद्रीय बल के जवानों पर पांच जनवरी को हुए हमले की जांच के लिए सीबीआइ और बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के एकलपीठ के आदेश पर खंडपीठ ने बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकलपीठ ने 17 जनवरी को एसआइटी गठन का आदेश दिया था।

एकलपीठ के आदेश को ईडी ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी और स्वतंत्र रूप से सीबीआइ से जांच की मांग की। बुधवार को खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में अंतिम आदेश ईडी और राज्य सरकार दोनों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ही पारित किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई छह मार्च को होनी है, तब तक एसआइटी की जांच पर रोक लगा दी गई है। ईडी के वकील ने बुधवार को कोर्ट में तर्क दिया कि राज्य पुलिस द्वारा मामले की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमला करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामलों पर ईडी की जांच के संबंध में हुआ था, जिसमें राज्य कैबिनेट के एक दिग्गज सदस्य पहले से ही सलाखों के पीछे है। राज्य सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि जांच का प्रभार पूरी तरह से राज्य पुलिस को दिया जाए। बताते चलें कि राशन वितरण घोटाला मामले में पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों की एक टीम जब संदेशखाली में तृणमूल नेता शाहजहां शेख के आवास की तलाशी लेने गई थी, उसी दौरान भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था। इसमें एजेंसी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे।

कलकत्ता हाई कोर्ट। फाइल

जागरण विशेष

बायो रिसोर्स सेंटर से श्रीअन्न संग प्राकृतिक कृषि को मिल रहा संबल

बिहार के शिवहर जिले में कृषि विभाग के साथ मिलकर जयकली कुंवर मेमोरियल ट्रस्ट कर रहा सेंटर का संचालन

नीरज • शिवहर

चार माह पहले तक बिहार के शिवहर जिले के किसान शंकर राम श्रीअन्न की खेती और उपयोगिता नहीं समझते थे। मोटा अनाज कह धान-गेहूं पर ही आश्रित थे, लेकिन बीते साल 10 कट्ठे में 10 क्विंटल मडुवे की उपज और अच्छी कीमत ने उनकी राय बदल दी। साढ़े आठ क्विंटल मडुवा को 25 हजार 500 में बेचा है। इससे उन्हें साढ़े 13 हजार की शुद्ध आमदनी हुई है। अगले मौसम में रकबा बढ़ाने की तैयारी में हैं। यह बदलाव शिवहर में स्थापित बायो रिसोर्स सेंटर (जैव संसाधन केंद्र) के प्रचार-प्रसार और निशुल्क प्रशिक्षण से आया है। जिला कृषि पदाधिकारी कमलेश कुमार का कहना है कि श्रीअन्न की खेती के प्रति जागरूकता आई है। यह एक बेहतर प्रयास है। विभाग की टीम भी किसानों के संपर्क में रहती है।

राकेश, संस्थापक, जयकली देवी मेमोरियल ट्रस्ट

सप्ताह में तीन दिनों का प्रशिक्षण सत्र चलता है। पहले दिन घरेलू अपशिष्ट, गोबर व गोमूत्र की मदद से बायोइनपुट्स तैयार कर रासायनिक उर्वरक की जगह इसके उपयोग व लाभ की जानकारी दी जाती है। शेष दो दिनों में श्रीअन्न की खेती और उसके लाभ के बारे में बताया जाता है।

प्राकृतिक पद्धति के साथ श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित बायो रिसोर्स सेंटर से तीन माह में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर के तीन हजार किसान जुड़ चुके हैं। वे जैविक उर्वरक बनाने व अपनाने के साथ श्रीअन्न की खेती के प्रति प्रेरित हुए हैं। 600 किसानों ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। तीन वर्षों से राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के अभियान में जुटे शिवहर जिले के जयकली कुंवर मेमोरियल ट्रस्ट ने कृषि विभाग की देखरेख में इस नवाचार को शुरू किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और खेती-किसानी में रुचि रखनेवाले राकेश इसके संस्थापक हैं।

काम और प्रशिक्षण दोनों मिल रहा: शिवहर के तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा स्थित कृषि फार्म में स्थापित सेंटर में ज्वार, बाजरा, चीना, कोदो, सावां और मडुवे के अलावा काले गेहूं की खेती की जा रही है। किसान यहां काम करके और देखकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राकेश बताते हैं कि प्रशिक्षण के लिए केंद्र में तीन कृषि विज्ञानी, एक केमिस्ट, एक शोध समन्वयक और दो संसाधन कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सेंटर से जुड़े किसानों की फसलों का मुआयना किया जाता है। अगर किसी के सामने दिक्कत आती है तो उन्हें फार्म हाउस में बुलाकर प्रायोगिक जानकारी के साथ समाधान बताया जाता है। यहां होने वाले खर्च का वहन फार्म में होनेवाली उपज से पूरा किया जाता है। किसान शंकर बताते हैं कि शिवहर-सीतामढ़ी में मडुवे की खेती होती रही है, लेकिन किसान अपने लिए ही थोड़ा-बहुत उपजाते थे। रिसोर्स सेंटर से मार्गदर्शन के बाद इसका विस्तार कर रहे हैं।

तरियानी छपरा स्थित फार्महाउस में तैयार हो रही जैविक खाद • सौ. रिसोर्स सेंटर

श्रीअन्न को मुख्यधारा की खेती बनाने की तैयारी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देशभर में 261 संस्थाओं को बायो रिसोर्स सेंटर संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। राकेश द्वारा संस्थापित शिवहर का जयकली कुंवर मेमोरियल ट्रस्ट भी उनमें से एक है। जुलाई, 2023 में यहां सेंटर खोलने की मंजूरी मिली थी। सात सितंबर, 2023 से काम शुरू कर दिया गया था। अब सीतामढ़ी में चार, मुजफ्फरपुर में एक व शिवहर में तीन और बायो रिसोर्स सेंटर खोलने की तैयारी है। संस्था के शोध समन्वयक गौरव कुमार सिंह बताते हैं कि धीरे-धीरे किसान श्रीअन्न की खेती और जैविक उर्वरक के उपयोग के प्रति जागरूक होने लगे हैं।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

शराब पीकर मुकदमे में समझौता करने आए दो गिरफ्तार

जासं, जमुई: बिहार के जमुई जिले में एक चौकीदार शराब का सेवन कर बुधवार को आरोपित के साथ न्यायालय पहुंच गया। वहां उसे नशे में पाकर विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र बहादुर सिंह ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया। वह चौकीदार दलित अत्याचार के एक मुकदमे में आरोपित के साथ समझौता करने न्यायालय में उपस्थित हुआ था। मामला एससी एसटी अदालत में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, मुकदमा करने वाला चौकीदार चंद्रदेव पासवान अपने साथ इस मामले के एकमात्र आरोपित शंभू यादव को लेकर न्यायालय में पहुंचा और जमानत के लिए सुलह का आवेदन दाखिल किया। दोनों पक्षकारों ने पहले शराब पी उसके बाद नाम पुकारे जाने पर न्यायालय पहुंच गए।

****

दैनिक जागरण
एक बार आरंभ होने के बाद कोई भी कार्य आसान हो जाता है

क्षेत्रवाद पर प्रहार

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते समय प्रधानमंत्री ने वैसे ही कांग्रेस को निशाने पर रखा, जैसे उन्होंने लोकसभा में रखा था। अपने संबोधन में उन्होंने कर्नाटक की पूरी सरकार की ओर से दिल्ली में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का जिक्र किए बिना उसे देश को बांटने की एक साजिश करार देकर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला ही किया। उन्हें यह हमला इसीलिए करना पड़ा, क्योंकि उक्त प्रदर्शन में खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। उन्होंने यह प्रदर्शन इसलिए किया, ताकि यह साबित कर सकें कि केंद्र सरकार कर्नाटक के वित्तीय हितों की अनदेखी कर रही है। हालांकि इस आरोप का खंडन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने टैक्स बंटवारे के मसले को तूल देना आवश्यक समझा और इसीलिए वह अपने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रियों के साथ दिल्ली प्रदर्शन करने आ गए। ध्यान रहे कि डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश ने अंतरिम बजट को लेकर यह कहा था कि दक्षिण का पैसा उत्तर में बांटा जा रहा है और यदि ऐसा ही होता रहा तो दक्षिणी राज्यों को अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है। यह क्षेत्रवाद के साथ अलगाववाद को जानबूझकर हवा देने के अलावा और कुछ नहीं। इस प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश को तोड़ने के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट करने में भी संकोच नहीं किया कि हमारा टैक्स हमारा पैसा जिस भाषा में बोला जा रहा है, वह देश के लिए नया खतरा पैदा करने वाला है।

समझना कठिन है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे डीके सुरेश के बयान पर आपत्ति जता चुके थे, तब भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रदर्शन करने क्यों चले आए? यदि कर्नाटक सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि उसके मुख्यमंत्री दिल्ली आकर प्रदर्शन करने लगें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यही किया। यदि कोई राज्य सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं तो उसे धरना-प्रदर्शन का सहारा लेने के बजाय वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री से संवाद करना चाहिए। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ऐसा नहीं किया। इससे यही पता चलता है कि राष्ट्रीय दल होने के बाद भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री किस तरह क्षेत्रीय दलों के नेताओं की तरह व्यवहार करने लगे हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह क्षेत्रवाद की राजनीति पर प्रहार किया, वैसे ही उन्होंने लोकसभा में अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को भी निशाने पर लिया था, क्योंकि यह प्रश्न किया जा रहा था कि किसानों, महिलाओं, युवाओं के कल्याण की योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? इस तरह के प्रश्न देश को बांटने वाली राजनीति को ही रेखांकित करते हैं।

समान नागरिक संहिता

भारत के संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा ने इस बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रहित में देश में समान नागरिक संहिता उपयुक्त समय पर बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी विभिन्न मामलों की सुनवाई में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में उचित टिप्पणी कर चुका है। बावजूद इसके स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर किसी स्तर पर प्रभावी पहल नहीं हो पाई। लंबी प्रतीक्षा के बाद अब मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड ने यह कदम उठाने का साहस दिखाया। प्रदेश में सत्तारूढ़ धामी सरकार ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जनता से वादा किया। दोबारा सत्ता संभालते ही धामी कैबिनेट ने पहली ही बैठक में संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने को विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया। समिति से ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार ने देरी नहीं लगाई और विधानसभा सत्र में इसका विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया। दो दिन की चर्चा के बाद सदन में यह पारित हो चुका है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सिविल कानून समान होंगे। संहिता में महिला अधिकारों को अधिक संरक्षित किया गया गया है तो विवाह और विवाह विच्छेद को पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में भी कानूनी दायरे के भीतर दोनों पक्षों के हित सुरक्षित किए गए हैं। ऐसे ही तमाम प्रविधान किए गए हैं। राजनीतिक गलियारों में धामी सरकार की इस पहल के चाहे जो निहितार्थ निकाले जाएं, लेकिन यह कदम अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनने जा रहा है। वे भी इसी तरह अपने यहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे पूरे देश में बेहतर माहौल का निर्माण होने के साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर भी इसके लिए राह तैयार होगी। कुल मिलाकर राज्य की समान नागरिक संहिता की पहल के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे।

घातक असर वाला इजरायल-हमास संघर्ष

शिवकांत शर्मा

समूचे पश्चिम एशिया में लड़ाई फैलने से ईरान के युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का भी खतरा है

इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए एक और प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। हालांकि इस प्रस्ताव की शर्तों को देखते हुए तत्काल कोई सहमति बनने के आसार कम ही दिखते हैं। इस लड़ाई को छिड़े हुए करीब चार महीने पूरे होने को हैं। इसमें 27,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की भारी सैन्य उपस्थिति और कूटनयिक प्रयासों के बावजूद यह लड़ाई अब मिसाइल और ड्रोन हमलों के रूप में लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और जार्डन समेत आसपास के दस देशों में फैल चुकी है। यमन के ईरान समर्थक हाउती आतंकियों के हमलों से लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया है। जहाजों को अफ्रीका का चक्कर काटकर यूरोप-अमेरिका जाना पड़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं।

अमेरिका में यह चुनावी वर्ष है और यूरोप में चल रही यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पा रहा है। ऐसे समय में अमेरिका ऐसी किसी और लड़ाई में नहीं उलझना चाहता, जिससे रूस को यूक्रेन की और जमीन हथियाने और यूरोप में दबदबा कायम करने का अवसर मिल जाए। यही कारण है कि अमेरिका ने सीरिया में जार्डन की सीमा पर स्थित अपने सैन्य अड्डे पर 28 जनवरी के ड्रोन हमले का जवाब तत्काल देने के बजाय सोच-विचार कर देने का निश्चय किया। ड्रोन हमले में अमेरिका के तीन सैनिक मारे गए थे और 30 से अधिक घायल हुए थे। यद्यपि ईरान ने हमले में अपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका से इन्कार किया, फिर भी अमेरिका का मानना है कि यह हमला सीरिया में सक्रिय जैनाबियून ब्रिगेड और फतेमियून डिविजन के या इराक में सक्रिय इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के किसी गुट ने किया है, जिन्हें प्रशिक्षण और हथियार ईरान का इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड देता है। अमेरिकी रक्षामंत्री लायड आस्टिन ने स्वीकारा कि हमास-इजरायल युद्ध के बाद से इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर 160 हमले हुए हैं। अपनी नाक बचाने के लिए अमेरिका ने ईरान समर्थित इस्लामी प्रतिरोध गुटों के ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए, परंतु वह लड़ाई को फैलाना नहीं चाहता। इसीलिए वह अपने अरब मित्र देशों के साथ मिलकर लंबे युद्धविराम के एक सौदे पर काम कर रहा है।

अमेरिका के साथ-साथ मिस्र की दिलचस्पी युद्धविराम में सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्वेज नहर उसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है और लाल सागर का व्यापार ठप होने से स्वेज नहर से होने वाली आमदनी कम हो गई है। इसीलिए हमास नेता इस्माइल हानिया ने पिछले दिनों काहिरा जाकर नए युद्धविराम प्रस्ताव पर दो दिनों तक विचार किया। इस सौदे में दो बड़ी अड़चनें हैं। हानिया की मंशा है कि बंधकों की रिहाई और युद्धविराम के बाद इजरायल गाजा से हट जाए और अंतरराष्ट्रीय सेना की देखरेख में फलस्तीन के राजनीतिक समाधान की बातचीत शुरू हो। नेतन्याहू गाजा से हमास की हस्ती मिटाए बिना वहां से नहीं हटना चाहते।

संभव है कि दबाव में आकर नेतन्याहू और हानिया थोड़े दिनों के लिए कोई सौदा कर लें, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगा। नेतन्याहू का गठबंधन ऐसे कट्टरपंथी जायनिस्ट दलों के समर्थन पर टिका है, जो जार्डन नदी से समुद्र तक फैली जमीन पर यहूदियों का दैविक अधिकार मानते हैं। जबकि हमास जार्डन नदी से समुद्र तक फैली जमीन को फलस्तीनी और इजरायल को उस पर कब्जा करके बैठा देश मानता है। स्थायी युद्धविराम होते ही इजरायल में चुनाव की मांग उठेगी, जिसमें नेतन्याहू का हारना लगभग तय है। यदि लड़ाई जारी रहती है और नेतन्याहू गाजा से हमास की जड़ें उखाड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमास का राजनीतिक अस्तित्व उसी तरह समाप्त हो जाएगा, जैसे सीरिया से इस्लामिक स्टेट का हुआ था।

हाउती विद्रोहियों के हमलों से प्रभावित हो रहा समुद्री व्यापार। एएफपी

इजरायल हमास युद्ध एक नाजुक दोराहे पर है। एक रास्ता बंधकों के बदले लंबे युद्धविराम की ओर जाता है। इसका प्रयोग अमेरिका और अरब देश मिलकर सुलह की ऐसी रूपरेखा तैयार करने में कर सकते हैं जिसके सहारे अरब या अंतरराष्ट्रीय देखरेख में गाजा और पश्चिमी किनारे पर नया फलस्तीनी शासन कायम हो सके। इजरायल को सुरक्षा से जीने का भरोसा मिल सके और फलस्तीनियों को स्वतंत्रता से जीने और अपनी सरकार बनाने का हक मिल सके। ऐसा होने पर इजरायल और सऊदी अरब के संबंधों के बढ़ने की प्रक्रिया बहाल हो सकेगी और अमेरिका की प्रस्तावित भारत-पश्चिम एशिया कारिडोर योजना भी आगे बढ़ सकेगी। इसमें दो बड़ी अड़चनें हैं। गाजा में हुए भारी संहार और विनाश के बाद हमास जैसे संगठनों को दोबारा पनपने से कौन रोकेगा? दूसरी बड़ी अड़चन है वे यहूदी बस्तियां, जिन्हें इजरायल ने पिछले 57 वर्षों के कब्जे के दौरान फलस्तीनियों के पश्चिमी किनारे पर बसाया है। क्या इजरायली सरकार उन्हें वहां से हटा पाएगी? दूसरा रास्ता युद्धविराम की जगह सीमित और लक्षित युद्ध जारी रखने की ओर जाता है, जिस पर नेतन्याहू अड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व उसी पर टिका है। वह हमलों को तब तक नहीं रोकना चाहते, जब तक हमास का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। इस रास्ते का सबसे बड़ा खतरा यही है कि इतने व्यापक संहार और विनाश के बाद फलस्तीनियों के साथ-साथ अरब देशों में भी इजरायल और पश्चिम के प्रति रोष की भावना फैल सकती है, जो हमास जैसे संगठनों के लिए जमीन तैयार करेगी। पश्चिमी किनारे और लेबनान में रोष पहले से ही उबाल पर है। हिजबुल्ला के किसी राकेट से इजरायली बस्ती को बड़ी क्षति होते ही इजरायल को अपनी उत्तरी सीमा पर भी लड़ाई में कूदना पड़ सकता है। यमन, सीरिया और इराक में ईरान समर्थक प्रतिरोधी गुट अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। किसी जहाज या अड्डे को कोई बड़ी क्षति हुई तो अमेरिका को भी युद्ध में उलझना पड़ सकता है। लाल सागर का रास्ता बंद होने से विश्व व्यापार को वैसे ही क्षति हो रही है। समूचे पश्चिम एशिया में लड़ाई फैलने से ईरान के युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का भी खतरा है। ऐसी भयावह आशंकाओं को देखते हुए भलाई इसी में लगती है कि इजरायली जनता ही अपनी सरकार को बदले या फिर उस पर युद्धविराम का दबाव डाले। अमेरिका के प्रसिद्ध राजनयिक हेनरी किसिंजर ने ठीक ही कहा था, 'इजरायल की कोई विदेश नीति नहीं है, सिर्फ घरेलू राजनीति है।'

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

विकृत इतिहास लेखन के दुष्परिणाम

हरेंद्र प्रताप

इस्लामी हमलावरों के रक्तरंजित इतिहास के बावजूद वामपंथी हमेशा उनका महिमामंडन ही करते रहे

अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन दिनों पूरा देश राममय है। इन्हीं प्रभु श्रीराम को काल्पनिक बताकर नकारने के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने क्या-क्या तिकड़में नहीं कीं। हिंदुओं के आराध्य देवों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाने के लिए कई पुस्तकें तक लिखी डालीं, जो दुर्भाग्य से बाद में हमारे स्कूल-कालेजों के पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन गईं। 'प्राचीन भारत में विज्ञान और सभ्यता' नामक पुस्तक में प्रभु श्रीराम के बारे में वामपंथी इतिहासकार आरएस शर्मा ने लिखा कि 'पुराणों की परंपरा के आधार पर श्रीराम का जन्म अयोध्या में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, पर खोदाई से यह सत्य सामने आया कि उस समय वहां मानव की कोई बस्ती थी ही नहीं।' आरएस शर्मा ने अपने इसी तर्क के आधार पर अपनी पुस्तक में 'प्रभु श्रीराम को काल्पनिक पात्र' घोषित कर दिया था। आजाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत के बारे में जो कुछ पढ़ाया जाता रहा, वे सब पुस्तकें वामपंथियों ने लिखी थीं। इस कारण आरएस शर्मा द्वारा लिखित 'प्राचीन भारत' तथा सतीश चंद्रा द्वारा लिखित 'मध्यकालीन भारत' को पढ़कर तैयार हुई पीढ़ियां न केवल अभारतीय होती रहीं, बल्कि वे भारत को हीन भाव से भी देखने लगीं। इन वामपंथियों ने अपनी पुस्तकों में प्रभु श्रीराम, श्रीकृष्ण और अर्जुन को इतिहास का काल्पनिक पात्र घोषित कर दिया था।

पहले अयोध्या में श्रीराम मंदिर और अब वाराणसी के ज्ञानवापी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे में वहां प्राचीन काल में भव्य मंदिर होने के प्रमाण सामने आ रहे हैं। इस्लामी आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को तोड़ा और बलात मत परिवर्तन कराया। इस्लामी हमलावरों का इतिहास रक्तरंजित है, पर वामपंथियों ने उनको महिमामंडित किया। उनके द्वारा तोड़े गए आस्था के केंद्रों का भी आरोप वामपंथियों ने साजिशन हिंदुओं पर लगा दिया। सतीश चंद्रा ने 'मध्यकालीन भारत' में लिखा है कि हिंदुओं ने बौद्ध और जैन मंदिरों को न केवल तोड़ा, बल्कि उन्होंने बलपूर्वक कब्जा किया। सतीश चंद्रा के अनुयायी आंखें खोलकर देख लें कि न्यायालय में आज हिंदुओं की तरफ से लड़ने वाले वकील पिता-पुत्र हरिशंकर और विष्णु 'जैन' हैं। आरएस शर्मा, सतीश चंद्रा, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा और इरफान हबीब द्वारा लिखी पुस्तकें माध्यमिक से लेकर उच्चतर स्तर तक पढ़ाई जाती रहीं। इनकी पुस्तकों को पढ़कर तैयार हुई पीढ़ियां इस देश और इसकी सच्चाई को नकारने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। इसका जीवंत उदाहरण वामपंथी हैं।

हमलावरों का महिमामंडन। फाइल

22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद वामपंथियों की प्रतिक्रिया उनके विकृत सोच को प्रकट करती है। एक वामपंथी ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाली 'मूर्ति' के बारे मे लिखा, 'रामलला के हाथ में धनुष-तीर दिखलाना अपराध है। पांच साल के बालक के हाथ में शस्त्र-जुवेनाइल एक्ट के अनुसार कार्रवाई हो।' संभव है आने वाले दिनों में वामपंथी अपने लोगों को सक्रिय करके इस पर बहस भी छेड़ दें। वे इस विषय को प्रचारित कर सकते हैं कि बच्चे श्रीरामलला की मूर्ति देखकर हिंसक हो सकते हैं। अतः उसे हटाया जाए। अयोध्या में खोदाई से ही पता चला था कि वह एक प्राचीन मंदिर था। आखिर आरएस शर्मा ने किस खोदाई के आधार पर यह लिखा कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व वहां कोई मानव बस्ती थी ही नहीं। दुर्भाग्य देखिए कि उनसे इसका प्रमाण मांगे बिना उनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती रहीं। अगर प्रभु श्रीराम काल्पनिक थे तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को सबसे पहले ठुकराने वाले वामपंथी नेता का नाम उनके माता-पिता ने सीताराम येचुरी क्यों रखा? माता-पिता का प्रभु श्रीराम-माता सीता के प्रति जो आस्था थी, उसको नकारने का साहस वामपंथी विषवमन का सबसे बड़ा प्रमाण है। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के जन्मस्थान के बारे में फैसला आ जाने के बाद भी 'बाबरी मस्जिद' कह कर भारत के मुसलमानों को भड़काने का असफल प्रयास चल रहा है। भारत के संविधान और पूजा स्थल कानून का हवाला देकर अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी की सच्चाई को भी नकारा जा रहा है।

अयोध्या, मथुरा और काशी की बात करने पर सेक्युलर जमात बाबर-अकबर और औरंगजेब को सेक्युलर बताने का चाहे जितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन वह सफल नहीं होगा। वह इससे मुंह नहीं मोड़ सकता कि औरंगजेब एक बेहद बर्बर शासक था। उसने अपने भाई दारा शिकोह का सिर काटकर उसे पिता शाहजहां के सामने पेश किया था। उसने तमाम मंदिर तोड़े और सिख गुरुओं को निर्ममता से मारा। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में पुरातत्व सर्वेक्षण का मामला न्यायपालिका के तहत विचाराधीन है, लेकिन इसे न्यायालय में लटकाने के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमें मुगलों से कुछ भी लेना-देना नहीं है, पर जब भी मुगलों के काले कारनामों पर से पर्दा उठता है तो उनके बचाव में वह सामने आ जाते हैं। इबादतगाह को तो बदला जा सकता है, पर पूजा स्थल को नहीं। न्यायालय में जाकर सच्चाई को सामने लाने के लिए हिंदू सर्वे या खोदाई की मांग कर रहे हैं। समय का तकाजा है कि हिंदुओं के प्रमुख पूजा स्थलों को वापस किया जाए। यह समय की मांग है कि अगर मुगलों की बर्बरता पर से पर्दा उठता है तो उसमें बाधाएं न डाली जाएं। सच सामने आना ही चाहिए। इसके साथ ही सरकार और देश का प्रबुद्ध वर्ग आगे आकर वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों को पाठ्यक्रमों से हटाने की पहल करें। तभी भारत अपने मूल स्वभाव के साथ आगे बढ़ सकेगा।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्ता की सार्थकता

संस्कारों का निर्माण युगों की साधना से होता है। संस्कार दृढ़ता एवं विनम्रता का परिचायक है। संस्कारवान या ज्ञानी व्यक्ति जब सत्ता पर आरूढ़ होता है तो विवेकशून्य नहीं होता और परमार्थ एवं आदर्श निर्माण के मार्ग से किंचित भी विचलित नहीं होता है। न ही मदांध हो अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करता है। वहीं सत्ता की बागडोर संभालते ही अज्ञानी या संस्कारहीन व्यक्ति ईश्वर-विमुख हो अहंकार के घोड़े पर सवार होकर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघने को विवश हो जाता है।

ईश्वर किसी भी मनुष्य को सत्ता एवं शक्ति महज संसार के कल्याण एवं स्वयं के आत्मोत्थान के लिए प्रदान करते हैं। इन दुर्लभ अवसरों का उपयोग जो गुणीजन समाज एवं राष्ट्र की जीवनीशक्ति के लिए करते हैं, वे इतिहास में अमिट हो जाते हैं, जबकि स्वार्थी एवं अज्ञानी इसका उपयोग स्वयं एवं अपने परिजनों के कल्याण के लिए कर अपने पद तथा कद को कलुषित करते हैं। कोई भी प्रतिभा तभी फलीभूत होती है जब उसका लक्ष्य लोक-कल्याण हो। स्वार्थ केंद्रित सत्ता अथवा साधना अपनी शक्ति के क्षरण के लिए अभिशप्त होती है। निःस्वार्थ साधना अथवा सत्ता का सदुपयोग सत्ताधारी को शाश्वत यश एवं सम्मान का भागी बनाता है। वहीं जब कोई व्यक्ति सत्ता में आने के बाद विध्वंस का कारण बनता है तो वह दैवीय अनुकंपा से मिले इस दुर्लभ जीवन अवसर का दुरुपयोग करता है। इसके दंडस्वरूप उसके भावी जीवन की संपूर्ण सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। अतः सत्ता की सार्थकता राष्ट्र एवं लोक हित में है। अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता से मानवता, परमार्थ एवं उन्नत समाज के कल्याण में है। सत्ता का दुर्लभ अवसर पाकर भी राष्ट्र के लिए कुछ विशिष्ट एवं उल्लेखनीय न कर पाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। ऐसे व्यक्ति को समय एवं इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

सर्जरी से प्रसव का बढ़ता चलन

देवेंद्रराज सुथार

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज विश्व में पांच में से एक बच्चा सर्जरी के माध्यम से जन्म लेता है

भारत में सिजेरियन यानी आपरेशन से डिलीवरी (प्रसव) की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-पांच के मुताबिक देश में सिजेरियन के जरिये बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की तादाद में वृद्धि देखी गई है। जहां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-चार में 2015-16 के दौरान आपरेशन के जरिये बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं का आंकड़ा 17.2 प्रतिशत था, वह 2019 से 2021 के बीच बढ़कर 21.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। शहरी क्षेत्रों में तो यह 32.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 17.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है। यह वृद्धि एक चुनौती खड़ी करती है। खासकर तब जब निजी स्वास्थ्य क्लीनिक ऐसे प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर पांच में से एक बच्चा सिजेरियन के माध्यम से पैदा होता है। आने वाले दशकों में यह आंकड़ा बढ़कर एक तिहाई होने की संभावना है। भारत भी इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में सिजेरियन प्रसव में वृद्धि दर्ज की गई है, जहां निजी क्लीनिकों को सरकारी सुविधाओं की तुलना में प्राथमिकता मिल रही है। सर्जरी के बाद कुछ जटिलताएं अक्सर बनी रहती हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं को प्रभावित करती हैं। यह आर्थिक बोझ भी पैदा कर रही है, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में निजी अस्पतालों में सामान्य जन्म की तुलना में 10 गुना अधिक खर्च होता है। हालांकि सिजेरियन का विकल्प चुनने के कुछ वैध कारण भी हैं, जैसे चिकित्सा आवश्यकता या मां की पसंद। यह कुछ अस्पतालों के लाभ के उद्देश्यों से जुड़ी हुई भी प्रतीत होती है।

यह भी निर्विवाद है कि सिजेरियन डिलीवरी शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने और शिशुओं में जन्मजात मानसिक विकलांगता के मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि सिजेरियन डिलीवरी की बढ़ती प्रवृत्ति परिवारों पर बोझ डालती है। नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन अनावश्यक सिजेरियन प्रक्रियाओं को कम करने के महत्व पर जोर देता है। यह जरूरी है कि सरकार स्वस्थ गर्भवती माताओं में सामान्य प्रसव के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अभियान चलाए। यह महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य साक्षरता के साथ सशक्त बना सकता है, जो अंततः माताओं और शिशुओं दोनों के लिए एक स्वस्थ भविष्य में योगदान कर सकता है। माताओं और नवजात शिशुओं के हितों की रक्षा करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चिकित्सकीय रूप से आवश्यक होने पर ही सिजेरियन डिलीवरी की जाए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

जरूरी है जमीनी हकीकत का विश्लेषण

'शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में 'जगमोहन सिंह राजपूत' ने शिक्षा के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यूं तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार आर्थिक संसाधनों और शिक्षकों के अनुशासन पर विशेष ध्यान देती है, पर इसके साथ-साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत पर भी सरकार को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होने पर अक्सर शिक्षकों पर गाज गिरती है, पर कोई यह नहीं देखता कि बच्चों के अभिभावक ही उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। विद्यालय भेजने से ज्यादा जरूरी उनके लिए जीविकोपार्जन और खेती-बाड़ी का काम होता है। कहीं-कहीं तो यह भी देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से बच्चों के यूनिफार्म आदि के लिए मिलने वाले धन का उपयोग अभिभावक अन्य जरूरतों को पूरा करने में कर लेते हैं और बच्चों को बिना यूनिफार्म के ही स्कूल जाना पड़ता है। सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में एप और स्मार्ट क्लास के जरिये पढ़ाने के आदेश दिए गए हैं, पर उन विद्यालयों का क्या जो आज भी आधारभूत सुविधाओं जैसे अच्छी सड़कें, अच्छा विद्यालय परिसर, जल, फर्नीचर, बिजली आदि से वंचित हैं। जहां मोबाइल का नेटवर्क तक सही नहीं आता क्या वहां डिजिटल शिक्षा पद्धति अपनाई जा सकती है? इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता सिर्फ भारी-भरकम बजट देने से या शिक्षकों के ऊपर तलवार लटकाने से नहीं बढ़ेगी, इसके लिए जरूरत है एक बेहतरीन विकास संचार की, जिसके जरिये जमीनी हकीकत का विश्लेषण हो सके। अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हों। शिक्षकों को भी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है। भारत के बेहतर भविष्य के लिए सरकारी तंत्र की सक्रियता और अभिभावकों की शिक्षा के प्रति निष्क्रियता का अंत आवश्यक है।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

समाज की जरूरत हैं शिक्षक

'शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती' शीर्षक से जगमोहन सिंह राजपूत का आलेख पढ़ने को मिला। सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं उनको पढ़ाना आता भी है या नहीं, उनको विषय का ज्ञान है या नहीं, शिक्षक की जिम्मेदारी वे जानते हैं या नहीं। पहले के शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पहले खुद पढ़ते थे। समाज में शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी है। उनके ऊपर ही छात्रों का भविष्य निर्भर है। आज छठी कक्षा के छात्र को दूसरी कक्षा का ज्ञान भी नहीं है। निःसंदेह यह शिक्षकों की निष्क्रियता को दर्शाता है। ऐसे में शिक्षकों को और जवाबदेह होने की जरूरत है। शिक्षक वही बनाया जाए जिसको पढ़ाना आता हो। उनकी बहाली में एक ही प्रक्रिया की जानी चाहिए। उनको किसी विषय पर पढ़ाने को कहा जाए। अगर वे पढ़ा पाएं तभी उनकी बहाली हो। शिक्षक कोई नौकरी नहीं है यह समाज की जरूरत है। देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। समाज का हित होगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

अशोक कुमार दुबे, पटना

वास्तविक रत्न हैं आडवाणी

'इसलिए भारत के रत्न हैं आडवाणी' शीर्षक आलेख में बलवीर पुंज ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने को बिल्कुल सही फैसला बताया है। वास्तव में आडवाणी जी ने भारत की राजनीति में शुचिता और ईमानदारी के लिए सर्वस्व अर्पण किया है। आज जब देश की राजनीति और नेताओं का एक विकृत स्वरूप लोगों की मानसिकता में एक स्थायी आकार ले चुका है उस समय लालकृष्ण आडवाणी जैसा नेता एक उदाहरण और आशा की किरण के रूप में सामने अवस्थित हो जाता है। देश की आजादी के बाद यदि किसी राजनेता ने भारतीय समाज को जनजागरण के एक नए और ऐतिहासिक दौर में प्रवेश कराया तो वह आडवाणी ही हैं। आडवाणी का सम्मान देश का सम्मान है।

वेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर, यूपी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

3.67 प्रतिशत का योगदान ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि फंड में, जिस धनराशि से पेंशन के लिए भी प्रविधान किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का प्रश्न

कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 के अंतर्गत, ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य हैं, उनके लिए न्यूनतम पेंशन का प्रविधान वर्ष 1995 में किया गया था, जिसे वर्ष 2014 में बढ़ाते हुए न्यूनतम एक हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया गया। कुछ कर्मचारी संगठन पिछले कुछ समय से मूल पेंशन की रकम में वृद्धि एसं अन्य मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं

निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली पेंशन की रकम को बढ़ाए जाने की हो रही है मांग। प्रतीकात्मक

डा. अश्विनी महाजन
प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत अभी अर्हता प्राप्त सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम एक हजार रुपये प्रतिमाह मात्र की पेंशन का प्रविधान है। मजदूर संगठनों द्वारा बार-बार यह मांग की जा रही है कि सभी सदस्यों के लिए इससे कहीं अधिक पेंशन का प्रविधान होना चाहिए। अलग-अलग संगठनों ने इसके लिए अलग-अलग पेंशन राशि की मांग की है। इस संबंध में देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और पेंशन अंतिम आहरित वेतन का आधा तय किया जाना चाहिए। साथ ही, ईपीएस इस मामले में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।

देश में कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ता के हिसाब से अलग-अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का प्रविधान है। एक तरफ 2004 से पूर्व में नियुक्त सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें सरकार उनकी पूरी सेवा अवधि के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करती है। वहीं वर्ष 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का प्रविधान है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा भविष्य निधि में योगदान दिया जाता है, जिसे नई पेंशन स्कीम के नियमों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, और उसी संचित निधि में से योगदान पर आधारित पेंशन देने का प्रविधान है। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की मांग कर रहे हैं और कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली भी कर दी है।

निजी क्षेत्र के कर्मचारी ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं। ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा राशि ईपीएफओ में जमा की जाती है और इस प्रकार से हर कर्मचारी द्वारा जमा कुल राशि पर हर साल घोषित दर के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है। अपने सेवा काल के दौरान जमा की गई राशि और साथ ही ब्याज पर भुगतान सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने या छूटने पर कर्मचारी को कर दिया जाता है। वर्ष 1995 से ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उनकी जमा राशि और ब्याज के अलावा न्यूनतम पेंशन का प्रविधान किया गया और उसे बाद में एक हजार रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाया गया। इसके बाद कर्मचारियों की निरंतर यह मांग रही है कि यह राशि अत्यंत कम है और इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा गैर ईपीएफओ कर्मचारियों एवं मजदूरों व छोटे व्यापारियों के लिए नई शुरुआत की गई है। गैर ईपीएफओ कर्मचारियों व मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन योजना के रूप में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना प्रारंभ की गई है। व्यापारी और स्व-रोजगार युक्त व्यक्तियों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। इन दोनों योजनाओं में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह तक मासिक योगदान करना होगा। एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक को, जैसा भी मामला हो, पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ तीन हजार रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन डीबीटी द्वारा प्राप्त होगी। यह भी प्रविधान किया गया है कि यदि किसी ग्राहक ने लगातार योगदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे निर्धारित दंड शुल्क के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं स्वरोजगार युक्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान मोटे तौर पर तब करना होगा, जब वर्तमान में इसके लिए जिन 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने सदस्यता ली है। यानी इस योजना के लिए राशि का प्रविधान कम से कम 20 वर्ष से पहले नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि ईपीएफओ के सदस्यों को यदि ऊंची पेंशन देनी पड़े तो उसकी देनदारी तुरंत ही ईपीएफओ के संचित फंड पर पड़ेगी और इतनी पेंशन देने के बाद ईपीएफओ की संचित राशि धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है। ऐसे में ईपीएफओ में योगदान देने वाले कर्मचारियों को भविष्य में उनकी राशि वापिस करने में कठिनाई हो सकती है।

केंद्र सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशन फंड एक एकत्रित फंड है। पेंशन निधि में व्यक्तिगत खाते नहीं रखे जाते हैं। ईपीएस, 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर उनकी पात्रता के आधार पर निकासी लाभ या पेंशन के लिए पात्र हैं। 31 मार्च 2019 तक फंड के एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार पेंशन फंड घाटे में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में नियोक्ता के योगदान के रूप में वेतन के 1.16 प्रतिशत के रूप में लगभग आठ हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया जा रहा है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन के एक हजार रुपये के भुगतान के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया जा रहा है। इसलिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाए जाने के बाद बजट से बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी और पूरा बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ईपीएफओ में इस पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लेती है तो उसे उसी अनुपात में इसका बोझ उठाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय : सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर 2022 के अपने निर्णय में 15 हजार से ऊपर के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत यह निर्देश दिया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं का योगदान 8.33 प्रतिशत की बजाय 9.49 प्रतिशत रहेगा। इस अतिरिक्त राशि का भुगतान केंद्र सरकार करती है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों का योगदान इस योजना में वेतन का 12 प्रतिशत रखा गया था। इस संबंध में जिन कर्मचारियों की पात्रता पाई गई, उनके संबंध में उन्हें डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए। इस संबंध में विकल्प उन्हीं कर्मचारियों द्वारा भरे जा सकते हैं, जो एक सितंबर 2014 को या उससे पूर्व सेवा में थे। इस संबंध में 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऊंची पेंशन देने का निर्णय सभी कर्मचारियों के लिए नहीं माना गया था। एक सितंबर 2014 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं किए गए। हालांकि कर्मचारी इस बात के लिए सहमत नहीं हैं।

वस्तुतः वर्तमान में ईपीएस, 95 स्कीम के अंतर्गत 15 हजार से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन एक हजार रुपये रखी गई थी, लेकिन 2014 से 2024 के बीच जीवन लागत में भी काफी वृद्धि हुई है, इसलिए कर्मचारियों की अधिक पेंशन की मांग न्यायोचित दिखाई देती है। लेकिन यह समझना होगा कि वर्तमान में जब सरकार एक हजार रुपये की दर से पेंशन प्रदान करती है तो उसका आंशिक भार केंद्र सरकार पर पड़ता है। इसलिए यदि पेंशन की राशि बढ़ाई जाती है तो भी केंद्रीय बजट पर इसका भार उसी अनुपात में बढ़ेगा। ऐसे में यह सामान्य निर्णय नहीं है, इसके लिए सरकार को आकलन करना पड़ेगा। इस संबंध में सरकार द्वारा एक एक्च्युरियल फर्म की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है जो पेंशन स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के प्रस्तावित फैसले के आर्थिक पक्ष का आकलन करेगा। ऐसे संकेत हैं कि ईपीएफओ और पूर्व एक्च्युरियल के वित्तीय प्रभाव के आकलन में काफी अंतर है। इसलिए ऐसा लगता है कि एक्च्युरियल द्वारा इस संबंध में किए गए आकलन का सरकार के प्रस्तावित निर्णय पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस संबंध में कर्मचारियों को पेंशन में वृद्धि हेतु कुछ समय तो लग सकता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पेंशन राशि के संबंध में सरकार कर्मचारियों के पक्ष में सोच रही है और यह बात सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से भी स्पष्ट हो रह है। परंतु संभवतः कर्मचारियों को इसके लिए कुछ प्रतीक्षा करनी होगी।

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का मसला

पेंशन से संबंधित मामले में इस विषय का एक दूसरा आयाम भी है। हाल में कुछ इस तरह की चर्चाएं हुई हैं कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने के कारण कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाई जाए। वैसे सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाती है तो युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर घट सकते हैं, इसलिए किसी भी सरकार के लिए यह कदम लोकप्रिय नहीं होगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि कार्यक्षम लोगों को उनके लिए उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था हो। उम्र बढ़ने को विकास और योगदान के समय के रूप में भी देखना होगा। कौशल को अद्यतन करने, नए कौशल हासिल करने और विकसित कार्यबल के साथ जुड़े रहने के लिए निरंतर सीखने के अवसरों का समर्थन करना होगा। अधिक आयु वाले लोगों को नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, ताकि वे नई प्रौद्योगिकी के साथ अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। वैसे हम उनकी ताकत और अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। ज्ञान साझा करने और मार्गदर्शन के लिए अनुभवी लोगों को युवा सहकर्मियों के साथ जोड़ कर परामर्श और ज्ञान हस्तांतरण का कार्य किया जा सकता है। उनका उपयोग रणनीतिक योजना और समस्या-समाधान के लिए किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक नए व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए संसाधन और सहायता प्रदान करके वरिष्ठ उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, जहां उनके कौशल की मांग अधिक है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाएं, वृद्ध वयस्क देखभाल, भावनात्मक समर्थन और सामुदायिक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त युवा पीढ़ी के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और सलाहकारों के रूप में उनके अनुभव का उपयोग का उपयोग हो सकता है। उनके कौशल और ज्ञान कला, शिल्प, कहानी कहने और ऐतिहासिक संरक्षण को समृद्ध करने में भी उनकी भूमिका हो सकती है। (डा. अश्विनी महाजन)

खरी-खरी

पलटीश बाबू की जय

डा. सुरेश कुमार मिश्रा

जब कोई गेंद किसी दीवार से टकराती है, तो टकराव में दोनों सतहों पर परमाणुओं और अणुओं की परस्पर क्रिया शामिल होती है। ये परमाणु और अणु विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, जो उनकी स्थिति, अभिविन्यास और बंधन ऊर्जा निर्धारित करते हैं। इन विद्युत चुंबकीय अंतःक्रियाओं की ताकत और प्रकृति परमाणुओं और अणुओं के प्रकार, साथ ही उनके आवेशों, द्विध्रुवीय क्षणों और अन्य गुणों पर निर्भर करती है।

टक्कर के दौरान गेंद और दीवार के परमाणुओं एवं अणुओं के बीच विद्युत चुंबकीय संपर्क होने वाली विकृति की प्रकृति और सीमा निर्धारित करते हैं। जब गेंद दीवार से टकराती है, तो गेंद की सतह और दीवार की सतह संपर्क में आती है और दोनों सतहों में परमाणुओं व अणुओं के बीच विद्युत चुंबकीय बल उनके परस्पर क्रिया और विरूपण का कारण बनते हैं। विरूपण में शामिल बलों की दिशा और परिमाण के आधार पर संपीड़न, झुकने, कतरनी या अन्य प्रकार के तनाव शामिल हो सकते हैं।

टकराव के दौरान संग्रहीत और जारी होने वाली ऊर्जा की मात्रा विरूपण की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करती है, जो बदले में गेंद व दीवार के अणुओं के बीच विद्युत चुंबकीय संपर्क पर निर्भर करती है। यदि विरूपण लोचदार है तो गेंद अपनी कुछ मूल गतिज ऊर्जा के साथ वापस उछलती है। यदि विरूपण बेलोचदार है, तो टक्कर के दौरान गेंद से दीवार पर स्थानांतरित की गई कुछ ऊर्जा गर्मी या अन्य रूपों के रूप में नष्ट हो जाएगी। यहां ऊर्जा का मतलब यह है कि पलटाव कम ऊर्जावान होगा, और गेंद अपनी कुछ मूल गतिज ऊर्जा खो देगी।

वैसे मुझे पता है कि आपको ऊपर बताई गई बातें समझ में नहीं आई हैं। इसलिए इसे आसान उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। यहां गेंद को पलटीश कुमार, दीवार को चुनाव, परमाणु और अणुओं को सरकारी जांच एजेंसियां, चुंबकीय बल को स्वार्थ, दिशा और परिमाण को सीटों की संख्या, मूल स्थिति को वापसी-पलटने के गुण और फेंकने-पकड़ने वाले को कुर्सी का भूखा समझ लें, आपको गेंद वापसी एवं पलटने का माजरा समझ में आ जाएगा।

पोस्ट

अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं। जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है।
नवजोत सिंह सिद्धू@sherryontopp

जयंत चौधरी लोकसभा में फिलहाल जीरो सीट के साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजनीति में सबसे बड़ा खतरा होता है अप्रासंगिक होने का। यही खतरा उन्हें भाजपा की ओर लेकर जा रहा है।
अरविंद चोटिया@arvindchotia

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा। साथ ही उन मंत्रियों, पक्ष-विपक्ष के विधायकों को भी याद रखा जाएगा, जिन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में वक्तव्य दिए!
अजीत सिंह राठी@AjitSinghRathi

कर्नाटक सरकार टैक्स बंटवारे की आड़ में केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। अलग दक्षिण भारतीय देश के लिए कोई भी आंदोलन इसी तर्ज पर खड़ा होगा। भाजपा उत्तर में जितनी मजबूत होगी, दक्षिण में यह मुहिम भी उतनी परवान चढ़ेगी। इससे भ्रष्ट दक्षिण भारतीय नेताओं को ईडी के साथ सौदेबाजी करने में भी सहायता मिलेगी।
मनु जोसेफ@manujosephsan

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या संप्रग शासन के समय की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र लाया जाना चाहिए?

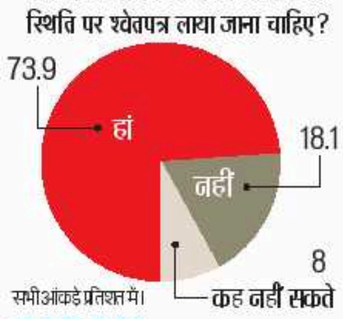

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने बलबूते 370 सीटें हासिल कर सकती है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सोचें पुत्र अजीत के जाऊं किसके साथ,
बीजेपी या फिर सपा थामूं किसका हाथ।
थामूं किसका हाथ एक पाएगा सत्ता,
दूजा लटका आज कि जैसे सूखा पत्ता।
उन्हें देख अखिलेश बाल अब अपना नोचें,
दिखता फ्यूचर डार्क यही चिंता में सोचें।
– ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

जांच आयोग की रिपोर्ट, लीपापोती का जरिया

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में पिछले दस वर्षों में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन किसी भी घटना में दोषियों को सजा न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने ऐसी हर घटना के लिए आयोग का गठन किया, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भी सौंपी, लेकिन वर्षों से वे जांच प्रतिवेदन केवल धूल खा रहे हैं। किसी भी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया। यदि हम मान लें कि विधानसभा में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होती तो शायद चर्चा से कोई ऐसा रास्ता निकलता कि आगे की घटनाओं को रोका जा सकता था। मंगलवार के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भयावह विस्फोट हुआ तो फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि इस लापरवाही की सजा दोषियों को मिलेगी या नहीं। हरदा में भी अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की मध्य प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी झाबुआ जिले के पेटलावद, बालाघाट और दमोह में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात यह हैं कि वर्ष 2015 में पेटलावद विस्फोट की जांच पूरी कर रिपोर्ट गृह विभाग को छह अप्रैल 2016 को ही सौंप दी गई, लेकिन अब तक न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही इस तरह के घटनाक्रम को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। इसका ही परिणाम है कि मंगलवार को हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट ने कई लोगों की जान ले ली। बालाघाट जिला मुख्यालय से सात किमी दूर ग्राम खैरी में स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में सात जून 2017 को तेज धमाका हुआ था। इस विस्फोट में 26 लोगों की मौत हुई थी। धमाका इतना तेज था कि बाहर खड़ा फायर ब्रिगेड का वाहन भी जल गया था। धमाकों की आवाज पांच किमी दूर तक सुनाई दी थी। शवों के चीथड़े दो किमी दूर तक गिरे थे। पटाखा फैक्ट्री चार साल से बिना अनुमति के संचालित की जा रही थी। इससे पहले 2015 में किरनापुर तहसील में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी, एक दर्जन लोग घायल हुए थे। वहीं दमोह में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से सात लोगों की जान जा चुकी है। दमोह के कोतवाली थानांतर्गत नया बाजार में बड़े पुल के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री में 30 अक्टूबर 2023 को विस्फोट हुआ था। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक अभय उर्फ छुट्टन गुप्ता सहित सात लोगों की मौत हो गई थी। मजिस्ट्रियल जांच के बाद रिपोर्ट तो आई, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद का मंजर। नईदुनिया

12 सितंबर 2015 की सुबह झाबुआ जिले के पेटलावद की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 79 लोगों की मौत और 150 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मकान में अवैध रूप से रखी जिलेटिन राड और डेटोनेटर में विस्फोट के चलते चारों ओर लाशों का ढेर लग गया था। इसमें मुख्य आरोपित पेटलावद निवासी राजेंद्र कांसवा को बनाया गया था, जिसकी इस विस्फोट में मौत बताई गई थी। पेटलावद विस्फोट घटना की जांच के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर्येंद्र कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया था। सक्सेना द्वारा जांच पूरी कर जांच प्रतिवेदन छह अप्रैल 2016 को गृह विभाग को भेजा गया था, तब से अब तक इस पर गृह विभाग में कार्यवाही ही प्रचलन में है। सक्सेना ने इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सुझावों भी दिए थे, लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाया गया। अदालत से सारे आरोपित भी बरी हो गए और सरकारी अधिकारियों को सरकार ने बचा लिया। ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

वस्तुतः इन दिनों राजनेताओं की निर्भरता एसपी-कलेक्टर और बड़े अधिकारियों पर बढ़ गई है। उनकी मनमर्जी से ही अधिकारियों को मनमाफिक पोस्टिंग मिलती है। यही कारण है कि कुर्सी बचाए रखने के लिए वे लोकसेवक के बजाय राजनेताओं के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कभी कोई कलेक्टर पटवारी का रिकार्ड चेक नहीं करता है। किसी भी एसपी का रात्रि में गश्त देखने शहर में राउंड लगाना हो, थाने का औचक निरीक्षण करना हो, यह उनकी प्राथमिकता में नहीं है। प्रशासनिक मुखिया के पद राजनीतिक हो गए हैं, वे सरकार की हां में हां ही करते रहते हैं। मुख्य सचिव हो या पुलिस महानिदेशक, कोई राजधानी के बाहर नहीं निकलना चाहता है। यही वजह है कि हम जिस सुशासन की बात करते हैं, वह मात्र सपना जैसा ही है। सरकार को चाहिए कि कानून का राज स्थापित करने के लिए अधिकारियों में भी जिम्मेदारी का भाव पैदा करे, लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे, ऐसे हादसों को रोका जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश डायरी

प्राथमिकताएं और दाने भुनाने का आग्रह

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

कुपित थे इंद्रदेव लंबे समय से। हिमाचल में कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि यलो अलर्ट भी ठगा गया। अंततः द्रवित हुए बादल। धरती को पानी मिला, पहाड़ों ने चांदी का मुकुट पहन लिया। प्यासी धरती के लिए दो बूंदें भी अमूल्य होती हैं।

इसी बीच विधायक प्राथमिकता बैठक का दो दिवसीय वार्षिक कार्य भी संपन्न हुआ। इसमें विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री को बताते हैं। प्राथमिकताओं को आवश्यक आवश्यकताएं भी कहा जा सकता है। वर्षों से विधायक प्राथमिकता बैठकें हो रही हैं और आश्चर्य यह होता है कि अब तक विधायक सड़कों, जल निकासी योजनाओं, पेयजल योजनाओं, अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के विषयों में फंसे हैं, जबकि प्रत्येक सरकार यह दावा करती है कि जितना विकास उसके कार्यकाल में हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। प्राथमिकता बैठकें ही दशकों से अपूर्ण कार्यों की शरणस्थली नहीं हैं, अपितु प्रशासन जनता के द्वार, जनसंवाद, सरकार आपके द्वार, जनमंच आदि में भी ऐसे कई दृश्य सामने आते हैं जो सत्यापित करते हैं कि कोई अपूर्ण मांग पूरी जिजीविषा के साथ अब भी सांसें ले रही है और फिर उसी मंच तक आई है, जहां से उसे आश्वासन मिल चुके हैं। इस सबमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंत्री जी की परंपरागत डांट का रूट भी निश्चित होता है... मंत्री से जिलाधीश, जिलाधीश से एसडीएम और एसडीएम से आगे वहां तक, जहां तक कोई तो है सुनने वाला। ऊना के सलांगड़ी में सरकार जब जनता के द्वार पहुंची तो वहां ओडिशा में अपने बलिदानी पुत्र का स्मारक बनाने की प्रार्थना लेकर एक वृद्ध छोटे लाल खड़े थे। 11 वर्ष पूर्व जब वाम उग्रवाद से भिड़ते हुए सुरेंद्र कुमार ने आत्मोत्सर्ग किया था, घोषणा की थी वीरभद्र सिंह सरकार ने कि स्मारक बनेगा। बलिदानी के पिता कहते हैं, उन्होंने कोई मांग नहीं की थी। सरकार ने स्वयं घोषणा की थी। उन्हें ओडिशा सरकार ने बुलाया है कि सम्मान करना है। यहां कई बार प्रशासन जनता के द्वार पहुंचा, कई जनमंच हुए, पर बलिदानी के पिता की आंखें अब तक सूनी दहलीज बनी हुई हैं।

कुल्लू के करशाला में हिमपात में फंसी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस। जागरण आर्काइव

इसलिए जब कोई विधायक अपनी प्राथमिकता बताता है तो उनके माध्यम से वस्तुतः एक दर्पण भी उपलब्ध करवाता है जिसमें उसका चेहरा सामने आता है, दृष्टि दिखती है। धरातल से जुड़ाव दिखता है। इस संदर्भ में नया यह हुआ है कि चिट्टे के आतंक की बात विधायक प्राथमिकता बैठक तक आई। सबने कहा कि यह नगरों तक ही नहीं, घरों तक आ गया है। हिमाचल प्रदेश को चिट्टे से खतरा है, यह स्वयं कानून बनाने वाले कह रहे हैं तो आशा की जानी चाहिए कि कानून और सख्त होंगे। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री तो कई बार कह चुके हैं कि हिमाचल की जेलों में जगह नहीं बची है, चिट्टे से जुड़े इतने लोग अंदर हैं। यहां विषय फिर मांग और आपूर्ति के कोण पर नहीं ठहर पाता। नशे की आपूर्ति को रोकने के लिए तो कई एजेंसियां सक्रिय हैं, किंतु मांग कम हो, उसकी तरफ ध्यान बहुत कम है। स्तर सरकारी हो या गैर सरकारी। इस सबके बावजूद सकारात्मक पक्ष यह है कि विधायकों को यह विषय प्राथमिकता वाला अनुभव हुआ।

एक विधायक ने नए जिले बनाने का आग्रह उठाया है। संसार एक वैश्विक गांव बन रहा है, राष्ट्राध्यक्ष तक इंटरनेट के माध्यम से आभासी बैठकें कर रहे हैं और यहां परामर्श यह है कि कांगड़ा के चार टुकड़े किए जाएं। जो प्रदेश डा. यशवंत सिंह परमार के समय से केंद्र की सहायता पर निर्भर है, जहां वित्तीय संकट इतना है कि गारंटियां तो दूर, रोजमर्रा का काम कठिन हो रहा है, वहां नए जिलों की मांग वही दाने भुनाने के आग्रह जैसा है जो जेब में हैं ही नहीं। कोई कह सकता है कि यह कांगड़ा का कद बराबर करने की युक्ति है, इसलिए कांगड़ा के टुकड़े न किए जाएं। कोई यह भी कह सकता है कि चूंकि छोटी इकाई को प्रशासित करना सरल होता है, इसलिए जिले बनाए जाएं। सच यह है कि कांगड़ा ने बड़ा होकर, 68 विधानसभा सीटों में से 15 सीटों वाला जिला होकर क्या पा लिया जो छोटे जिले नहीं पा सके? प्राथमिकताओं में नए जिलों का गठन आवश्यक आवश्यकता प्रतीत नहीं होता। राहत देनी है तो चंबा के सिहुंता जैसे क्षेत्रों को दें जो चंबा से दूर हैं और कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के पास हैं। गठन के बजाय पुनर्गठन की बात होती तो व्यावहारिक होती।

अब मौसम बदल जाएगा, किंतु एक प्राथमिकता यह भी होनी चाहिए कि एक अच्छे हिमपात के बाद पूर्व आपदा प्रबंधन पर जोर दिया जाए। बर्फ के गोलों से खेलना एक बात है और उन्हीं गोलों में फंसकर किसी पर्यटक को 14 किलोमीटर के लिए सात हजार रुपये देने पड़ें तो इससे पर्यटन का प्रचार नहीं हो सकता। आशा है अगली बार प्राथमिकताएं और वास्तविक होंगी।

****

अदाणी टोटल एनर्जी को ईवी चार्जर देगी सर्वोटेक पावर

नई दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जर बनाने वाली कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम्स और अदाणी टोटल एनर्जीज ई-मोबिलिटी के बीच एक वार्षिक रेट समझौता हुआ है। इसके तहत सर्वोटेक सिस्टम्स अदाणी एनर्जी को ईवी चार्जर की आपूर्ति करेगी, जो विभिन्न हवाई अड्डों और अन्य स्थानों पर लगाएं जाएंगे। इन चार्जर को लगाने की जिम्मेदारी भी सर्वोटेक पावर की होगी। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी और पहले चरण का काम शुरू हो चुका है। (प्रेट्र)

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विकास को लेकर अगले तीन दशक देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।
– टीवी नरेंद्रन, सीईओ, टाटा स्टील

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डालर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
72,152 ▼ 34.09	21,930.40 ▲ 1.10	₹63,370 ▲ ₹170	₹74,600 ▼ ₹300	₹82.96 ▼ ₹0.09	$ 79.11

एक नजर में

आज एमपीसी के फैसलों की जानकारी देंगे शक्तिकांत दास

मुंबई : आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास गुरुवार यानी आज मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी। आरबीआइ ने करीब एक वर्ष से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर बनाए रखा है। विश्लेषकों का कहना है कि महंगाई के मौजूदा स्तर को देखते हुए आरबीआइ इस बार भी रेपो दर को स्थिर रख सकता है। (प्रेट्र)

शेयर विभाजन पर केनरा बैंक बोर्ड में विमर्श 26 को

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने बुधवार को कहा कि वह स्टाक लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए शेयर विभाजन पर विचार कर रहा है। इस संबंध में 26 फरवरी को होने वाली बोर्ड बैठक में फैसला किया जाएगा। विभाजन में शेयर की कीमत कम हो जाती है और संख्या बढ़ जाती है। शेयरों का कुल मूल्य समान ही रहता है। (प्रेट्र)

भारत में आइपीओ को लेकर अभी फैसला नहीं : हुंडई

सिओल : दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर ने बुधवार को कहा कि उसने अभी तक अपनी भारतीय इकाई के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। कंपनी ने कहा कि आइपीओ को लेकर कोई फैसला होने या एक महीने के अंदर इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। रायटर ने बीते सप्ताह ही कहा था कि हुंडई मोटर अपनी भारतीय इकाई के आइपीओ लाने की योजना बना रही है। (रायटर)

दो फोल्डेबल आइफोन पर काम कर रही है एपल

बेंगलुरु : अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलाजी कंपनी एपल कम से कम दो फोल्डेबल आइफोन के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने पर काम कर रही है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से द इन्फार्मेशन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अभी यह शुरुआती चरण में हैं और 2024-2025 के दौरान इनके बड़े पैमाने पर उत्पादन की कोई योजना नहीं है। (रायटर)

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती पर चर्चा नहीं

चालू वित्त वर्ष में 69 हजार करोड़ का लाभ कमाने वाली कंपनियां अब कर रहीं घाटे में डीजल बेचने की बात

जयप्रकाश रंजन • पणजी

- अप्रैल 2022 के बाद से नहीं हुआ है पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव
- पेट्रोलियम मंत्री बोले- अस्थिर वैश्विक हालातों में फैसला करना आसान नहीं

गोवा के बेतूल में स्थित ओएनजीसी के कैंपस में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक (आइईडब्ल्यू) में दुनिया के 120 देशों के प्रतिनिधि व ऊर्जा सेक्टर के विशेषज्ञ आए हुए हैं। यहां ऊर्जा सेक्टर से जुड़े हर विषय पर चर्चा हो रही है। लेकिन उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रही जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। यह विषय है पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले नौ महीनों में सरकारी क्षेत्र की तीनों तेल मार्केटिंग कंपनियों को हुए भारी मुनाफे (संयुक्त शुद्ध लाभ- करीब 69,000 करोड़ रुपये) के बावजूद उनकी तरफ से आम जनता को राहत देने की कोई बात नहीं की जा रही। कुछ हफ्ते पहले तक पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा कमाने वाली इन तीनों कंपनियों (आइओसी, बीपीसीएल व एचपीसीएल) का कहना है कि उन्हें अब डीजल बिक्री में घाटा हो रहा है।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों के सस्ता होने की संभावना से जुड़े सवाल पर सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारी खुल कर कुछ नहीं बोल रहे। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि यह एक तार्किक सवाल है, लेकिन इसका जवाब तेल कंपनियां उचित समय पर देंगी। सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं करती। उनका कहना है कि हाल में तेल कंपनियों को जो मुनाफा हुआ है, वह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे भी वैश्विक हालात बहुत ज्यादा अस्थिर हैं जिसकी वजह से कोई भी फैसला करना आसान नहीं है। जहां तक बंपर मुनाफे का सवाल है तो अगर ऐसी ही स्थिति चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2024) में भी रहती है तो कंपनियां कीमतों में संशोधन कर सकती हैं। सरकारी तेल कंपनियां किस कीमत पर तेल खरीद रही हैं और खुदरा कीमत तय करने में किस कीमत को आधार बनाया जा रहा है, यह पूरा फार्मूला ही बहुत ही उलझा हुआ है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के डाटा को देखें तो चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत ने जून, 2023 में सबसे सस्ती कीमत (औसत मासिक कीमत) पर 74.93 डालर प्रति बैरल की दर से क्रूड खरीदा, जबकि सबसे महंगी कीमत सितंबर, 2023 में 93.54 डालर प्रति बैरल रही है। पहले दस महीनों में सिर्फ दो महीने ही 90 डालर से ज्यादा कीमत दी गई है। जनवरी में यह कीमत 79.22 डालर प्रति बैरल रही है। कहने की जरूरत नहीं कि जब अप्रैल से सितंबर, 2023 के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड 75 डालर के करीब था, तब सरकारी तेल कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया है।

मई 2022 में केंद्र ने घटाया था उत्पाद शुल्क

देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कंपनियों ने अप्रैल 2022 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया है। अंतिम बदलाव छह अप्रैल 2022 को किया गया था। तब बताया गया था कि घरेलू बाजार में पेट्रोल की बिक्री में 17 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 26-27 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 120 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। मई 2022 में केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। उसके बाद से घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर हैं।

20 लाख भारतीयों को एआइ में प्रशिक्षित करेगी माइक्रोसाफ्ट

सत्या नडेला • फाइल/एपी

- दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे माइक्रोसाफ्ट के चेयरमैन नडेला
- कहा- एआइ नियमन पर भारत और अमेरिका में सहयोग की जरूरत

मुंबई, प्रेट्र : माइक्रोसाफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने बुधवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के संबंध में नियमन बनाने के लिए भारत और अमेरिका को एक दूसरे के सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नए जमाने की यह तकनीक 'विकास को समान रूप से वितरित' कर सकती है। दो दिवसीय दौरे पर भारत आए नडेला ने कंपनी के कार्यक्रम में कहा कि माइक्रोसाफ्ट 2025 तक 20 लाख भारतीयों को एआइ में प्रशिक्षित करेगी। नडेला ने कहा कि माइक्रोसाफ्ट भारत में निवेश जारी रखेगी।

एआइ को एक शक्तिशाली तकनीक बताते हुए नडेला ने कहा कि इसको लेकर बहुपक्षीय स्तरों पर आम सहमति आवश्यक है। कंपनी के एक कार्यक्रम में नडेला ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह विशेष रूप से भारत और अमेरिका के लिए जरूरी है कि वे मानदंडों को तोड़ने के बजाए उन्हें तैयार करने के लिए सहयोग करें। उन्होंने भारत को दुनिया से सबसे तेजी से उभरते बाजारों में से एक बताया।

इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक डाटा के हवाले से नडेला ने कहा कि 2025 तक भारत में एआइ जीडीपी का आकार 500 अरब डालर होगा, जबकि उस समय कुल जीडीपी पांच ट्रिलियन डालर होगी।

तेल की मांग में चीन को पछाड़ देगा भारत

इंडिया एनर्जी वीक

- आइईए ने कहा, तेल की अतिरिक्त मांग में भारत की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी
- 2030 तक भारत की कच्चे तेल की मांग बढ़कर 66.4 लाख बैरल प्रतिदिन होगी

जागरण ब्यूरो, पणजी : आर्थिक विकास दर के मामले में चीन से आगे चल रहा भारत कच्चे तेल की मांग में भी उससे आगे निकलने वाला है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 20 से 30 वर्षों के दौरान दुनिया में कच्चे तेल की अतिरिक्त मांग में भारत की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। भारत सरकार जिस तरह से आर्थिक विकास दर की रफ्तार लगातार बढ़ाने की कोशिश में है उससे यहां पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और बढ़ सकती है। बुधवार को इंडिया एनर्जी वीक में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आइईए) ने एक रिपोर्ट में यह बात कही।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कच्चे तेल की मांग वर्ष 2023 में 54.8 लाख बैरल प्रतिदिन थी जो वर्ष 2030 तक 66.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। भारत तेल खपत के मामले में अभी चीन के बाद दूसरे स्थान पर है लेकिन 2027 में चीन पीछे छूट जाएगा। संभवतः इसका एक बड़ा कारण यह है कि चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी से लेकर 2030 तक वैश्विक तेल मांग बढ़ाने में भारत का सबसे ज्यादा योगदान होगा।

अमेरिका समेत विकसित देशों और चीन में तेल की मांग सुस्त होने लगी है, जो आगे चलकर घटने लगेगी। जबकि औद्योगिक विकास में तेजी आने से डीजल की मांग तेज होने जा रही है। विमानन सेवाओं का विस्तार होने से एटीएफ की मांग भी तेज होगी। पेट्रोल की मांग की रफ्तार बहुत तेज नहीं रहेगा क्योंकि भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ रहा है। फिर भी पेट्रोल की मांग सालाना आधार पर 0.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। इस रिपोर्ट का यह मतलब यह भी है कि अगर भारत घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ाता है तो कच्चे तेल के लिए बाहरी देशों पर उसकी निर्भरता और बढ़ेगी। भारत अभी अपनी जरूरत का 86 प्रतिशत तेल आयात करता है।

स्वच्छ ईंधन को लेकर निश्चित हो वैश्विक नीति: पुरी

जिस तरह से कच्चा तेल व कोयला उत्पादक देशों ने मनमाने तरीके से कीमतों को तय किया है, वह स्वच्छ ईंधन के मामले में नहीं होना चाहिए। भारत ने वैश्विक समुदाय को इस बारे में आगाह करते हुए कहा है कि अगर स्वच्छ ईंधन की कीमतों को तय करने को लेकर निश्चित नीति नहीं बनी तो इसका उल्टा असर होगा। इंडिया एनर्जी वीक के एक सत्र में पेट्रोलियम मंत्री ने क्रूड खरीदने को लेकर दबाव बनाने वाले देशों को आगाह करते हुए कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जहां से भी जरूरत होगी, वहां से तेल खरीदेगा। पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने कहा कि ग्रीन ईंधन की तरफ सभी को जाना है लेकिन इसकी रफ्तार इस बात से तय होगी कि कीमतों को लेकर बाजार में कितनी निश्चितता रहती है।

पांच प्रतिशत महंगी हुई शाकाहारी थाली

मुंबई, प्रेट्र : घर में तैयार होने वाली शाकाहारी थाली वार्षिक आधार पर जनवरी में पांच प्रतिशत महंगी हुई है, जबकि मांसाहारी थाली 13 प्रतिशत सस्ती हुई है। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के 'राइस रोटी रेट' अनुमान के अनुसार, पिछले महीने दाल, चावल, प्याज और टमाटर का मूल्य बढ़ने से शाकाहारी थाली महंगाई हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने प्याज और टमाटर के मूल्य में वार्षिक आधार पर 35 और 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह चावल और दालों के मूल्य में 14 और 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शाकाहारी थाली की कुल लागत में चावल की 12 प्रतिशत और दालों की नौ प्रतिशत हिस्सेदारी है। ब्रायलर (फार्म में तैयार होने वाला मुर्गा) के मूल्य में 26 प्रतिशत की कमी के चलते मांसाहारी थाली सस्ती हुई है। मांसाहारी थाली की कुल लागत में ब्रायलर की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मासिक आधार पर शाकाहारी और मांसाहारी थाली की लागत में क्रमशः छह व आठ प्रतिशत घटी है।

पेटीएम मामले से निपटना आरबीआइ का काम : जोशी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी ने बुधवार को कहा कि पेटीएम मुद्दे से निपटना आरबीआइ का काम है। सरकार का फिलहाल इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। जोशी ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) एक छोटी वित्तीय इकाई है और इसमें कोई प्रणालीगत स्थिरता संबंधी चिंता नहीं है।

नियमों का पालन न करने समेत विभिन्न चिंताओं के चलते आरबीआइ ने पीपीबीएल को 29 फरवरी के किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार करने पर रोक लगाई है। साथ ही बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। विवेक जोशी ने कहा कि यह बैंकों को विनियमित करने वाले नियामक की ओर से की गई कार्रवाई है। हमारा मानना है कि आरबीआइ ने उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था के हित में कार्रवाई की होगी। पेटीएम की पेमेंट एग्रीगेटर सब्सिडियरी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के संबंध में जोशी ने कहा कि चीन से निवेश के लिए अनुमति मांगी गई है। आवेदन की समीक्षा चल रही है। जोशी ने जहां तक मेरी समझ है, पीपीबीएल बैंक नहीं है जो खातों को स्थानांतरित करेगा। यह कार्य ग्राहकों को करना होगा।

लगातार दूसरे दिन उछले पेटीएम के शेयर

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेटीएम नाम से डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और बीएसई में यह 496.75 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। इसी तरह एनएसई में कंपनी के शेयर 9.99 प्रतिशत की बढ़त के साथ 496.25 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। बीते दो दिनों की तेजी से कंपनी का पूंजीकरण 3,720.17 करोड़ बढ़कर 31,547.62 करोड़ रुपये हो गया है।

एनएसई में नए स्तर पर एमएफ की हिस्सेदारी

नई दिल्ली, आइएएनएस : एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड (एमएफ) की हिस्सेदारी 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में 8.81 प्रतिशत के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। प्राइम इन्फोबेस के डाटा के अनुसार, 30 सितंबर 2023 में इन कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 8.73 प्रतिशत थी। बीती तिमाही के दौरान म्यूचुअल फंड्स ने एनएसई की कंपनियों मे 58,198 करोड़ रुपये का मजबूत निवेश किया है।

डाटा के अनुसार, 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में एलआइसी की निवेश हिस्सेदारी घटकर 3.64 प्रतिशत रही है। यह इसका सर्वकालिक निचला स्तर है। 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में एलआइसी की निवेश हिस्सेदारी 3.73 प्रतिशत थी। एलआइसी देश की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है। प्राइम डाटाबेस समूह के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया का कहना है कि मुनाफावसूली के चलते बीती तिमाही में बीमा कंपनियों ने 5,622 करोड़ की बिकवाली की है। इसमें एलआइसी का बड़ा हिस्सा रहा है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष समेत अन्य पर केस

रायपुर : छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (सीजीपीएससी) की वर्ष 2021 की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने केस दर्ज कर लिया है। इसमें सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव सहित अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान सजीपीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर भाजपा ने जमकर वार किया था। स्वयं प्रधानमंत्री ने भर्ती परीक्षा की जांच की गारंटी दी थी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सीबीआइ जांच की घोषणा की थी। (नईदुनिया)

जमुई में बच्चों के सामने मां के साथ दुष्कर्म, आरोपित फरार

जमुई: बिहार में जमुई जिले के झाझा में मंगलवार को बच्चों के सामने उनकी मां के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद आरोपित फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता बच्चों के साथ ससुराल से पैदल मायके आ रही थी। उसके भाई के घर में छठियारी था। रास्ते में अकेली देख राजकुमार यादव छेड़खानी करने लगा। इसका विरोध करने पर आरोपित ने उसे पकड़कर झाड़ी में ले गया और दुष्कर्म किया। घटना के वक्त उसके दोनों छोटे-छोटे बच्चे मौजूद थे। (जासं)

रामभद्राचार्य की गर्दन काटने पर इनाम घोषित करने वाला गिरफ्तार

अलीगढ़ : जगद्गुरु रामभद्राचार्य की गर्दन काटने पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित करने का वीडियो प्रसारित करने वाले युवक को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ निवासी डेविड नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करता था। उसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ था। इसमें वह जगत्गुरु रामभद्राचार्य की गर्दन काटने वाले को दो लाख व आंख फोड़ने पर तीन लाख रुपये का इनाम देने की बात कह रहा है। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। (जासं)

मनी लांड्रिंग में भारत पेपर्स का निदेशक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू

- ईडी ने की कार्रवाई, कोर्ट में पेश कर सात दिन की रिमांड पर भी लिया गया
- मामले में 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर, पंजाब व उत्तर प्रदेश में दी थी दबिश

भारत पेपर्स लिमिटेड (बीपीएल) से संबंधित 200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले और मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने कंपनी के निदेशक अनिल कुमार अग्रवाल को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने बुधवार को उन्हें जम्मू में भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआइ मामले) कोर्ट में पेश कर सात दिन की रिमांड पर लिया है। अनिल अग्रवाल जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के रहने वाले हैं।

बता दें कि ईडी की करीब 20 टीमों ने गत 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नौ परिसरों में एक साथ दबिश दी थी। सितंबर, 2006 में स्थापित बीपीएल जम्मू और लुधियाना स्थित पेपर बोर्ड पैकेजिंग उद्योग भारत बाक्स फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीबीएफआइएल) की सहयोगी कंपनी है। कंपनी के निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, जेएंडके बैंक, पीएनबी और करूर वैश्य बैंक जैसे बैंकों के साथ लगभग 200 करोड़ रुपये के ऋण की धोखाधड़ी की है।

आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने फर्जी चालान जारी करके ऋणदाता बैंकों की अनुमति के बिना आयातित व स्वदेशी मशीनरी की बिक्री की और अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए पैसे को खुर्द-बुर्द किया।

इस संबंध में 12 फरवरी, 2020 को कठुआ स्थित भारत पेपर्स लिमिटेड और अग्रवाल सहित कंपनी के निदेशकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और सीबीआइ ने मामला दर्ज किया था। मामले में शिकायत एसबीआइ लुधियाना (पंजाब) द्वारा दर्ज की गई थी। बाद में इस मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई थी।

ईडी अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत ऋण की राशि का दुरुपयोग किया गया। भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशकों में से एक अनिल अग्रवाल कंपनी के संचालन और वित्त की देखभाल कर रहे थे। वह बैंकों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। जांच के दौरान अग्रवाल के बयान एक और 6 फरवरी को दर्ज किए गए। इस दौरान उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। इसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में छह आरोपित 11 साल बाद बरी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे के एक मुकदमे में एडीजे-छह कोर्ट ने 11 साल बाद सभी छह आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 27 अगस्त, 2013 को कवाल गांव में तीन हत्याओं के बाद जनपद में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। सात सितंबर को गांव नंगला मदौड़ में हुई पंचायत के बाद जनपद में दंगा फैल गया था। अभियोजन के अनुसार फुगाना में तोड़फोड़ और मकान में आगजनी की गई थी। इस मामले में केंद्रीय सुरक्षा बल में कांस्टेबल आबिद ने तीन अक्टूबर 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था। आबिद ने बताया था कि सांप्रदायिक नारे लगाते हुए राकी, नितिन, कपिल, विकास, सुमित और योगेश ने सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ उसके घर पर हमला बोल दिया था। तोड़फोड़ की गई थी। लूटपाट कर घर में आग भी लगा दी थी।

भारत में 100 अरब डालर का निवेश कर सकते हैं कुछ यूरोपीय देश

- ईएफटीए में शामिल देशों से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंचा भारत
- अगले 15 वर्षों में किया जाएगा यह निवेश, 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान

बेंगलुरु, रायटर : भारत यूरोपीय देशों के एक छोटे समूह से व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गया है। इस सौदे के तहत यह यूरोपीय देश अगले 15 वर्षों के दौरान भारत में 100 अरब डालर का निवेश कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे का उद्देश्य देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) ने व्यापार समझौते में निवेश को लेकर वादा किया है। ईएफटीए में नार्वे, आइसलैंड, लिस्टेंस्टीन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईएफटीए देशों से आने वाले निवेश से भारत में करीब 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी। यह निवेश मौजूदा और नई मैन्यूफैक्चरिंग परियोजनाओं में किया जाएगा। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की परियोजनाएं शामिल होंगी। यह व्यापार सौदा कुछ कृषि परियोजनाओं को बाजार पहुंच सुनिश्चित करेगा। साथ ही भारतीय पेशेवर ईएफटीए देशों में आसानी से आवागमन कर सकेंगे। वाणिज्य मंत्रालय और ईएफटीए ने इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले महीने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रायटर से कहा था कि भारत में अगले कुछ वर्षों में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) 100 अरब डालर पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारत संयुक्त अरब अमीरात समेत देशों को निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है। यह देश 50 अरब डालर का निवेश करने पर विचार कर रहे हैं।

धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में यूट्यूबर रचित कौशिक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लुधियाना : लुधियाना पुलिस ने यूट्यूबर रचित कौशिक को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उप्र के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली के शाहदरा निवासी रचित को पुलिस ने बुधवार को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।

पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि रचित कौशिक के खिलाफ लुधियाना में पर्चा दर्ज था। हमारी एक टीम ने कोर्ट से गैर जमानती आर्डर लेकर यूपी पुलिस के संपर्क में आने के बाद रचित को गिरफ्तार किया है। लुधियाना के पीरूबंदा इलाके में स्थित चर्च आफ गाड के पादरी अलीशा मसीह की शिकायत पर पुलिस ने 17 जनवरी को अज्ञात पर केस दर्ज किया था। मसीह ने कहा था कि एक्स पर नो कन्वर्जन नामक हैंडल से ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला एक वीडियो अपलोड किया गया है। एक्स पर पेज रचित कौशिक द्वारा चलाया जा रहा था।

मप्र के सीधी में शिक्षक ने छात्र से थाली में उठवाया मल, उसी में परोसा गया भोजन

नईदुनिया, सीधी

- छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत
- इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित, छात्र ने मना तो शिक्षक ने पिटाई की

आदिवासी युवक पर भाजपा नेता द्वारा पेशाब किए जाने की घटना से चर्चा में आए मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक और घिनौना मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल में एक छात्र से शिक्षक ने मैला (मल) थाली में उठवाकर साफ कराया। इस थाली को छात्र से धुलवाकर कुछ देर बाद मध्याह्न भोजन उसे परोसकर दिया गया। इंटरनेट मीडिया में वीडियो प्रसारित होने के बाद यह मामला सामने आया। छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है।

यह घटना जिले के संकुल केंद्र पोखरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पोखरा सथार टोला में एक फरवरी की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला सात वर्षीय छात्र सुबह 10 बजे स्कूल पहुंचा था। शिक्षक मणिराज सिंह गोंड ने उसे कक्ष में पड़ी गंदगी (मल) साफ करने को कहा। जब छात्र ने मना किया तो शिक्षक ने उसकी पिटाई की। डर कर छात्र सफाई करने के लिए तैयार हो गया। शिक्षक ने उससे मध्याह्न भोजन की थाली में मैला उठवाया। फिर थाली धुलवाई और उसी में उको मध्याह्न भोजन की खिचड़ी परोसी गई।

छात्र के पिता ने मामले की शिकायत की है। बच्चे के बयान के आधार पर शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
– रीता त्रिपाठी, थाना प्रभारी, बहरी

शिक्षक ने कहा, मैला बच्चे नहीं हटाएंगे, तो क्या हम हटाएंगे

स्कूल से छुट्टी होने के बाद छात्र घर पहुंचा और मामले की जानकारी स्वजन को दी। दूसरे दिन उसके पिता, सरपंच कमलेंद्र सिंह, पड़ोसी मनोहर सिंह और प्राणपति सिंह के साथ स्कूल पहुंचे। छात्र के पिता ने बताया कि जब घटना के बारे में शिक्षक मणिराज सिंह गोंड से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि यदि स्कूल का मैला बच्चे नहीं हटाएंगे, तो क्या हम हटाएंगे। स्कूल में कोई चपरासी नहीं है। यह जवाब सुनकर वह घर लौट आए और बहरी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई।

उचित मूल्य की दुकानों से आनलाइन भी खरीद सकेंगे राशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- हिमाचल प्रदेश की 11 दुकानों के साथ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत
- इन दुकानों से बिना सब्सिडी सभी समान आनलाइन खरीद सकेंगे ग्राहक

उचित मूल्य की दुकानों को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) की देखरेख में चल रहे ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) प्लेटफार्म पर लाने की पहल की गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों की उचित मूल्य की 11 दुकानों (एफपीएस) को पायलट प्रोजेक्ट के तहत ओएनडीसी से जोड़ा है। इसमें ऊना की पांच और हमीरपुर जिले की छह दुकानें शामिल हैं।

इस पहल का उद्देश्य उचित मूल्य के दुकानदारों की आय को बढ़ाना है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त अनाज के अलावा इन दुकानों में उपलब्ध सभी वस्तुओं को दुकानदार बेच सकते हैं। ओएनडीसी के जरिये ग्राहक इन दुकानों से बिना सरकारी सब्सिडी सामान को आनलाइन खरीदकर मंगा सकते हैं। चोपड़ा ने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य लाभार्थियों की संतुष्टि बढ़ाने के साथ-साथ एफपीएस डीलरों के लिए आय सृजन के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि ग्राहक आनलाइन आर्डर करने के लिए एफपीएस डीलर के साथ सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। चोपड़ा ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अन्य राज्यों में भी इस माडल को लागू किया जा सकता है।

****

6 ग्रामीणों की मौत और 46 अन्य लापता हो गए दक्षिण फिलीपींस के एक गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से। लापता लोगों में 27 खननकर्मी शामिल हैं, जो भूस्खलन के समय बसों में बैठकर घर जाने का इंतजार कर रहे थे। सेना के जवानों, पुलिस और स्वयं सेवियों ने 31 ग्रामीणों को बचा लिया।

आर्थिक तंगी से जूझ रहे 12.85 करोड़ मतदाता आज चुनेंगे नई सरकार

आम चुनाव संपन्न कराने के लिए बुधवार को लाहौर में मतदान सामग्री के साथ बूथ को रवाना होतीं अधिकारी। एएफपी

पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव आज दुनिया की रहेगी नजर

आज यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोग नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और लंबे समय से भारत को अस्थिर करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। भारत के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा दुनिया की नजर भी चुनाव पर रहेगी क्योंकि पाकिस्तान की सेना चुनाव को प्रभावित करती रही है।

पाकिस्तान में कैसे होता है चुनाव

पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में 336 सीटें हैं। इनमें से 266 उम्मीदवार प्रत्यक्ष मतदान के जरिए चुने जाते हैं और 70 सीटें आरक्षित हैं। 70 आरक्षित सीटों में से 60 महिलाओं के लिए हैं और 10 गैर मुस्लिमों के लिए हैं और ये असेंबली में हर पार्टी की संख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। जीते हुए उम्मीदवार राष्ट्रीय असेंबली का हिस्सा बन जाते हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के पास चुनाव के बाद किसी भी पार्टी में शामिल होने का विकल्प होता है।

कैसे होता है प्रधानमंत्री का चुनाव

राष्ट्रीय असेंबली के निर्वाचित सदस्य नेता सदन या प्रधानमंत्री चुनने के लिए मत देते हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को सदन में बहुमत दिखाना होता है। इसका मतलब है कि उसे 169 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है।

कैसे चुना जाता है मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री चुनने और प्रांतीय सरकार बनाने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे बड़ा दल गठबंधन बनाता है।

चुनाव पर सेना का असर

पाकिस्तान की सेना की आधिकारिक तौर पर चुनाव में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे से सेना चुनाव को प्रभावित करती रही है। सेना ने पाकिस्तान बनने के बाद से लंबे समय तक शासन किया है और कई मौकों पर सरकार के फैसलों में भी दखल दिया है।

पाकिस्तान में प्रमुख मुद्दे

पाकिस्तान में नई सरकार को संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, अफगानिस्तान से रिश्ते सुधारने, इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और बिजली कटौती के मुद्दे का समाधान करना होगा। इसके अलावा नई सरकार के सामने आतंकी समूहों की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने की चुनौती होगी।

कब आएंगे चुनाव के नतीजे

पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे गुरुवार शाम से आने शुरू हो जाएंगे। वहीं आम चुनाव के आधिकारिक नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे।

सरकार बनाने के प्रमुख दावेदार

पाकिस्तान की राजनीति में तीन प्रमुख राजनीतिक दलों का दबदबा है। ये दल हैं मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पीटीआइ)। पीएमएल-एन सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। दो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। पीपीपी की अगुवाई बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। पीपीपी पीएमएल-एन के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। दक्षिण पाकिस्तान में पीपीपी का मजबूत जनाधार है। पीटीआइ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान चार आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने की वजह से चुनाव से बाहर हैं।

जागरण रिसर्च

पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी को सेना के समर्थन का मिल सकता है लाभ

इस्लामाबाद, प्रेट्र: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं के बीच गुरुवार को नई सरकार बनाने के लिए करीब 12.85 करोड़ लोग मतदान कर सकेंगे। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए देशभर में करीब साढ़े छह लाख सुरक्षाकर्मियों को उतारा गया है। माना जाता है कि सबसे आगे चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शक्तिशाली सेना का समर्थन प्राप्त है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल में होने के कारण, शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की उम्मीद है।

आम चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) व बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच मुकाबला है। लेकिन पूर्व पीएम नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएल-एन सेना की आखों का तारा बनी हुई है। इसलिए विश्लेषक उसे आगे मान रहे हैं। वहीं, जनता में अधिक लोकप्रिय पीटीआइ का चुनाव चिह्न जब्त होने से उसे निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है।

मतदान सुबह आठ बजे शुरू होगा, शाम पांच बजे तक चलेगा: पाकिस्तान के चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान गुरुवार सुबह आठ बजे शुरू हो जाएगा जो शाम पांच बजे तक चलेगा। कहा, कुल 12,85,85,760 पंजीकृत मतदाता नेशनल असेंबली के 5,121 उम्मीदवारों के लिए मतदान कर सकेंगे। उम्मीदवारों में 4,807 पुरुष, 570 महिलाएं व दो ट्रांसजेंडर हैं। इसी तरह चार प्रांतीय असेंबली के लिए 12,695 उम्मीदवार मैदान में हैं।

336 नेशनल असेंबली सीटों में से 266 पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं: पाकिस्तान की कुल 336 नेशनल असेंबली सीटों में से 266 पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। लेकिन बाजपुर सीट पर एक उम्मीदवार की हत्या के बाद वहां मतदान स्थगित हो जाने से 265 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 60 सीटें महिलाओं के लिए व 10 अल्पसंख्यों के लिए आरक्षित हैं, जो जीतने वाली पार्टियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से भरी जाती हैं। इसी तरह चार असेंबली की 749 सीटों में से 593 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। नियम के अनुसार, मतदान के 14 दिनों के भीतर चुनाव परिणाम आ जाने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा व अन्य कारणों से चुनाव परिणाम आने में देरी हो सकती है।

दशकों का यह सबसे बेकार चुनाव: पीटीआइ : जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआइ ने बुधवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान आठ फरवरी के चुनावों में अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए मनचाहा परिणाम हासिल करने के लिए शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान के हाथों दशकों में अपनी "सबसे खराब राजनीतिक इंजीनियरिंग" का गवाह बन रहा है। पीटीआइ ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया। पीटीआइ ने अपना प्रचार इंटरनेट मीडिया के सहारे ही किया।

चुनाव से पहले बम विस्फोटों से दहला पाक, 30 की मौत, 52 घायल

- बलूचिस्तान में एक उम्मीदवार व एक पार्टी के कार्यालय के बाहर हुई घटना
- ईसीपी ने कहा, प्रांत में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, तय समय से होंगे चुनाव

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिण-पश्चिम पिशिन जिले में बुधवार को चुनाव कार्यालय के बाहर हुए विस्फोट के बाद घटनास्थल पर निरीक्षण करते सुरक्षा अधिकारी। एपी

कराची, प्रेट्र: आम चुनाव से एक दिन पहले पाकिस्तान बुधवार को दो भीषण बम विस्फोटों से दहल गया। अशांत बलूचिस्तान प्रांत में इससे कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 52 अन्य घायल हो गए। पिशिन जिले में हुई पहली घटना में एक निर्दलीय उम्मीदवार के कार्यालय के बाहर एक शक्तिशाली विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। इसके घंटे भर के भीतर किला अब्दुल्ला क्षेत्र में जमीयत-उलेमा इस्लाम-पाकिस्तान के चुनाव कार्यालय के बाहर एक और बम विस्फोट हुआ, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और 22 घायल हो गए। घटना की किसी आतंकी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

बलूचिस्तान पंजगुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब्दुल्ला जेहरी ने कहा कि पिशिन जिले में निर्दलीय उम्मीदवार असफंदयार खान काकर के चुनाव कार्यालय के बाहर बम एक बैग में रखा गया था, जिसमें टाइमर लगा था। उन्होंने कहा, कुछ घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए क्वेटा ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जेहरी ने कहा कि आतंकवादी लोगों को मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने के लिए चुनाव उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन चुनाव तय समय पर हो यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को और बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने दो विस्फोटों की पुष्टि की और कहा कि गुरुवार आठ फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए प्रांत में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री जान अचकजई ने हमलों की निंदा करते हुए घोषणा की कि चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे। उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहें, हम आतंकवादियों को इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने या तोड़फोड़ करने की अनुमति नहीं दे सकते। उल्लेखनीय है कि अशांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं।

न्यूज गैलरी

चीन ने क्विंग को बनाया शेयर नियामक का नया चेयरमैन

बीजिंग : बीजिंग ने बुधवार को शेयर नियामक चीन सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन में नए प्रमुख की नियुक्ति की। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, बैंकिंग उद्योग के दिग्गज और शंघाई वित्तीय केंद्र के पूर्व उप मेयर वू क्विंग चीन सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन के नए अध्यक्ष होंगे। वह ब्रोकरों पर सख्ती के लिए जाने जाते हैं। वह यी हुइमन का स्थान लेंगे। मार्केट रेगुलेटर्स द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर करने और शार्ट सेलिंग पर अंकुश लगाने की कोशिश करने के बावजूद सोमवार को चीनी शेयर पांच साल के निचले स्तर पर आ गए। प्रापर्टी शेयर की भारी बिकवाली के कारण शंघाई और हांगकांग के पास उसके छोटे साझेदार शेनझेन के बाजार सुस्त हो गए हैं। गत वर्ष शीर्ष चीनी शेयर 11.4 प्रतिशत और हांगकांग इंडेक्स तकरीबन 14 प्रतिशत गिर गया था। (एपी)

ब्रिटेन में भारतवंशी शिक्षिका बैरोनेस फ्लैदर का निधन

लंदन: ब्रिटेन में मंगलवार को प्रमुख भारतवंशी पीयर श्रीला फ्लैदर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाउस आफ लार्ड्स में खूबसूरत साड़ियां पहनने के लिए मशहूर शिक्षिका व राजनीतिज्ञ बैरोनेस श्रीला फ्लैदर लाइफ पीयर थीं। ब्रिटेन में लार्ड अथवा लेडी उपाधि वाले व्यक्ति को लाइफ पीयर कहा जाता है। फ्लैदर को लंदन के हाइड पार्क कार्नर में मेमोरियल गेट्स बनवाने का भी श्रेय जाता है। यह स्मारक विश्वयुद्ध में शहीद राष्ट्रमंडल देशों के सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। (प्रेट्र)

चिली के पूर्व राष्ट्रपति पिनेरा की हेलीकाप्टर हादसे में मौत

विना डेल मार: चिली के पूर्व राष्ट्रपति सिबेस्टियन पिनेरा की मंगलवार को हेलीकाप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। वह 74 वर्ष के थे। चिली के आंतरिक मंत्री कैरोलिना तोहा ने पूर्व राष्ट्रपति की मौत की पुष्टि की। हालांकि अब तक हादसे के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी है। वह 2010-2014 और फिर 2018-2022 तक देश के राष्ट्रपति रहे और संकट के क्षणों में देश का नेतृत्व किया। 2010 में खननकर्मियों को बचाने व महामारी के समय टीकाकरण करने वाले पांच शीर्ष देशों में चिली का नाम शामिल होने पर उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। (एपी)

अफगानिस्तान में वाद्य यंत्र बजाने व गाने पर 10 गिरफ्तार

काबुल: अफगानिस्तान के येंगी काला जिले में वाद्य यंत्रों के साथ खेलने और गाना गाने पर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ताखर प्रांत के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि तालिबान बलों ने सोमवार को येंगी कला जिले के सफी मंगल गांव में एक घर में छापा मारकर वाद्य यंत्रों के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तालिबान के स्थानीय अधिकारियों ने भी 10 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की की है। तालिबान शासन में किसी को भी वाद्य यंत्र बजाने, नाचने, गाने की अनुमति नहीं है। (एएनआइ)

हमास 135 दिन के युद्धविराम में बंधकों की रिहाई को तैयार

- ब्लिंकन के दौरे के समय दिया प्रस्ताव, इजरायल में चर्चा
- खान यूनिस में इजरायल को झेलना पड़ रहा कड़ा प्रतिरोध

यरुशलम, रायटर : अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की इजरायल में नेताओं से मुलाकात से पहले बुधवार को हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई के संबंध गाजा में 135 दिनों के युद्धविराम की योजना का मसौदा दिया है। यह मसौदा कतर और मिस्र को दिया गया है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह मसौदा सकारात्मक है और उम्मीद है कि इसे लागू करने में खास दिक्कत नहीं आएगी। कतर और मिस्र के जरिये यह प्रस्ताव अमेरिका और इजरायल के पास भी पहुंच गया है। इजरायल ने कहा है वह हमास के प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है।

हमास ने युद्धविराम का जो प्रस्ताव दिया है उसके अनुसार 135 दिनों तक गाजा में लड़ाई नहीं होगी। इस दौरान सभी इजरायली बंधक रिहा होंगे। इसी दौरान गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी भी शुरू होगी और सैनिकों की पूर्ण वापसी के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता करके स्थायी युद्धविराम लागू होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बुधवार को तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बंधकों की रिहाई और युद्धविराम पर बात की है। सूत्रों के अनुसार ब्लिंकन ने क्षेत्रीय स्थिति का उल्लेख करते हुए गाजा में लंबे समय के युद्धविराम और राहत सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता जताई है। युद्ध के चार महीने बीत जाने के बावजूद गाजा के खान यूनिस शहर में इजरायली सेना को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को वहां पर बमबारी और गोलाबारी में दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की सूचना है। इन्हें मिलाकर गाजा में मरने वालों की कुल संख्या 27,708 हो गई है। इन लड़ाकों के ठिकानों से बड़ी संख्या में एके-47 राइफलें, ग्रेनेड और गोला-बारूद बरामद हुआ है। जबकि मिस्र सीमा के नजदीक बने रफाह शरणार्थी क्षेत्र रफाह में बीती रात इजरायली हमले में दस लोगों की मौत हुई है। मृतकों के रिश्तेदार मुहम्मद अबूंदी ने कहा, ब्लिंकन के हर दौरे से पहले हम शांति की उम्मीद लगाते हैं लेकिन वास्तव में उनके आने के समय और उसके बाद इजरायली हमले बढ़ जाते हैं। ताजा हमला भी इसी वास्तविकता का नतीजा है।

सीरिया में इजरायली मिसाइल हमले में सात मरे : सीरिया के होम्स शहर में बुधवार रात इजरायल के मिसाइल हमले में सात लोग मारे गए और 13 घायल हुए हैं। इजरायल की यह मिसाइल लेबनान के ऊपर से होते हुए सीरिया की सीमा में पहुंची और वहां उसने नुकसान पहुंचाया। इसके साथ कई अन्य मिसाइलें भी इजरायल ने दागी थीं लेकिन उन्हें सीरिया के एयर डिफेंस ने आकाश में ही नष्ट कर दिया।

फलस्तीन राष्ट्र गठन से पहले इजरायल को मान्यता नहीं देगा सऊदी : सऊदी अरब से साफ कर दिया है कि गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र के गठन से पहले वह इजरायल के साथ संबंध सामान्य नहीं करेगा और न ही उसे मान्यता देगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय का यह बयान प्रधानमंत्री व युवराज मुहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की मुलाकात के दो दिन बाद आया है। अमेरिका की कोशिश है कि इजरायल और सऊदी अरब के संबंध सामान्य हों। इससे अरब जगत में अमेरिका के हितों को ताकत मिलेगी।

इजरायल में मरे 42 फ्रांसीसियों को श्रद्धांजलि : पेरिस में बुधवार को इजरायल में सात अक्टूबर, 2023 के हमास के हमले में मारे गए 42 फ्रांसीसी नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई।

जल्द ही मालदीव में एक भी विदेशी सैनिक नहीं होगा

- राष्ट्रपति मुइज्जू ने संकेत में भारत विरोधी रुख प्रदर्शित किया
- मुइज्जू ने अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया था

मुहम्मद मुइज्जू। फाइल फोटो

माले, प्रेट्र : मालदीव की सैन्य शक्ति बढ़ाने का संकल्प जताते हुए वहां के राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि जल्द ही हम उस स्थिति में होंगे जिसमें कोई भी विदेशी सैनिक देश में मौजूद नहीं होगा। भारतीय सेना का उल्लेख किए बिना मुइज्जू ने यह बात मालदीव में मौजूद 88 भारतीय सैनिकों की ओर संकेत करते हुए कही है। ये सैनिक मालदीव को उड्डयन क्षेत्र में सहयोग देने के लिए मालदीव में हैं।

चीन की ओर झुकाव वाले मुइज्जू भारतीय सैनिकों को देश से बाहर भेजने का वादा करके चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने हैं। इसके चलते वह पहले दिन से भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में भारत के साथ उनकी वार्ता चल रही है और सैनिकों की वापसी पर सहमति भी बनी है।

अपने भारत विरोधी रुख पर कायम मुइज्जू का यह बयान उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने समुद्री सर्वे की क्षमता विकसित कर द्वीपीय देश को अपने बल पर सुरक्षित करने की बात कही थी। पूर्व की मालदीव सरकार ने समुद्री सर्वे का भारत के साथ समझौता किया था। मुइज्जू ने इस समझौते को रद करने का भी संकेत दे चुके हैं। सोमवार को संसद में राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में मुइज्जू ने चीन के प्रति झुकाव को स्पष्ट तौर प्रदर्शित किया था। कहा, भारतीय सैनिकों का पहला समूह दस मार्च से पहले देश से रवाना होगा और आखिरी समूह दस मई से पहले जाएगा। ये सैनिक मालदीव में भारत द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए दो हेलीकाप्टरों और एक विमान का संचालन व रखरखाव करते हैं। ये विमान और हेलीकाप्टर मालदीव सरकार की सहायता के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। भारत मालदीव के लोगों को वर्षों से मानवीय सहायता दे रहा है। बता दें कि मुइज्जू ने अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया था।

अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय में एक और भारतीय छात्र मृत मिला

न्यूयार्क, प्रेट्र: अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अमेरिका के इंडियाना प्रांत स्थित पर्ड्यू विश्वविद्यालय में सोमवार को एक और भारतीय छात्र का शव पड़ा मिला। वहीं गत चार फरवरी को शिकागो में एक अन्य भारतीय छात्र पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर बुरी तरह पीटा। गत जनवरी से भारतीय छात्रों पर हमले की यह छठवीं घटना है और पांच छात्रों की अब तक मौत हो चुकी है।

पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग प्रमुख एकहार्ड ग्रोल ने बताया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डाक्टरेट के अभ्यर्थी 23 वर्षीय समीर कामथ का शव सोमवार को वारेन काउंटी में पड़ा मिला। मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री लेने के बाद समीर 2021 में यहां आया था। इससे पहले इसी विश्वविद्यालय का एक अन्य छात्र नील आचार्य गत 28 जनवरी को लापता हो गया था। कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली थी। इधर, शिकागो में एक अन्य भारतीय छात्र सैयद मजाहिर अली पर घर के पास ही हमला कर दिया गया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में मजाहिर घर के निकट टहलते नजर आ रहे हैं। तभी उन पर अज्ञात हमलावर हमला कर देते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। मजाहिर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अब बांग्लादेश का और रोहिंग्या शरणार्थियों को लेने से इन्कार

ढाका, रायटर: बांग्लादेश ने बुधवार को कहा कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के आने से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में अब किसी रोहिंग्या शरणार्थी को देश में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बौद्ध बहुल म्यांमार में मुस्लिम रोहिंग्याओं को दशकों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और तकरीबन दस लाख रोहिंग्या बांग्लादेश के सीमा पर स्थित काक्स बाजार जिले में बांस व प्लास्टिक के शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश 2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद यहां भाग आए थे।

बांग्लादेश सरकार में सड़क परिवहन और सेतु मंत्री ओबैदुल क्वादर ने कहा कि अब हम और रोहिंग्याओं को देश में आने की अनुमति नहीं देंगे। वे पहले से ही हम पर भार बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय सहायता काफी कम हो चुकी है। ऐसे में हम कब तक उनका समर्थन कर सकते हैं।

इस संबंध में बांग्लादेश के शरणार्थी राहत और प्रत्यावर्तन आयुक्त मोहम्मद मिजानुर रहमान ने बताया कि म्यांमार में जुंटा शासन व विद्रोहियों के बीच जारी जंग के बीच सैकड़ों लोग बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए म्यांमार की सीमा पर एकत्रित हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश रोहिंग्याओं के अत्यधिक बोझ से दबा हुआ है।

रूस ने पूरे यूक्रेन में किया मिसाइल व ड्रोन से हमला

- यूक्रेन ने कहा, कम से कम तीन नागरिकों की मौत, गर्भवती समेत 10 घायल
- हमले के दौरान ईयू के राजनयिक वित्तीय मदद पर कर रहे थे चर्चा

रूसी सेना के मिसाइल हमले में बुधवार को >> यूक्रेन की राजधानी कीव में आवासीय इमारत में आग गई। एएफपी

कीव, एपी: रूस ने बुधवार सुबह पूरे यूक्रेन में क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलों और शहीद ड्रोन से हमला किया। इसमें कम से कम तीन नागरिकों की मौत हो गई और एक गर्भवती महिला सहित 10 अन्य घायल हो गए।

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, हमलों में राजधानी कीव सहित कम से कम तीन प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया, जहां यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक जोसेप बोरेल यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता और वित्तीय सहायता पर चर्चा कर रहे थे। गोला-बारूद और कर्मियों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को पश्चिमी मदद की सख्त जरूरत है। 24 फरवरी को युद्ध अपनी दो साल की सालगिरह के करीब है, तो कुछ दीर्घकालिक विदेशी फंडिंग भी संदेह के घेरे में है। हालांकि हाल के महीनों में लगभग 1,500 किलोमीटर की अग्रिम पंक्ति मुश्किल से ही हिली है, लेकिन लंबी दूरी के हमलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों और तोपखाने के गोला-बारूद के भंडार में क्रेमलिन की सेना का दबदबा है।

यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने दावा किया कि उन्होंने बुधवार सुबह के हमले में लांच किए गए 64 में से 44 ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बैराज ने कीव में दो लोगों की जान ले ली। क्षेत्रीय गवर्नर विटाली किम ने कहा कि हमले में दक्षिणी यूक्रेन के शहर मायकोलाइव में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जहां लगभग 20 आवासीय इमारतें और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा कीव में 13 लोग घायल हुए हैं। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनीहुबोव ने कहा, खार्कीव में एस-300 मिसाइल हमले में एक 52 वर्षीय महिला मामूली रूप से घायल हो गई।

जासूसी की चिंताओं के बीच चीन ने अंटार्कटिका में खोला पांचवां शोध केंद्र

बीजिंग, प्रेट्र : चीन ने बुधवार को अंटार्कटिका में अपना पांचवां शोध केंद्र (रिसर्च स्टेशन) शुरू कर दिया। उसने यह स्टेशन ऐसे स्थान पर स्थापित किया है जो अमेरिका के सहयोगी देशों आस्ट्रेलिया एवं न्यूजलैंड से खुफिया सिग्नलों को एकत्रित करने के लिए मुफीद है, खासकर आस्ट्रेलिया के न्यू अर्नहेम स्पेस सेंटर से राकेट टेलीमेट्री का डाटा।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने क्विनलिंग नामक इस नवनिर्मित स्टेशन को बधाई संदेश में कहा कि इस स्टेशन की शुरुआत के साथ ही देश के ध्रुवीय अनुसंधान ने सार्थक परिणाम प्राप्त किए हैं। नया स्टेशन अंटार्कटिका में रास सागर के तटीय इलाके में स्थापित किया गया है। इसका फ्लोर एरिया 5,244 वर्गमीटर है। गर्मियों में यहां अभियान दल के 80 सदस्य और सर्दियों में 30 सदस्य रह सकते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेनबिन ने कहा कि यह स्टेशन अंतरराष्ट्रीय अंटार्कटिक नियमों एवं प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से पालन करता है।

अमेरिका में 'इनमें से किसी नहीं' से हारने वाली पहली प्रत्याशी बनीं हेली

- राष्ट्रपति पद के लिए नेवादा के रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में निक्की को झटका
- रिपब्लिकन उम्मीदवारी में ट्रंप से और पिछड़ीं दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर

निक्की हेली। एएफपी

लास वेगास, एपी: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभियान तेज हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवारी की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले निक्की हेली को आयोवा व न्यू हैंपशायर के बाद नेवादा में भी झटका लगा है।

नेवादा में मंगलवार को हुए प्राइमरी चुनाव में निक्की से अधिक वोट "इनमें से कोई उम्मीदवार नहीं" के पक्ष में पड़े। निक्की को 31 और "इनमें से किसी नहीं" को 63 प्रतिशत वोट मिले। इस तरह हेली अमेरिकी इतिहास में "इनमें से किसी नहीं" से चुनाव हारने वाली राष्ट्रपति पद की पहली प्रत्याशी बन गईं हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से निक्की की अस्वीकृति है। इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन और ट्रंप के बीच मुकाबले की संभावना प्रबल होती जा रही है।

डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी में जो बाइडन के लिए कोई उल्लेखनीय चुनौती नहीं है। नेवादा में मंगलवार को हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी उन्होंने आसानी से जीत ली। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली से चुनौती मिल रही हैं। हालांकि, निक्की को आयोवा व न्यू हैंपशायर के बाद नेवादा की प्राइमरी में झटका लगा है।

अब नेवादा में गुरुवार को होने वाले काकस में डोनाल्ड ट्रंप एक मात्र प्रमुख उम्मीदवार होंगे। दरअसल, नेवादा में रिपब्लिकन पार्टी प्रत्याशी के लिए प्राइमरी और काकस दोनों प्रक्रिया अपनाई जाती है, दावेदार कोई एक विकल्प चुन सकता है। निक्की ने पार्टी द्वारा संचालित काकस के बजाय राज्य संचालित प्राइमरी चुनाव को चुना।

इस बीच निक्की ने अपने चुनाव अभियान में ट्रंप को पाखंड का बादशाह बताया, इससे दोनों दावेदारों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।

****

दैनिक जागरण
इंग्लिश चुनौती
गुरुवार 8 फरवरी, 2024 www.jagran.com

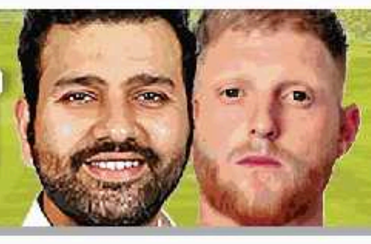

दर्शकों ने अब टेस्ट क्रिकेट दोबारा देखना शुरू कर दिया है और लोग बैजबाल क्रिकेट देखना चाहते हैं। टेस्ट क्रिकेट अब पहले से बेहतर हो गया है। अन्य टीम भी इंग्लैंड की तरह खेलना चाहती हैं। अन्य टीमों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।
– इयान बाथम, पूर्व आलराउंडर, इंग्लैंड

टेस्ट में शीर्ष गेंदबाज बनकर बुमराह ने रचा इतिहास

11 महीने से शीर्ष पर रहे अश्विन को पीछे छोड़ा लाल गेंद के प्रारूप में नंबर-एक बनने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने जसप्रीत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद जसप्रीत बुमराह बुधवार को आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। यह पहली बार है जब बुमराह ने यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले वह तीसरे स्थान तक ही पहुंच पाए थे।

विशाखापत्तनम में इस 30 साल के गेंदबाज ने नौ विकेट लेकर पैट कमिंस, कैगिसो रबादा और रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया। वह टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले देश के चौथे खिलाड़ी हैं। इससे पहले बिशन सिंह बेदी, अश्विन और रवींद्र जडेजा रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने में सफल रहे हैं। बुमराह ने इस रैंकिंग में अश्विन की जगह ली जो पिछले 11 महीने से इस सूची में शीर्ष पर थे। टेस्ट मैच में 499 विकेट लेने वाले अश्विन तीसरे स्थान पर खिसक गए। बुमराह के नाम 881 रेटिंग अंक है। वह सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने के मामले में अश्विन (904) और जडेजा (899) के बाद चौथे स्थान पर हैं। अश्विन और जडेजा मार्च 2017 में संयुक्त रूप से शीर्ष पर थे।

कपिल देव से निकले आगे : बुमराह मौजूदा समय में भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। लगातार नई उपलब्धियां प्राप्त करने वाले बुमराह ने कपिल देव को भी पीछे छोड़ दिया है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव दिसंबर 1979 से फरवरी 1980 तक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहे थे और वह कभी शीर्ष पर नहीं रहे। ऐसे ही एक अन्य पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान अपने करियर में तीसरे स्थान तक ही पहुंच सके थे। जहीर खान अक्टूबर-नवंबर 2010 में तीसरे नंबर पर रहे थे।

शानदार फार्म में चल रहे हैं बुमराह : हाल ही में सबसे कम मैचों में 150 विकेट पूरे करने वाले तेज गेंदबाज बने बुमराह इस साल शानदार फार्म में चल रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष अबतक तीन टेस्ट खेले हैं और 3.08 की इकानोमी से 23 विकेट चटका चुके हैं।

यशस्वी को भी हुआ फायदा : बल्लेबाजों की सूची में विशाखापत्तनम में दोहरा शतक जड़ने वाले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल 37 पायदान ऊपर 29वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि दूसरी पारी में शतक लगाने के बाद शुभमन गिल 14 पायदान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 38वें स्थान पर पहुंच गए।

डिविलियर्स ने हिंदी में लिखा संदेश

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी बुमराह की उपलब्धियों के कायल हैं। टेस्ट में नंबर एक गेंदबाज बनने के बाद डिविलियर्स ने हिंदी में बुमराह को संदेश दिया है। उन्होंने यू-ट्यूब पर राय व्यक्त करते हुए हिंदी में कहा, 'बुमराह शानदार गेंदबाजी करता है।'

बुमराह ने साझा किया दुख

नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में शीर्ष गेंदबाज बनने के बाद इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें लिखा है समर्थन बनाम बधाई। समर्थन वाले फोटो में एक व्यक्ति अकेला बैठा है, जबकि बधाई वाले फोटो में पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी को समर्थन की जरूरत होती है तो कोई साथ नहीं होता, लेकिन कुछ करने के बाद बधाई देने वालों की भीड़ बढ़ जाती है।

बुमराह की इंस्टाग्राम स्टोरी ● जसप्रीत बुमराह ● फाइल फोटो, प्रेट्र

अगले दो टेस्ट से भी बाहर रह सकते हैं कोहली

नई दिल्ली, जेएनएन : विराट कोहली इंग्लैंड के विरुद्ध राजकोट और रांची में होने वाले क्रमश: तीसरे और चौथे टेस्ट से भी बाहर रह सकते हैं। समझा जाता है कि उनके धर्मशाला में होने वाले पांचवें टेस्ट के लिए भी उपलब्ध रहने पर संशय है। कोहली भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से खेले गए शुरुआती टेस्ट से पहले 22 जनवरी को हैदराबाद पहुंचे थे, लेकिन उसी दिन वापस चले गए। इसके बाद बीसीसीआइ ने बताया था कि कोहली निजी कारणों के चलते शुरुआती दो टेस्ट से बाहर रहेंगे। वहीं, कार्यभार प्रबंधन के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तीसरे टेस्ट से टीम में वापसी करेंगे। चोट के कारण टीम से बाहर हुए केएल राहुल और रवींद्र जडेजा की निगरानी बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में चल रही है। माना जा रहा है कि अभी इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में फिजियो से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन चीजें सकारात्मक दिख रही हैं। तीसरा टेस्ट शुरू होने में अभी सप्ताह भर का समय है और टीम को कम से कम जडेजा या केएल में से किसी एक के उपलब्ध होने की उम्मीद है।

प्यूमा से करार पर रार : विराट कोहली प्यूमा इंडिया के साथ अपना आठ साल का करार खत्म कर सकते हैं। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कोहली इस कंपनी के साथ करार समाप्त करने के करीब हैं। माना जा रहा है कि कोहली एजिलिटास स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ेंगे। आशा की जा रही है कि कोहली ना सिर्फ ब्रांड का प्रचार करेंगे, बल्कि कंपनी में हिस्सेदारी भी रखेंगे। प्यूमा इंडिया के प्रबंध निदेशक कार्तिक बालागोपालन ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा, 'कोहली के साथ प्यूमा का रिश्ता लंबे वक्त तक जारी रहेगा।'

पंत को आइपीएल के पूरे सत्र में खेलने का भरोसा : रिकी पोंटिंग

मेलबर्न, प्रेट्र : दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने कहा कि रिषभ पंत आइपीएल के आगामी सत्र में खेलने को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन यह आक्रामक क्रिकेटर फिल्हाल विकेटकीपिंग से दूर रह सकता है। पंत दिसंबर 2022 में भीषण कार दुर्घटना गंभीर रूप से चोटिल हुए थे। इसके कारण उन्हें लिगामेंट की सर्जरी करानी पड़ी।

पोंटिंग ने कहा, 'पंत को पूरा भरोसा है कि वह मैच खेलने के लिए फिट होंगे। वह टीम में किस क्षमता में रहेंगे इसे लेकर हम अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। आपने इंटरनेट मीडिया पर उनसे जुड़ी चीजें देखी होंगी, वह सक्रिय है और अच्छी तरह से चल-दौड़ रहा है। आइपीएल शुरू होने में सिर्फ छह सप्ताह बचे हैं ऐसे में इस साल हमें उनसे विकेटकीपिंग करवाना मुश्किल होगा।

हम बस यही उम्मीद कर सकते है कि वह खेलने के लिए उपलब्ध रहे। हो सकता है कि वह सभी मैच ना खेले लेकिन अगर वह 14 लीग मैचों में से 10 मैच भी खेलता है तो यह टीम के लिए बोनस की तरह होगा।'

पंत अगर विकेटकीपिंग नहीं करेंगे तो बल्लेबाज या इंपैक्ट प्लेयर के रूप मेंखेल सकते हैं। आइपीएल 22 मार्च से शुरू हो सकता है। पोंटिंग ने कहा, 'मैं गारंटी देता हूं कि अगर मैंने अभी उससे खेलने के बारे में पूछा तो वह कहेगा कि मैं हर मैच खेलने के लिए तैयार हूं। मैं हर मैच में कीपिंग और चौथे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए तैयार हूं। हमें पिछले साल उसकी कमी बहुत अधिक खली थी। आप अगर उसके पिछले 12-13 महीने की यात्रा को देखेंगे तो उसने काफी मेहनत की है। वह खुद को भाग्यशाली समझता है कि जीवित बच गया।'

पोंटिंग ने कहा कि अगर पंत कप्तानी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे तो उनकी गैरमौजूदगी में फिर से डेविड वार्नर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे।

पोंटिंग मुख्य कोच बने

सिडनी, प्रेट्र : आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) के दूसरे सत्र से पहले बुधवार को वाशिंगटन फ्रीडम फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय-अमेरिकी व्यवसायी संजय गोविल के स्वामित्व वाली वाशिंगटन फ्रीडम के साथ दो साल का करार किया है। पोंटिंग फ्रेंचाइजी में ग्रेग शेफर्ड की जगह लेंगे। इस टी-20 लीग का दूसरा सत्र छह टीमों के बीच जुलाई में खेला जाएगा।

एक नजर में

भारतीय महिला फुटबाल टीम का सामना बांग्लादेश से

ढाका : भारतीय फुटबाल टीम गुरुवार को सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में मेजबान बांग्लादेश से भिड़ेगी तो उसकी निगाहें मिथक तोड़कर खिताब हासिल करने पर होगी। भारतीय टीम ने वर्तमान प्रतियोगिता में अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने ग्रुप चरण में भूटान (10-0) और नेपाल (4-0) को आसानी से हराया था लेकिन बांग्लादेश से वह एकमात्र गोल से हार गई थी। भारतीय टीम ने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने के कारण फाइनल में जगह बनाई। (प्रेट्र)

चमक बिखेरेंगे रामकुमार

बेंगलुरु : पाकिस्तान के विरुद्ध डेविस कप मुकाबले में भारत की जीत के नायक रहे रामकुमार रामनाथन और एन श्रीराम बालाजी सहित कई शीर्ष खिलाड़ी 12 से 18 फरवरी के बीच यहां होने वाले बेंगलुरु ओपन टेनिस में अपना भाग्य आजमाएंगे। (प्रेट्र)

अमित क्वार्टर फाइनल में

सोफिया : राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल, राष्ट्रीय चैंपियन आकाश और अभिमन्यु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को यहां 75वें स्ट्रैंड्जा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अमित ने 51 किग्रा भार वर्ग में यूक्रेन के रुडिक मैक्सीम के विरुद्ध शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया और 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला को मंगोलिया के एल्डारखिशिग बटुल्गा से होगा। आकाश (71 किग्रा) को हालांकि फ्रांस के ट्राओरे माकन की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज ने पहले दो राउंड में अच्छा खेल दिखा जिसके दम पर वह 3-1 से जीत दर्ज करने में सफल रहे। (प्रेट्र)

उदय सहारन ने दिखाई मानसिक मजबूती

नई दिल्ली, प्रेट्र : अंडर-19 विश्व कप में भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले उदय सहारन ने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी में दबाव में ना बिखरने वाली मानसिक मजबूती दिखाई है।

सेमीफाइनल में मंगलवार को भारतीय टीम 245 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 32 रन पर चार विकेट गंवा कर मुश्किल में थी। सहारन (81) ने सचिन धास (96) के साथ पांचवें विकेट के लिए 171 रन की शानदार साझेदारी कर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। भारतीय टीम लगातार पांचवीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। उदय राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वह पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल भी फाजिल्का के रहने वाले हैं। उदय मौजूदा विश्व कप में तीन अर्धशतक और एक शतक के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी की शैली 1980 और 90 के दशक की बल्लेबाजों की तरह है। उनका स्ट्राइक रेट 70 के आसपास रहता है। फिलहाल यह टीम के काम आ रहा है लेकिन सीनियर स्तर पर आने के लिए उन्हें इस मामले में मेहनत करनी होगी।

उदय सहारन ● फाइल फोटो, एक्स

मुझे भरोसा था : सचिन

बेनोनी, प्रेट्र : सेमीफाइनल में 96 रन की पारी खेलने वाले आक्रामक बल्लेबाज सचिन धास ने कहा कि 32 रन पर चार विकेट गंवाने के बावजूद मैंने और कप्तान उदय ने भरोसा नहीं छोड़ा। सचिन ने कहा, 'हमारी योजना अंत तक बल्लेबाजी करने की थी। हमें पूरा भरोसा था कि जीत तक पहुंच सकते हैं। हम आखिर तक क्रीज पर डटे नहीं रह सके, लेकिन हमने मैच जीता। यही मायने रखता है। मैं उदय को कह रहा था कि अंत तक खेलेंगे। हमें लगा कि हम समय लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे और प्रतिद्वंद्वी के गेंदबाजी आक्रमण को समझेंगे। हमारे बीच जो बातचीत हुई, वह लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की थी ताकि हम मैच का नतीजा अपने हक में करवा सकें।'

न्यूजीलैंड की दक्षिण अफ्रीका पर बड़ी जीत

क्रिकेट डायरी

माउंट मॉंगानुई, एपी : न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट के चौथे दिन नए खिलाड़ियों के साथ यहां पहुंची दक्षिण अफ्रीका को 281 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल की।

कप्तान टिम साउथी ने बीते दिन के स्कोर चार विकेट पर 179 रन पर न्यूजीलैंड की दूसरी पारी घोषित कर दी जिससे दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 529 रन का लक्ष्य मिला। काइल जैमीसन के चार और मिशेल सैंटनर के तीन विकेट से न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी को 247 रन पर समेट दी। इससे पहले, न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 511 रन बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 162 रन पर आउट कर 349 रन की बढ़त हासिल की थी। साउथी ने तब फालोआन नहीं देने का फैसला किया और पहली पारी में शतक जड़ने वाले अनुभवी केन विलियमसन ने दूसरी पारी में भी शतक लगाया। टेस्ट में यह उनका 31वां शतक था। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती चार ओवर में सलामी बल्लेबाज नील ब्रांड (3) और एडवर्ड मोरे (0) के विकेट गंवा दिए। जुबैर हमजा (36) और रेनार्ड वान टोंडर (31) ने 100 मिनट से अधिक समय तक बल्लेबाजी करके दक्षिण अफ्रीका को और किसी नुकसान के बिना लंच तक पहुंचाया। इसके तुरंत बाद दोनों गैर जिम्मेदाराना शाट खेलकर जैमीसन की गेंद पर आउट हो गए। डेविड बेडिंघम ने 96 गेंदों में करियर की सर्वश्रेष्ठ 87 रन की पारी खेलकर टीम के संघर्ष को आगे बढ़ाया। उन्होंने कीगन पीटरसन (16) के साथ पांचवें विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी भी। बेडिंघम ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की शाट गेंदों का आक्रामकता से सामना करते हुए अपनी पारी में 13 चौके और एक छक्का जड़ा।

आइपीएल की तैयारी में जुटे धोनी

आइपीएल की तैयारी के दौरान धोनी अपने मित्र की कंपनी ग्राइम स्पोर्ट्स का स्टीकर लगे बल्ले से बल्लेबाजी करते हुए ● एक्स

जैमीसन ● एएफपी

लियोन मेसी की उपस्थिति में इंटर मियामी को मिली हार

टोक्यो, एपी : हांगकांग में मैदान पर नहीं उतरने के बाद लियोन मेसी बुधवार को टोक्यो में इंटर मियामी के लिए एक प्रदर्शनी मैच में खेलने उतरे। उनकी उपस्थिति के बावजूद टीम को पेनाल्टी शूटआउट में जापान के क्लब विस्सेल कोबे से 3-4 से हार का सामना करना पड़ा।

मेसी अंतिम समय में 30 मिनट के लिए मैदान पर उतरे और टीम के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने मैच के 80वें मिनट में दो बार गोल करने का मौका बनाया, लेकिन वह विस्सेल कोबे को डिफेंस को चकमा नहीं दे सके। निर्धारित समय में स्कोर 0-0 रहने के बाद मैच का नतीजा पेनाल्टी शूटआउट के जरिये निकला जिसमें जापान के कल्ब ने बाजी मारी। मेसी ने शूटआउट में हिस्सा नहीं लिया। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 68000 है, लेकिन इस मैच को देखने सिर्फ 28614 दर्शक ही स्टेडियम पहुंचे।

लियोन मेसी ● एपी

आदिल राशिद के दम पर जीता वारियर्स

आइएलटी-20

नई दिल्ली, जेएनएन : आफ स्पिनर आदिल राशिद (चार विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी की मदद से शारजाह वारियर्स ने आइएलटी-20 टूर्नामेंट में अबूधाबी नाइटराइडर्स को सात विकेट से हराया। राशिद की फिरकी में नाइटराइजर्स के बल्लेबाज पूरी तरह उलझ गए और टीम 17.1 ओवर में महज 94 रन पर ढेर हो गई। जवाब में शारजाह वारियर्स ने 13.5 ओवर में तीन विकेट पर 95 रन बनाकर जीत दर्ज की।

लक्ष्य का पीछा करते हुए वारियर्स की शुरुआत भी धीमी रही और लेकिन निरोशन डिकवेला (30) और लियाम लिविंगस्टोन (30) ने सधी हुई पारियां खेली। नाइटराइडर्स के लिए इमाद वसीम ने दो विकेट झटके। इससे पहले, जी फाइव और एंड पिक्चर्स पर प्रसारित इस मैच में शारजाह वारियर्स ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। क्रिस वोक्स ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जो क्लार्क को खाता खोले बिना आउट कर नाइटराइडर्स को शुरुआती झटका दिया। इसके बाद हालांकि माइकल काइल पेपर (32) और अलिशान शारफु (26) ने जिम्मेदारी से खेलते हुए नाइटराइडर्स की पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई और लगा कि ये दोनों टीम को मुसीबत से उबारकर बड़े स्कोर की ओर ले जाएंगे। हालांकि राशिद ने नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर पहले अलिशान को आउट किया, फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पेपर को आउट कर एक बार फिर नाइटराइडर्स की पारी लड़खड़ा दी। नाइटराइडर्स इसके बाद वापसी नहीं कर सके और उसके बल्लेबाज राशिद की फिरकी में उलझते चले गए और 100 रन का स्कोर भी नहीं बना सके। नाइटराइडर्स की बल्लेबाजी इतनी खराब रही कि टीम के आठ बल्लेबाज दहाई अंक में भी नहीं पहुंच सके।

विकेट लेने के बाद खुश आदिल राशिद (बीच में) ● आयोजक

आयुषी ने न्यूजीलैंड की आलराउंडर अमेलिया केर का रिकार्ड तोड़ा

शाहनवाज अली ● गाजियाबाद

दिल्ली टीम की आलराउंडर आयुषी सोनी ने वनडे अंडर-23 महिला क्रिकेट ट्राफी में अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध करियर सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए नाबाद 234 रन बनाए जो महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड की आलराउंडर अमेलिया केर को पीछे छोड़ा जिन्होंने आयरलैंड के विरुद्ध नाबाद 232 रनों की पारी खेली थी।

दक्षिण अफ्रीका के साथ टी-20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा रहीं गाजियाबाद की आयुषी सोनी दिल्ली के लिए खेलती हैं। देहरादून में बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए आयुषी ने 154 गेंदों की अपनी पारी में 21 चौके और चार छक्कों जड़े। भारतीय महिला क्रिकेटरों में वनडे में सर्वाधिक स्कोर दीप्ती शर्मा के नाम है, जिन्होंने आयरलैंड के विरुद्ध 188 रन बनाए थे। आयुषी ने बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने पांच ओवर में आठ रन देते हुए एक विकेट लिया। इस उपलब्धि पर आयुषी ने दैनिक जागरण से बात करते हुए बताया कि वह लगातार इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती हैं।

आयुषी सोनी ●

राष्ट्रीय फलक

कुवैत से मुंबई में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र : नौका पर सवार होकर कुवैत से मुंबई पहुंचने वाले तीन लोगों को पुलिस ने अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मंगलवार को मुंबई पहुंचने पर तीनों ने नाव को गेटवे आफ इंडिया पर रोका था।

एक अधिकारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया नौका में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। नौका से आए तीनों लोग तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कोलाबा पुलिस ने तीनों के खिलाफ भारत में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि तीनों दो वर्ष पहले काम के संबंध में कुवैत गए थे। उन्हें कुवैत ले जाने वाले एजेंट ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बाद वे वहां से भाग निकले। लेकिन इस घटना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। नवंबर 2008 में आतंकी हमला करने वाले 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते ही मुंबई में दाखिल हुए थे। इन आतंकी हमलों में 166 लोगों की जान चली गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

अहमदाबाद में हेरीटेज महत्व का 'रानी का हजीरा' कराया गया अतिक्रमण मुक्त

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

- मुस्लिम व्यापारियों ने इस पर चारों ओर से कर रखा था कब्जा
- अहमदाबाद नगर निगम ने चलाया हेरीटेज बचाओ अभियान

अहमदाबाद नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के साथ ही हेरीटेज महत्व के स्थलों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया है। जामा मस्जिद के पीछे स्थित सुल्तान अहमद शाह के मकबरे के सामने बने 'रानी का हजीरा' से सैकड़ों वर्गमीटर का कब्जा हटाकर अब उसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मुस्लिम व्यापारियों ने इस पर चारों ओर से कब्जा जमा रखा था।

नगर निगम ने अहमदाबाद को स्वच्छ, सुंदर बनाने के साथ ही हेरीटेज महत्व के स्मारकों एवं इमारतों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान छेड़ रखा है। पुराने शहर में जामा मस्जिद के पीछे सुल्तान अहमद शाह का मकबरा है, जिसे राजा का हजीरा कहा जाता है। इसी के ठीक सामने माणक चौक से लगते रानी का हजीरा बना है। इसे मुगलई बीबी का मकबरा भी कहा जाता है,जहां सुल्तान की रानियों को दफनाया गया। इसका निर्माण 1445 में किया गया था।

गुजरात के विश्व विख्यात पारंपरिक नृत्य गरबा के पोशाक, अन्य कपड़े, हस्तशिल्प और कृत्रिम आभूषणों का यहां बड़ा बाजार है। गत दिनों महानगरपालिका ने यहां से अतिक्रमण हटाया तो इसके एक ओर बनी सीढ़ियां नजर आईं तथा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के साइन बोर्ड दिखने लगे। नगर निगम की ओर से शाहपुर, खाडिया, जमालपुर, रायखड, कालुपुर व दरियापुर इलाकों में बनी हेरीटेज इमारतों के संरक्षण के लिए इनके आसपास के अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है।

यूनेस्को ने अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड हेरीटेज सिटी घोषित कर रखा है। अहमदाबाद को छह सौ साल पहले सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था। इस शहर में 500 से 600 साल पुरानी साढ़े चार सौ इमारतें हैं। इनमें भद्र किला, जामा मस्जिद, बाबा अलीसर गंजबख्श का मकबरा, सरखेज रोजा, आजम खान-मौजम खान का रोजा, तीन दरवाजा, सिद्दी सैयद की जाली, झूलती मीनारें, पांच कुंवा, दिल्ली दरवाजा आदि शामिल हैं।

अहमदाबाद में रानी का हजीरा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साभार : हनी

पूनम पांडेय सर्विकल कैंसर अभियान की ब्रांड एंबेसडर नहीं : मंत्रालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को अभिनेत्री पूनम पांडेय को लेकर यह साफ किया है कि उनको सर्विकल कैंसर को लेकर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान कार्यक्रम का ब्रांड एंबेसडर नहीं बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण इसलिए आया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा था कि पांडेय की टीम और मंत्रालय के अफसरों के बीच उन्हें ब्रांड एंबेसडर बनाने को लेकर बातचीत चल रही है और वह इस जागरूकता अभियान का चेहरा बन सकती हैं।

32 वर्षीय अभिनेत्री पूनम पांडेय का नाम इन दिनों एक बार सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने सर्विकल कैंसर से अपनी मौत की अफवाह फैलाई थी। लेकिन एक दिन बाद सामने आकर उन्होंने सभी को चौंका दिया और कहा कि ऐसा उन्होंने इस जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में बताया था कि सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए सरकार 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को बढ़ावा देगी।

यौन उत्पीड़न मामले में हाकी खिलाड़ी वरुण के विरुद्ध सुबूत जुटा रही पुलिस

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय हाकी खिलाड़ी वरुण कुमार के विरुद्ध दुष्कर्म के आरोपों की जांच कर रही बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि वह इस मामले में सुबूत जुटा रही है। इसमें उनके और पीड़िता के बीच बातचीत के रिकार्ड और संदेश आदि शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि जांच में शामिल होने के लिए वह जल्द ही वरुण से संपर्क करेगी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। आवश्यक सुबूत जुटाए जा रहे हैं। हमने अभी तक वरुण कुमार से संपर्क नहीं किया है। वह कर्नाटक से बाहर हैं। वह अभी जिस स्थान पर अभ्यास कर रहे हैं, हमने वहां कोई टीम नहीं भेजी है। यदि वह यहां आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें अपनी टीम वहां भेजनी होगी।

उल्लेखनीय है कि एक महिला ने खिलाड़ी पर आरोप लगाया है कि जब वह नाबालिग थी तब वरुण ने कई बार उनका यौन उत्पीड़न किया। बेंगलुरु पुलिस ने खिलाड़ी के खिलाफ पास्को (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण से जुड़ा कानून) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि जब वह वरुण कुमार से मिली तब यह खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के बेंगलुरु स्थित केंद्र में अभ्यास कर रहा था। वरुण को 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें हाल ही में पंजाब पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) पद पर पदोन्नत किया गया।

- पुलिस ने कहा, जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही खिलाड़ी से किया जाएगा संपर्क

वरुण कुमार फाइल

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का
गुरुवार, 8 फरवरी, 2024

राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस (12 फरवरी)

एआइ टूल्स से बढ़ाएं कौशल

अब नए तरह के तकनीकी कौशल कार्यस्थलों पर पेशेवरों की पहचान बन रहे हैं। यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) टूल्स की मदद से ईमेल लिखने, मीटिंग सारांश, प्रेजेंटेशन, तरह-तरह के प्रोजेक्ट तैयार करने जैसे कार्य सहजता से कर लेते हैं, तो निश्चित ही दूसरों की तुलना में अधिक कार्यकुशल साबित होंगे। कुछ ऐसे ही उपयोगी एआइ टूल्स और उनकी उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र...

फोटो : प्रीपिक

अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि हमारे टेकसेवी युवाओं के लिए यह स्वर्णिम दौर है। आज नई तकनीकें और डाटा जिस तरह से हमारे कामकाज और पेशेवर दुनिया को बदलने में लगे हैं, उससे नए आर्थिक अवसरों के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का दायरा सामाजिक पिरामिड के निचले स्तर तक पहुंचने लगा है। अमेजन वेब सर्विस की एक रिपोर्ट बताती है कि गत वर्ष हर तीसरा यूरोपीय बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वीकार कर चुका था। एआइ, 5जी और क्लाउड सर्विसेज के इस दौर में डिजिटल स्किल को धार देने में एआइ टूल्स अब दुनियाभर में अविश्वसनीय ढंग से मददगार साबित हो रहे हैं। आज एआइ किसी नवउद्यमी के लिए या तो सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। कई एआइ टूल्स अब कम मेहनत, कम लागत में बेहतर और अपेक्षित सफलता की उम्मीदें पैदा करने लगे हैं।

उत्पादकता बढ़ाने में एआइ की भूमिका : उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कार्यों के संपन्न होने की गति को तीव्रतर कर देती है, चाहे हम बिजनेस में हों, स्कूल में या किसी अन्य सिस्टम का हिस्सा हों। यहां बात किसी फैंसी रोबोट की नहीं, बल्कि ऐसे इंटेलिजेंट साफ्टवेयर की हो रही है जो आपके सामान्य कार्यों को सुव्यवस्थित और स्वचालित कर रहे हैं। लेखन, अनुवाद, शोध, शिड्यूलिंग जैसे कार्यों में ये टूल्स भरोसेमंद सहायक बन रहे हैं।

चैटजीपीटी-राइटिंग प्रोजेक्ट के लिए : जेनरेटिव एआइ की ताकत से दुनिया को परिचित कराने वाला यह एआइ टूल प्रश्नों का जवाब देने, किसी लेखन का सारांश, कोई ड्राफ्ट तैयार करने, राइटिंग प्रोजेक्ट में प्रूफ रीडिंग जैसे कार्यों में सहायक है। वांछित जवाब के लिए कुछ तरकीबें सीखने और इनपुट संकेतों को परिष्कृत करने की जरूरत होती है। यह शोध और विचार मंथन में भी सहायक हो सकता है, हालांकि आपको संबंधित स्रोतों से उसका सत्यापन करना होगा। यह निश्शुल्क है, लेकिन कुछ स्पेशल टूल्स और प्लग-इन्स आदि के प्रयोग के लिए 20 डालर प्रतिमाह भुगतान कर चैटजीपीटी प्लस का एक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं। आप https://chat.openai.com/ पर जाकर इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रामरली-पेशेवर लेखन के लिए : पेशेवर लेखक वर्तनी, व्याकरण, विराम चिह्न आदि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह किसी लेखन को अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत करने में भी सहायक है। सामान्य व्याकरण के लिए निश्शुल्क प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वाक्य समायोजन, पूर्ण वाक्य लेखन या किसी साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रीमियम सर्विसेज में अपग्रेड करना होगा। https://www.grammarly.com/ पर क्लिक करें।

मिड जर्नी-इमेज तैयार करने के लिए : इमेज के लिए यह सबसे बेहतर टूल माना जाता है। इसका वी5.2 वर्जन वास्तविक प्रतीत होने वाले फोटो तैयार कर सकता है। हालांकि, एआइ जेनरेटेड इमेज में त्रुटियों की आशंका रहती है। इसमें एनिमे मोड भी है, जो प्रोफाइल पिक्चर तैयार करने से लेकर गेम डेवलपमेंट तक अनेक कार्यों में उपयोगी हो सकता है। इसे https://www.midjourney.com/home पर ट्राइ कर सकते हैं।

नोशन एआइ-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नोट टेकिंग के लिए : ड्राफ्ट, सारांश, प्रूफ रीडिंग और टोन एडजस्टमेंट जैसी खूबियों के साथ-साथ इसमें नोट तैयार करने और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स मिलते हैं। इसमें मीटिंग नोट्स से चेकलिस्ट या बुलेट प्वाइंट बनाने की सुविधा भी है। इसमें सभी नोट्स को स्टोर कर सकते हैं। इससे नए आइडिया तैयार और उसे लागू करने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर बिना कोड लिखे सीधे इन नोट्स के जरिए पूरी एक वेबसाइट तैयार की जा सकती है। इसे https://www.notion.so/product/ai पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं।

अन्य उपयोगी एआइ टूल्स

गूगल बार्ड : गूगल के एडवांस जेमिनी प्रो एलएलएम के आ जाने से अब बार्ड चैटबाट के जरिए ग्रामर की जांच भी संभव है। साथ ही इससे इमेज भी निश्शुल्क तैयार की जा सकती है।

चैटजीपीटी वायस : चैटजीपीटी एप से इस सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। यहां किसी भी भाषा में बोलकर उसका अनुवाद कर सकते हैं। साथ ही नई भाषा सीखने में भी यह मददगार हो सकता है।

एडोब पाडकास्ट : इसके लिए यूजर को केवल आडियो फाइल को अपलोड करना होगा। इसके बाद यह साफ्टवेयर साउंड क्वालिटी को बेहतर बना देगा। यह टूल रिकार्डिंग साउंड को बेहतर बनाने के लिए अनावश्यक आवाज को फिल्टर कर देता है।

टेक टिप्स

यूट्यूब पर तैयार करें प्लेलिस्ट

प्रतिदिन करोड़ों यूजर यूट्यूब पर घंटों समय बिताते हैं। यही इस वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म की लोकप्रियता का कारण भी है। कोई मनपसंद वीडियो बाद में देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे नई प्लेलिस्ट बना और मौजूद प्लेलिस्ट को मैनेज कर सकते हैं :

- नई प्लेलिस्ट के लिए प्रोफाइल आइकन यानी स्क्रीन के नीचे दाहिने कोने पर यू आइकन पर टैप करें।
- प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर न्यू प्लेलिस्ट बटन पर टैप करें।
- यूट्यूब आपके द्वारा हाल में देखे गए सभी वीडियो की सूची प्रदर्शित करेगा।
- पसंदीदा वीडियो के सामने बाक्स पर टिक कर नेक्स्ट बटन पर टैप करें।
- '+न्यू प्लेलिस्ट' पर क्लिक कर वीडियो को सुरक्षित कर लें। ड्राप डाउन मेन्यू से प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं। क्रिएट पर टैप कर सेव कर लें।
- किसी वीडियो को हटाना चाहते हैं, तो इसी तरह हटा भी सकते हैं।

टेक अपडेट

सेक्सटार्सन से बचाएगा मेटा का नया टूल

टीनएज बच्चों की आनलाइन गतिविधियों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए मेटा ने नए टूल्स शुरू किए हैं। सेक्सटार्सन में साइबर अपराधी उगाही और सेक्सुअल फेवर आदि के लिए आंतरिक तस्वीरों के दुरुपयोग की धमकी देते हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए मेटा ने 'टेक इट डाउन' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके जरिये मेटा बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की मदद कर रहा है। टेक इट डाउन के तहत 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को अंतरंग तस्वीरों का डिजिटल फिंगरप्रिंट जमा करना होगा, जिसके बाद मेटा उसकी आनलाइन कापी को खोजकर डाउन यानी डिलीट कर देगा।

वर्ग पहेली - 2538

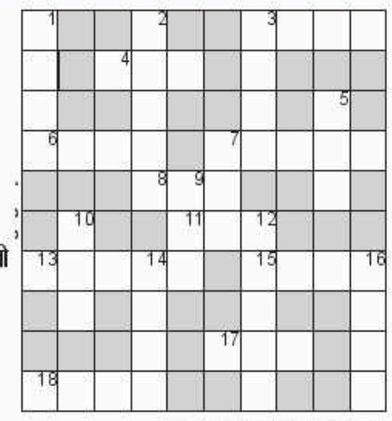

बाएं से दाएं
3. उपकार, भलाई (4)।
4. उत्कृष्ट, सबसे बड़ा (3)।
6. धक्का देना, पीसना (4)।
7. मकर के आकार का (5)।
8. रक्षा करने वाला (3)।
11. महाराष्ट्र का निवासी (3)।
13. उच्चविचार रखने का भाव (5) 15. ऋषि कात्यायन की पत्नी (4) 17. एक मीठा कंद (3)।
18. राजा की सभा (4)।

ऊपर से नीचे
1. व्यापक नियम के विरुद्ध नियम (4) 2. अलग, अलहदा (5)।
3. मृत्यु के बाद का लोक (4)।
5. रोशनी (3) 7. भूरे रंग का एक कीड़ा (3) 9. सामर्थ्य, योग्यता (3)।
10. वस्तु, चीज (3)।
12. कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष के घर मिठाई कपड़े आदि भेजना (2,3)।
14. आकार के अनुसार (4)।
16. महादेव, जिसका कंठ नीला हो (4)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

अ	न	ब	न		मे	ह	न	ता
न					न		ख	मा
मो	हि	त		मो	का		रा	लू
द				ल				म
क	सू	र		सि	तं	म्ब	र	
		से	श	री	र		तं	र
हु				मा				डु
र		लु		तं	ना		ख	रा
गि		ग		म				डि
जं	ग	दी	श्व	र		मे	ह्म	मा

जागरण सुडोकू-2538

		3			6	1		4
1		6	8				5	
7			3		1		6	9
	1		4			5		8
3	7	5			9		1	
		4		2		7		6
5	6		9				2	1
		9		1		6		
4			5		2		7	3

कल का हल

5	4	3	8	1	7	6	9	2
6	7	1	3	2	9	4	5	8
8	9	2	5	4	6	7	1	3
7	2	5	1	3	4	9	8	6
9	3	6	7	8	5	1	2	4
4	1	8	6	9	2	3	7	5
2	5	4	9	6	1	8	3	7
1	8	7	4	5	3	2	6	9
3	6	9	2	7	8	5	4	1

आज का भविष्यफल- 08 फरवरी, 2024 गुरुवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। राहुकाल : दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03:00 बजे तक। आज का दिशाशूल : दक्षिण। पर्व एवं त्योहार : रटंती कालिका पूजन आज की भद्रा : प्रात: 11:18 बजे से रात्रि के 09:41 बजे तक। विशेष : बुध अस्त पूर्व में।

कल 09 फरवरी, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल का पर्व एवं त्योहार : मौनी अमावस्या
विशेष : अमावस्या तिथि क्षय
विक्रम संवत 2080 शके 1945 उत्तरायण, माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तत्पश्चात अमावस्या श्रवण नक्षत्र तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र व्यतिपात योग तत्पश्चात वरियान योग मकर में चंद्रमा।

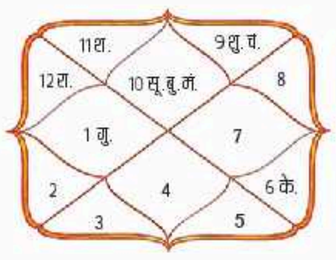

मेष : महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी।
वृष : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। देशाटन की स्थिति सुखद होगी।
मिथुन : स्थानांतरण हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।
कर्क : पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
सिंह : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की परेशानी और उलझनें रहेंगी।
कन्या : आर्थिक सफलता मिलेगी। जीविका में प्रयास सार्थक होगा।
तुला : रिश्तों में निकटता आएगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा।
वृश्चिक : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।
धनु : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
मकर : धन, सम्मान यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
कुंभ : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
मीन : शासन का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा।

इंटरनेट मीडिया

वाट्सएप मैसेजिंग को बनाएं सुरक्षित

वाट्सएप पर लोग संदेशों, विचारों, फोटोग्राफ और कई निजी जानकारियों को साझा करते हैं। हालांकि, वाट्सएप संदेशों को डिफाल्ट एंड-टू-एंड इन्क्रिप्शन के जरिये सुरक्षित रखता है। लेकिन, यूजर की छोटी सी गलती से कई बार साइबर ठगी के मामले सामने आते हैं। जानते हैं कुछ ऐसे जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में, जिनके जरिये अपने मैसेजिंग अनुभव को आप सुरक्षित बना सकते हैं...

आधिकारिक एप का ही करें प्रयोग : आपका मैसेज सुरक्षित और प्राइवेट तभी होगा, जब आप आधिकारिक एप का प्रयोग करेंगे। साथ ही एप का नवीनतम वर्जन में अपडेट होना भी जरूरी है। गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड करते समय वाट्सएप का लोगो और नाम जरूर चेक करना चाहिए। फर्जी वाट्सएप एप आपकी सुरक्षा में सेंध लगा सकता है।

टू स्टेप वेरिफिकेशन : अपने वाट्सएप अकाउंट को सुरक्षित बनाने के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके एनेबल होने पर रिसेटिंग और अकाउंट वेरिफाइ करने के लिए छह डिजिट वाले पिन के बारे में पूछा जाता है। इससे फिशिंग और स्कैमर्स से सुरक्षा मिलती है।

चुनें डिसअपीयरिंग विकल्प : संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित बनाने के लिए फोटो और मीडिया के लिए 'व्यू वंस' का विकल्प चुन सकते हैं। इससे मैसेज प्राप्तकर्ता केवल एक बार ही मैसेज को देख सकता है। उसे सेव, फारवर्ड, स्क्रीनशाट या शेयर नहीं कर सकता। व्यू वंस का विकल्प वायस नोट्स में भी उपलब्ध है।

चैटलाक से सुरक्षित करें निजी चैट : चैटलाक फीचर के जरिये निजी चैट को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें चुने गए चैट को ऐसे फोल्डर में समायोजित कर दिया जाता है, जिसे केवल यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए यूनिक पासवर्ड बनाना होता है, जो डिवाइस पासवर्ड से अलग होता है। अगर कोई आपके फोन का एक्सेस भी प्राप्त कर लेता है, तो भी वह चैटलाक तक नहीं पहुंच सकता।

स्कैम से रहें सुरक्षित : कालिंग, ईमेल या मैसेज किसी भी माध्यम से धोखाधड़ी हो सकती है। इससे बचने का तरीका यही है कि किसी की बात पर तुरंत विश्वास करने के बजाय थोड़ा विचार करें, उसकी निजी जानकारियां पता करें। यदि वह संदिग्ध प्रतीत होता है तो ब्लाक और रिपोर्ट करें। इससे आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा।

सुरक्षित स्रोत से डिवाइस लिंक करें : चैट को बेहतर बनाने के लिए वाट्सएप चार डिवाइस तक लिंक करने की सुविधा देता है। डेस्कटाप पर वाट्सएप को क्यूआर कोड से लिंक कर रहे हैं, तो web.whatsapp.com को देखें। लिंक्ड डिवाइसेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो सेटिंग में लिंक्ड डिवाइसेज पर क्लिक करें।

राष्ट्रीय फलक

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ

राज्य ब्यूरो, देहरादून

विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ विधेयक, सरकारी सेवाओं में मिलेगा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को विधानसभा ने राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण विधेयक को प्रवर समिति के संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यह विधेयक 11 अगस्त, 2004 से लागू हुआ माना जाएगा। साथ ही 11 अगस्त, 2004 और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अधीन विभिन्न राजकीय सेवाओं व पदों पर चयनित राज्य आंदोलनकारियों की नियुक्ति वैध मानी जाएगी। इस निर्णय से 2004 के बाद आंदोलनकारी आरक्षण के तहत नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों को भी राहत मिल गई है।

पुष्कर सिंह धामी। फाइल

बुधवार को सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक को प्रवर समिति के संशोधनों समेत विचार करने के लिए प्रस्तुत किया। इस पर सदन ने एक स्वर में पारित करने पर सहमति जताई। यह विधेयक गत वर्ष सितंबर में हुए सत्र में भी लाया गया था। तब कुछ संशोधनों की आवश्यकता बताते हुए प्रवर समिति को सौंपा गया। प्रवर समिति ने इसमें पूर्व में राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों की व्याख्या की। साथ ही, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए विधेयक लाने का उल्लेख किया। इसमें एक नई धारा जोड़ी गई, जिसमें 11 अगस्त 2004 के बाद समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार की गई राज्य आंदोलनकारियों के चयन व नियुक्तियों को वैध ठहराया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सात दिन से अधिक जेल में रहने अथवा घायल होने वालों को सीधी भर्ती की आयु सीमा व चयन की प्रक्रिया में एक बार शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे आंदोलनकारी की आयु 50 वर्ष से अधिक होने अथवा शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने से अनिच्छुक होने पर उसके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। सात दिन से कम जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। आश्रितों में चिह्नित आंदोलनकारियों की पत्नी, पति, आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा व पति द्वारा परित्यक्त पुत्री को शामिल किया गया है।

> राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्तराखंड बना है। मैं स्वयं खटीमा, मसूरी तथा मुजफ्फरनगर कांड का साक्षी रहा हूं। विधानसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विधेयक को पारित किया गया है। यह राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान है।
> -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड।

देश में एक साथ चुनाव कराने पर डी. राजा ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र: माकपा महासचिव डी. राजा ने बुधवार को 'एक देश, एक चुनाव' पर गठित उच्चस्तरीय समिति से मुलकात की। इस दौरान उन्होंने देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार का विरोध किया। गत वर्ष सितंबर में सरकार ने लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं, नगर पालिकाओं व पंचायतों में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर जल्द से जल्द जांच करने और सिफारिश करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अधीन समिति अधिसूचित की थी। राजा ने बताया कि उन्होंने 'एक देश, एक चुनाव' के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और समिति को 'व्यापक चुनाव सुधार' पर विचार करने का सुझाव दिया। मैंने समिति से कहा कि यह प्रस्ताव अव्यवहारिक है और बहुदलीय लोकतंत्र और विविधता वाले देश में संविधान के अनुरूप नहीं है।

मस्जिद गिराकर गुरुद्वारा रकाबगंज बनाने के बयान पर घिरे सिरसा

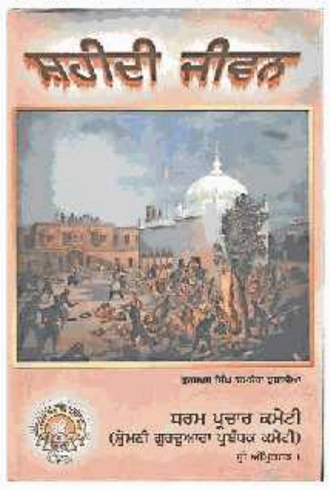

गुरबख्श सिंह शमशेर चुवालिया लिखित पुस्तक शहीदी जीवन का कवर पेज

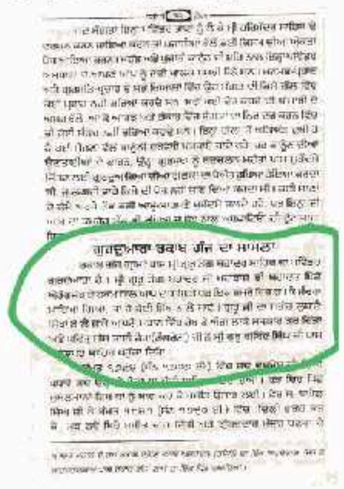
गुरबख्श सिंह शमशेर चुवालिया लिखित पुस्तक शहीदी जीवन का पेज नंबर 32

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

गुरुद्वारा रकाबगंज के निर्माण को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में एसजीपीसी की ओर से प्रकाशित एक पुस्तक का हवाला देते हुए कहा था कि गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब वही स्थान है, जहां गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का अंतिम संस्कार हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1707 में दिल्ली आकर इस स्थान पर गुरुघर बनवाया था। मुगल शासक की ओर से उसे हटाकर मस्जिद बनवा दी गई थी। वर्ष 1783 में दिल्ली फतेह करने के बाद बाबा बघेल सिंह ने मुगल शासक सुल्तान शाह आलम से कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के स्थान पर गुरुद्वारा बनेगा। उन्होंने मस्जिद ध्वस्त कर गुरुद्वारा का निर्माण कराया था।

सिरसा के इस बयान का शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और अन्य नेताओं ने विरोध किया है। उन्होंने सिरसा पर सिख इतिहास को गलत तरह से प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए श्री अकाल तख्त से कार्रवाई की मांग की है। शिअद बादल के नेता मनजीत सिंह जीके ने कहा कि सिरसा को कुछ भी बोलने से पहले तथ्यों की जानकारी करनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी का जहां बलिदान हुआ था, वहां शीशगंज गुरुद्वारा है। जहां धड़ का संस्कार हुआ था, वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब वाले स्थान को लेकर 1783 में विवाद हुआ था और उस समय की गई खोदाई में वहां से अस्थियां निकली थीं। उसके बाद वहां गुरुद्वारा बनाने का निर्णय हुआ। बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह आहलुवालिया और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने वहां गुरुद्वारा बनवाया, लेकिन कोई मस्जिद नहीं गिराई गई थी।

वर्ष 2018 में प्रकाशित पुस्तक शहीदी जीवन के आधार पर कहा : डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने सिरसा के बयान का समर्थन किया। डीएसजीएमसी के धर्म प्रचार समिति के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह कर्मसर ने कहा कि शहीदी जीवन पुस्तक के पेज नंबर-32 में गुरुद्वारा रकाबगंज का मामला शीर्षक में लिखा गया है कि संवत 1707 में जब दशमेश गुरु दिल्ली पधारे, तब उन्होंने उस स्थान पर मंजी साहिब का निर्माण किया था। कुछ समय बाद मुस्लिमों ने वहां मस्जिद बना दी थी। बाबा बघेल सिंह ने संवत 1790 दिल्ली फतेह के बाद उस मस्जिद को ध्वस्त कर गुंबदार मंदिर बनाकर गुरुद्वारा कायम किया।

> **अगर कुछ गलत लगता है, तो पुस्तक के तथ्य पर प्रश्न करना चाहिए : आरपी सिंह**
> भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी कहा कि सिरसा ने स्वयं से नहीं बल्कि एसजीपीसी की ओर से प्रकाशित पुस्तक के आधार पर बयान दिया है। यदि सरना और जीके को इसमें कुछ गलत लगता है, तो उन्हें एसजीपीसी से पुस्तक में दिए गए तथ्य को लेकर प्रश्न करना चाहिए।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

चुनाव पूर्व खरगे के हार मान लेने का दावा फर्जी

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

नई दिल्ली, जेएनएन: इंटरनेट मीडिया पर संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सदन को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार करते हुए मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 400 से अधिक सीटें जीतने जा रही है।

पड़ताल: संसद टीवी के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर हमें इस कार्यवाही का पूरा वीडियो मिला, जिसे दो फरवरी, 2024 को अपलोड किया गया है। 46.28 मिनट के फ्रेम से सुनने पर प्रसारित क्लिप का संदर्भ स्पष्ट हो जाता है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए खरगे कहते हैं, "... आपका इतना बहुमत है। पहले तो 330, 334 था, अब तो 400 पार हो रहा है। ...अपने आप को ढोल बजा रहे हैं। 400 आएंगे, 500 आएंगे। आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे।

निष्कर्ष: बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान खरगे ने विपक्ष की हार को स्वीकार करते हुए बीजेपी के 400 से अधिक सीटों के जीतने का बयान नहीं दिया था। उन्होंने बीजेपी के इस चुनावी नारे का जिक्र करते हुए कहा था कि इस बार के चुनाव में वह 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। प्रसारित क्लिप में उनके बयान के इस हिस्से को शामिल नहीं किया गया है, जिससे इसके मायने बदल जा रहे हैं।

यही तो है मोदी जी की गारंटी का कमाल! अब तो विपक्ष ने भी कर लिया स्वीकार, मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार
#ModiHaiToMumkinHai

क्या हो रहा है प्रसारित?
यूजर हिमाशु भकुनी ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, 'यही तो है मोदी जी की गारंटी का कमाल! अब तो विपक्ष ने भी कर लिया स्वीकार, मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार'। इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर यूजर्स समान संदर्भ के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं।

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फालो करने के लिए कोड स्कैन करें।

कपूरथला में 20 कुत्तों ने महिला को नोच-नोच कर मार डाला

जागरण संवाददाता, कपूरथला

पंजाब के सुल्तानपुर लोधी के गांव चुलधा में करीब 20 आवारा कुत्तों ने मंगलवार देर शाम एक महिला पर हमला कर उसे नोच-नोच कर मार डाला। इलाके में 20 दिन में आवारा कुत्ते दो बच्चों को नोच-नोच कर मार चुके हैं। उनके हमले में घायल एक महिला अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है।

मृतक महिला की फाइल फोटो

मृतक महिला 32 वर्षीय परी देवी अपने पति केवल कुमार के साथ चुलधा गांव के बाहर झुग्गी में रह कर मजदूरी करती है। वह मंगलवार को पशुओं के लिए चारा लेने खेतों की तरफ गई थी। इस दौरान 15 से 20 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। चीख सुनकर जब तक गांव वाले पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। सरपंच गुरदेव सिंह ने बताया कि कुत्तों ने महिला के हर अंग को बुरी तरह नोच खाया था। उसके सिर की खोपड़ी तक नजर आने लगी थी। कपूरथला के डीसी अमित कुमार पांचाल ने घटना का संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, इलाके में आवारा कुत्तों के हमले से मौत की यह तीसरी घटना है। पड़ोसी गांव चूहड़पुर में भी एक बच्चे की कुत्तों के काटने से मौत हो चुकी है। इससे पूर्व एक महिला भी इन कुत्तों का शिकार हो चुकी है और सिविल अस्पताल में जिंदगी व मौत के बीच झूल रही है।

दस वर्षीय बालिका को कुत्तों ने नोचकर मार डाला

जासं, सिद्धार्थनगर : उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बकरी के लिए चारा काटने खेत की तरफ गई 10 वर्षीय बालिका पर कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया और कई जगह उसको नोच डाला। गंभीर रूप से घायल बालिका को ग्रामीण उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तरन्नुम चार बहनों व दो भाइयों में सबसे छोटी थी। उसके पिता की दो वर्ष पहले बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। तरन्नुम बुधवार शाम कुछ अन्य बच्चों के साथ खेत की तरफ गई ही थी कि जहां पर कुत्तों का झुंड आ गया। उसके साथ गए बच्चे कुत्तों को देखकर भाग गए, वह भी भागी, लेकिन कुत्तों ने दौड़ाकर उसे नोचना शुरू कर दिया। साथ गए बच्चों ने इसकी जानकारी गांववालों को दी।

तरन्नुम

****

बिहार के जमालपुर में खुला भारत का पहला रेल इंजन कारखाना

1862 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया रेलवे ने बिहार के जमालपुर में भारत का पहला रेल इंजन कारखाना स्थापित किया था। कुशल कामगारों की उपलब्धता यहां कारखाना स्थापित करने की मुख्य वजह रही। भारत का पहला भाप रेल इंजन यहीं बना था। कारखाने में आज भी काम हो रहा है।

टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने कपिल

1994 में आज ही के दिन अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच में हसन तिलकरत्ने का विकेट लेकर कपिल देव टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली के 431 विकेट के वर्ल्ड रिकार्ड को तोड़कर नया रिकार्ड कायम किया था।

अपनी रेशमी आवाज से मंत्रमुग्ध कर देते थे जगजीत सिंह

गजल सम्राट जगजीत सिंह का जन्म 1941 में आज ही के दिन राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। करियर की शुरुआत 1961 में आल इंडिया रेडियो जालंधर स्टेशन पर गायन से की। 1976 में एलबम 'द आनफॉर्गेटेबल्स' से प्रसिद्धि प्राप्त की। चिट्ठी ना कोई संदेश, झुकी झुकी सी नजर, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, होश वालों को खबर क्या और होठों से छू लो तुम जैसी गजलों ने उन्हें अमर बना दिया। साथ-साथ, अर्थ, वीर जारा, तुम बिन जैसे कई फिल्मों में आवाज दी। 10 अक्टूबर, 2011 को उनका निधन हो गया।

होमोसेपियंस के हिमालय में होने का लगेगा पता

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़

मानव प्रजाति होमोसेपियंस पाषाण काल (प्रागैतिहासिक) में हिमालय में थी या नहीं इसका पता जल्द लग सकेगा। इसकी पुष्टि जनवरी में बेरीनाग में प्रकाश में आई एक गुफा, उसके भीतर उकेरी गई मानव और पशु आकृति की कार्बन डेटिंग से होगी। इसके लिए इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलेटर सेंटर(आइयूएसी) की टीम बेरीनाग आएगी। अब तक ताम्र युग से कुछ पहले मानव के हिमालय होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। 18 जनवरी को एक पर्वतारोही ने बेरीनाग में प्राचीन गुफा का पता लगाया था।

बेरीनाग में मिली गुफा के भीतर दीवार पर मानव आकृतियां और जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं। देखने में यह चित्र काफी प्राचीन लग रहे हैं। गुफा प्रकाश में आने के बाद क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी सीएस चौहान ने गुफा और चित्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गुफा और चित्र प्रागैतिहासिक काल के प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह के चित्र इससे पूर्व पिथौरागढ़ जनपद में प्रकाश में नहीं आए हैं। बिल्कुल सटीक काल का पता कार्बन डेटिंग से ही लगेगा। इस संबंध में आइयूएसी से पत्राचार किया गया है। आइयूएसी पुरातत्व विज्ञानियों की टीम बेरीनाग भेजेगी। गुफा में पशुओं के साथ 11 मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। इतिहासकारों ने पाषाण काल में होमोसेपियंस के हिमालय में निवास का पता लगाने के प्रयास पूर्व में किए थे। बनकोट और नैनीपातल में होमोसेपियंस के ताम्र युग में हिमालय में होने के प्रमाण मिले थे। बेरीनाग गुफा और मानव आकृतियों की कार्बन डेटिंग से ताम्र युग से पहले मानव के पिथौरागढ़ में होने के प्रमाण मिल सकेंगे।

बेरीनाग में मिली गुफाओं की कार्बन डेटिंग करेगी आइयूएसी

हिमालय में मानव प्रजातियों के होने का मिला प्रमाण। फाइल

बेरीनाग में मिली गुफा और चित्रों के प्रागैतिहासिक काल के होने का अनुमान है। सही काल का पता कार्बन डेटिंग से लग सकेगा। इसके लिए आइयूएसी से पत्राचार किया है। - **सीएस चौहान, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, अल्मोड़ा**

मेक्सिको पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा जहाज

रायल कैरेबियन का दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज 'आइकन आफ सीज' अपनी यात्रा के पहले चरण में अमेरिका से मेक्सिको पहुंच गया। जहाज ने क्विंटानी रू राज्य के महाहुआल में लंगर डाल दिया है। 250,800 टन वजनी यह 'महाकाय' जहाज टाइटैनिक से की गुना बड़ा है। इसमें 6610 यात्री और 2350 चालक दल के सदस्यों सहित 7960 से अधिक लोग सवार हैं। रायटर

इधर-उधर की

छात्रों ने बनाया सबसे छोटा ह्यूमनाइड रोबोट

बीजिंग, एजेंसी: हांगकांग के एक स्कूल में चार छात्रों ने दुनिया का सबसे छोटा ह्यूमनाइड रोबोट (मानव जैसा दिखने वाला रोबोट) बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम कर लिया है। स्कूल में रोबोटिक्स टीम के सदस्य आरोन हो याट फंग, इसाक जाचरी, जस्टिन वांग और हेई लेउंग ने 5.55 इंच लंबा एक रोबोट बनाया। यह रोबोट पिछले रिकार्डधारक से .44 इंच छोटा है, जो 2022 में पाकिस्तान के जैन अहमद कुरैशी द्वारा बनाया गया था। गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स के नियमों के अनुसार सबसे छोटे ह्यूमनाइड रोबोट श्रेणी के लिए रोबोट को दो पैरों पर चलने में सक्षम होने के साथ-साथ अपने कंधों, कोहनी, घुटनों व कूल्हों को हिलाने में भी सक्षम होना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि उनका रोबोट कम आय वाले छात्रों के लिए शैक्षिक उपकरण के रूप में काम करेगा।

5.55 इंच है ह्यूमनाइड रोबोट की लंबाई ● इंटरनेट मीडिया

गंध से प्रेरित होकर निर्णय लेने वाली मस्तिष्क की कोशिकाओं का लगाया पता

यूनिवर्सिटी आफ कोलोराडो स्कूल आफ मेडिसिन के शोधार्थियों ने किया अध्ययन

करंट बायोलाजी जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध

वाशिंगटन, एएनआइ: यूनिवर्सिटी आफ कोलोराडो अंसचुट्ज मेडिकल कैंपस के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि गंध मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं को ट्रिगर करती है, जो त्वरित 'गो, नो-गो' (यानी यह करें या न करें) निर्णय लेने में भूमिका निभा सकती हैं। शोध की कार्रवाई करंट बायोलाजी जर्नल में प्रकाशित हुई थी। विज्ञानियों ने हिप्पोकैम्पस पर ध्यान केंद्रित किया, जो मस्तिष्क का एक क्षेत्र है, जो स्मृति और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। वे जानते थे कि तथाकथित 'समय कोशिकाएं' हिप्पोकैम्पस कार्य में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं, लेकिन साहचर्य सीखने में उनकी भूमिका नहीं जानती थीं। यूनिवर्सिटी आफ कोलोराडो स्कूल आफ मेडिसिन में कोशिका और विकासात्मक जीवविज्ञान के प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक डिएगो रेस्ट्रेपो के अनुसार 'ये कोशिकाएं हैं, जो आपको निर्णय लेने की याद दिलाती हैं।'

हिप्पोकैम्पस (लाल निशान में चिह्नित)। फाइल

तेल की तुलना में मीठे फलों पर जल्दी दी प्रतिक्रिया: शोधकर्ताओं ने देखा कि जब चूहों को मीठा पानी देने वाली टोंटी को चाटकर फलों की गंध पर प्रतिक्रिया करने का विकल्प दिया गया, तो उन्होंने खनिज तेल की गंध के विपरीत फलों की गंध को चाटना जल्दी से सीख लिया।

सीयू स्कूल में कोशिका और विकासात्मक जीवविज्ञान में एक वरिष्ठ प्रशिक्षक मिंग मा ने कहा, 'जब फल की गंध होती है, तो वे चाटते हैं और उन्हें यह किसी उपलब्धि की तरह लगती है। जब यह खनिज तेल की गंध होती है, तो वे चाटना बंद कर देते हैं।' सीयू स्कूल आफ मेडिसिन में कोशिका और विकासात्मक जीव विज्ञान में सहायक अनुसंधान प्रोफेसर व अध्ययन के एक अन्य प्रथम लेखक और डीएससी फैबियो सिमोस डी सूजा के अनुसार जितना अधिक उन्होंने सीखा, उतनी ही अधिक कोशिकाएं उत्तेजित हुईं, जिससे गंधों की अधिक तेजी से डिकोडिंग हुई और चूहों को फलों की गंध चुनने में तेजी से कुशल होने की इजाजत मिली है। रेस्ट्रेपो के अनुसार 'इससे पहले हम नहीं जानते थे कि हिप्पोकैम्पस में निर्णय लेने वाली कोशिकाएं होती हैं।' यह शोध मस्तिष्क में निर्णय लेने में क्या शामिल है, इसके बारे में वर्तमान में उपलब्ध जानकारियों को और विस्तार देता है।

हिप्पोकैम्पस में ही निर्णय लेने की कोशिकाएं होती है

हिप्पोकैम्पस मल्टीटास्किंग है और निर्णय लेने के लिए गंध उत्प्रेरक का काम करता है। गंध नाक तक जाती है और यह घ्राण बल्ब और हिप्पोकैम्पस तक तंत्रिका संकेत भेजती है। दोनों अंग आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। रेस्ट्रेपो ने कहा, 'हिप्पोकैम्पस निर्णय-भविष्यवाणी करने वाली समय कोशिकाओं को चालू करता है जो आपको संकेत देता है कि क्या याद रखना है।' इससे पहले तक यह अवधारणा थी कि कोशिकाएं आपको केवल घटनाओं और समय की याद दिलाती हैं, जबकि यह इससे आगे का काम करता है। यहां हम न्यूरान्स में एन्कोड की गई स्मृति देखते हैं और फिर निर्णय लेते समय तुरंत पुनर्प्राप्त हो जाती है।

हाइपरटेंशन नियंत्रण में वजन कम करने वाली सर्जरी अधिक प्रभावी

अनुसंधान

शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में बताया है कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में वजन कम करने वाली बेरिएट्रिक सर्जरी दवाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों ने बेरिएट्रिक सर्जरी करवाई थी, उनका बीएमआइ कम था और वे उन लोगों की तुलना में पांच साल के बाद कम दवाओं पर निर्भर थे। जबकि केवल एंटीहाइपरटेन्सिव दवाओं का इस्तेमाल करने वालों की तुलना में ब्लड प्रेशर का स्तर भी सामान्य बना हुआ था।

शोधकर्ताओं का निष्कर्ष अमेरिकन कालेज आफ कार्डियोलाजी में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। मोटापा हृदय रोगियों के लिए एक सिद्ध जोखिम कारक है, जो हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले होते हैं। ये दोनों दिल का दौरा, स्ट्रोक हार्ट फेल होने की आशंका को बढ़ा सकते हैं। अमेरिका में वयस्कों में मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर की दर 41.9 और 45.4 प्रतिशत है। साओ पाउलो में हार्ट हास्पिटल और बीपी हास्पिटल में बेरिएट्रिक सर्जरी के विशेषज्ञ व अध्ययन के प्रमुख लेखक कार्लोस आरेलियो शियावोन ने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर सहित महत्वपूर्ण हृदय संबंधी जोखिम कारकों के खतरे को कम करने के लिए अक्सर विफलता मिलती है। शोधकर्ताओं ने गेटवे परीक्षण में 100 लोगों (जिनमें से 76 प्रतिशत महिलाएं थीं) को शामिल किया, जिनका बाडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) लगभग 36.9 किलोग्राम/एम2 था। सभी प्रतिभागियों को हाई ब्लडे प्रेशर था और वे कम से कम दो दवाओं का उपयोग कर रहे थे। पांच वर्षों में बेरिएट्रिक सर्जरी कराने वालों के लिए बीएमआइ 28.01 किलोग्राम/एम2 था और अकेले मेडिकल थेरेपी लेने वालों के लिए 36.40 किलोग्राम/एम2 था। जिन लोगों ने बेरिएट्रिक सर्जरी करवाई थी, उनके द्वारा ली जाने वाली दवाओं की संख्या में 80.7 प्रतिशत, जबकि मेडिकल थेरेपी का उपयोग करने वालों में 13.7 प्रतिशत की कमी आई। (एएनआइ)

स्क्रीन शाट

क्यों कह दिया मिनिषा ने कि फोन लेकर नहीं भागूंगी?

समंदर किनारे घूमना मिनिषा को है पसंद। (इंस्टाग्राम) minissha_lamba

अक्सर लोग सितारों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए बेताब होते हैं। सोचिए क्या हो, जब कोई सितारा किसी आम आदमी के पास आकर कहे कि क्या मैं आपकी तस्वीर खींच दूं? ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के वर्सोवा बीच (समंदर) पर, जब बचना ऐ हसीनो फिल्म की अभिनेत्री मिनिषा लांबा ने एक महिला से कहा कि मैं आपकी वीडियो बना देती हूं। दरअसल, मिनिषा बीच पर शाम की सैर कर रही थीं। उस दौरान वह इंस्टाग्राम पर लाइव आईं। वह समंदर की खूबसूरती की बात कर ही रही थीं कि उनकी नजर वहां पर खड़ी एक महिला पर पड़ी, जो अपना रील बनाने का प्रयास कर रही थी। वो अकेली थी, ऐसे में रील बनाने में उसे दिक्कत हो रही थी। मिनिषा बिना कुछ सोचे उसके पास चली गईं और कह दिया कि क्या मैं आपकी फोटो खींच दूं। इस पर उस महिला ने पहले सोचा, इस पर मिनिषा ने उन्हें हंसते हुए कहा कि मैं फोन नहीं चुराऊंगी। फोटो लेनी है, ले लेती हूं। मैं लाइव हूं कहीं नहीं जाऊंगी। महिला ने अपना फोन मिनिषा के हाथों में दे दिया और वीडियो बनवा ली। मजेदार बात यह रही कि जैसे ही मिनिषा ने बताया कि वह वर्सोवा बीच पर हैं। एक यूजर ने उनसे पूछा कि क्या मैं वर्सोवा बीच आ जाऊं, मुझे चालीस मिनट लग जाएंगे। इस पर मिनिषा ने हंसते हुए कहा कि नहीं, मैं केवल 15 मिनट तक के लिए ही यहां हूं।

पहली बार साथ दिखेंगे सिद्धांत-मृणाल

भंसाली की फिल्म में संगीतकार की भूमिका में होंगे सिद्धांत और मृणाल ● मिडडे आर्काइव

अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी फिलहाल अपने पेशेवर जीवन के स्वर्णिम दौर में हैं। उनके हाथ में न सिर्फ कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, बल्कि अब उन्हें सिनेमा जगत की अपनी मनपसंद हस्तियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इस कड़ी में हाल ही में सिद्धांत ने दैनिक जागरण से बातचीत में संकेत दिया था कि वह पीरियड फिल्मों के प्रख्यात फिल्मकार संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था, 'मैं एक फिल्म कर रहा हूं, जो कि हिंदी सिनेमा के एक बहुत जाने माने फिल्मकार के प्रोडक्शन में बन रही है। मुझे हमेशा से उनके साथ काम करने की इच्छा थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन पीरियड फिल्में बनाई है।' अब इस फिल्म से जुड़ी बाकी की जानकारियां भी सामने आ चुकी है। संजय इस फिल्म को सिद्धांत और अभिनेत्री मृणाल ठाकुर के साथ बना रहे हैं। फिल्म का निर्देशन वह स्वयं नहीं करेंगे, बल्कि वह फिल्म से बतौर निर्माता जुड़ेंगे। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में सिद्धांत और मृणाल संगीतकार की भूमिका में होंगे। फिल्म के निर्देशन की बागडोर निर्देशक रवि उद्यावर के हाथों में होगी।

अभिनेता विद्युत जामवाल एक बार फिर क्रैक: जीतेगा तो जीएगा फिल्म में दमदार एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है।

पांच देशों के एक्शन निर्देशकों के साथ किया काम: आदित्य

फिल्म क्रैक में फिर से दिखेगा विद्युत का जबरदस्त एक्शन ● जागरण आर्काइव »

एक के बाद एक हिट फिल्मों से हिंदी सिनेमा में एक्शन और स्टंट का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस चुनौती से निपटने और वैश्विक स्तर का एक्शन दिखाने के लिए फिल्मकार विदेशी एक्शन निर्देशकों के साथ काम करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। विद्युत जामवाल अभिनीत फिल्म क्रैकः जीतेगा तो जीएगा में निर्देशक आदित्य दत्त ने पांच देशों के पांच अलग एक्शन निर्देशकों के साथ काम किया है। इस बारे में आदित्य ने बताया, 'मैंने अपने एक्शन दृश्यों को भावनाओं के साथ बारीकी से लिखा था। मैं उन्हें ठीक उसी तरह से फिल्माना चाहता था। फेडरिको कुएवा स्पेन से, दक्षिण अफ्रीका के केरी ग्रेग, फ्रांस के सिरिल रफेली, जर्मनी के डेविड सजातार्स्की और बेंगलुरु के रवि वर्मा जैसे निर्देशकों ने अपना योगदान दिया है।'

गुड़ाचारी 2 में इमरान बन सकते हैं खलनायक

अखिल भारतीय फिल्म बनाने के लिए फिल्ममेकर अलग-अलग इंडस्ट्री के कलाकारों को कास्ट कर रहे हैं। ताकि उनकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक हो। इस कड़ी में गुड़ाचारी की सीक्वल में अदिवि शेष के साथ इमरान हाशमी को कास्ट करने की खबरें हैं। वर्ष 2018 में प्रदर्शित स्पाई एक्शन तेलुगु फिल्म गुड़ाचारी बाक्स आफिस पर सफल रही थी। फिल्म में अदिवि शेष और शोभिता धूलिपाला प्रमुख भूमिका में थे। अदिवि ने हिंदी सिनेमा में साल 2008 में मुंबई हमले में शहीद हुए संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक फिल्म मेजर से पदार्पण किया था। बताया जाता है कि सीक्वल का लक्ष्य पहले भाग की सफलता को आगे बढ़ाना और गुडाचारी फ्रेंचाइजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। सूत्रों का दावा है कि इमरान से फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। निर्माताओं को यकीन है कि वह इमरान और अदिवि को एकसाथ स्क्रीन पर लाने में सफल रहेंगे। इसमें उनका किरदार ग्रे होने की संभावना है।

टाइगर 3 में खलनायक की भूमिका में नजर आ चुके हैं इमरान। फाइल

अब धीमे चलना चाहते हैं अनुपम

लोग काम को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं अभिनेता अनुपम खेर हैं, जो सोचते हैं कि काम को कैसे कठिन बनाया जाए। हालांकि इसके पीछे अनुपम का अपना तर्क है। मुंबई में बुधवार को फिल्म कुछ खट्टा हो जाए के ट्रेलर लांच पर पहुंचे अनुपम से जब इस फिल्म में काम करने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह मेरी पहली हिंदी फिल्म थी, जो मैंने अमेरिका में तीन साल तक न्यू एम्स्टर्डम शो में काम करने के बाद साइन की थी। जब आप 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं और 540 से ज्यादा फिल्में कर चुके होते हैं, तो आप अपने काम को और कठिन बनाना चाहते हैं। आप अपने काम को तभी कठिन कर सकते हैं, जब आप यह सोचे कि मैं तो नवोदित कलाकार हूं। मुझे दिग्गज कलाकार का खिताब डरावना लगता है। मेरी तरफ दिग्गज की तरह देखना, यह दुनिया का नजरिया हो सकता है। मैं अपने आप को नए नजरिए से देखना चाहता हूं। हालांकि यह भी सच है कि हर वह फिल्म जो मैं करता हूं, उसमें अपना अनुभव भी जरूर डालता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि पहले मैं बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। अब धीमे चल रहा हूं, ताकि कहीं न कहीं तो पहुंच जाऊं।

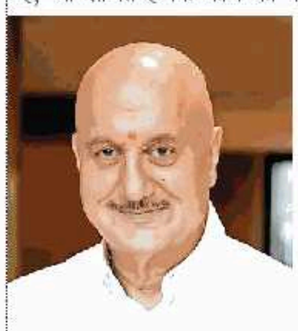

कुछ खट्टा हो जाए फिल्म में हलवाई के रोल में हैं अनुपम। फाइल

प्रेम कहानी से बालीवुड में पदार्पण करेंगे अहान

आमिर खान के बेटे जुनैद को यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) महाराजा से लांच करने की तैयारी में हैं। यह फिल्म डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज होगी। अब वह एक और नए चेहरे को लांच करने की तैयारी में हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि यशराज फिल्मस ने एक लव स्टोरी के लिए निर्देशक मोहित सूरी को साइन किया है। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही आरंभ होगी। असल खबर यह है कि इस फिल्म से अभिनेत्री अनन्या पांडेय के चचेरे भाई अहान पांडेय डेब्यू करेंगे। वाईआरएफ फिल्म को लेकर उनकी तैयारियां करा रहा था। सूत्रों का दावा है कि अहान को पांच साल पहले वाईआरएफ ने साइन किया था। इस दौरान अभिनय से जुड़ी कलाओं को लेकर उनका प्रशिक्षण चल रहा था। इसे काफी गोपनीय रखा गया था। बताया जा रहा है कि वाईआरएफ के मुखिया आदित्य चोपड़ा उन्हें भव्य तरीके से लांच करने की तैयारी में हैं। पिछले कुछ महीनों से अहान चुपचाप इस प्रेम कहानी में ढलने के लिए मोहित सूरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अहान को मोहित रोमांटिक हीरो के रूप में पेश करना चाहते हैं। अहान इस भूमिका के लिए साइन किए जाने से ही पहले कई स्क्रीनटेस्ट और आडिशन दे चुके हैं। इस अनाम फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक आरंभ हो सकती है। फिल्म की अभिनेत्री का नाम भी फिलहाल तय नहीं है। मोहित इससे पहले आशिकी 2, एक विलेन जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं।

अभिनेत्री अनन्या पांडेय के चचेरे भाई हैं अहान पांडेय ● मिडडे आर्काइव

विरासत में सबा को मां से मिला रंगमंच, तो पिता से पंजाबी संगीत

फिल्म सांग्स आफ पैराडाइज में राज बेगम की भूमिका में होंगी सबा। (इंस्टाग्राम)@ sabazad

माता-पिता से बच्चों को सिर्फ धन, संपदा और जमीन जायदाद ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक बातें भी विरासत में मिलती हैं। गायिका और अभिनेत्री सबा आजाद को उनके माता-पिता से विरासत में कला के अलग-अलग प्रारूप मिले हैं। सबा के पिता सरदार हैं और मां कश्मीरी। इसके अलावा सबा की परवरिश दिल्ली में हुई है। इससे उनकी परवरिश में कई संस्कृतियों का मिलाजुला असर रहा है। कलात्मक नजरिए से इसके प्रभाव पर सबा कहती हैं, 'मैं थिएटर परिवार से हूं। मेरा ज्यादातर वक्त ज्यादातर रिहर्सल, स्टेज, कभी स्टेज के पीछे तो कभी नाटक करते हुए गुजरता था। मेरे माता-पिता बहुत ज्यादा संगीत सुनते थे। उनके पास म्यूजिक रिकार्ड्स और टेप का बहुत बड़ा संग्रह था। घर में कभी शांति नहीं होती थी, कोई न कोई गाना तो हमेशा बज रहा होता था। मुझे संगीत से जुड़े शब्दों की समझ वहां से आई। मेरी दादा-दादी पंजाब में रहते थे, तो उनकी तरफ से मुझे बहुत सारा पंजाबी संगीत और लोक संगीत सुनने को मिला। फिर मां की तरफ से मुझे थिएटर से जुड़ी जानकारियां मिली। मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी कर रही हूं, उसका कारण मेरे माता-पिता ही है। अगर वो नहीं होते तो मैं इतनी सारी चीजों के बारे में नहीं जान पाती।' सबा आगामी दिनों में बायोपिक सांग्स आफ पैराडाइज में कश्मीर की गायिका राज बेगम की भूमिका में नजर आएंगी।

धर्मक्षेत्र के नाम से बन रही है गंगाजल 3 : प्रकाश झा

धर्मक्षेत्र की कहानी पर काम कर रहे हैं प्रकाश झा ● मिडडे आर्काइव

फ्रेंचाइज और सीक्वल फिल्मों का जमाना है। कई वर्ष पुरानी फिल्मों की सीक्वल बन रही है, तो ऐसे में भला फिल्मकार प्रकाश झा क्यों पीछे रहें। वह पहले ही राजनीति फिल्म की सीक्वल राजधर्म लेकर आने की तैयारी में हैं। वहीं अब 2003 में रिलीज हुई फिल्म गंगाजल की फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म की कहानी भी वह तैयार कर चुके हैं। इसमें ट्विस्ट यह है कि प्रकाश गंगाजल फ्रेंचाइज के नाम से उस फिल्म को नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि इस फिल्म का नाम उन्हें मिल नहीं पाया है। प्रकाश झा कहते हैं, 'गंगाजल फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म का शीर्षक धर्मक्षेत्र है। गंगाजल का शीर्षक मिलने में दिक्कत हो रही थी। वह कुछ कानूनी पचड़ों में फंस गई, तो फिर मैंने उस नाम को लेने का ख्याल छोड़ दिया।' धर्मक्षेत्र फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश बताते हैं, 'फिल्म में हेड कान्स्टेबल की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म की कहानी लिखी जा चुकी है।' धर्मक्षेत्र फिल्म में किसी पुलिस अधिकारी की बजाय हेड कान्स्टेबल की कहानी लाने का कारण बताते हुए आगे प्रकाश कहते हैं, 'रोहित शेट्टी (निर्देशक) की फिल्मों में बनियान में सौ पुलिस वाले गाना गाते हैं। वह देखकर लगता है कि वास्तविक जीवन में तो यह संभव ही नहीं है। दरअसल, रोहित जानते हैं कि दर्शकों का दिमाग कैसे काम करता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मुझे वास्तविकता दिखानी है।'

****